

CONTENTS

**Fifteenth Series, Vol.III, Second Session, 2009/1931 (Saka)
No.20, Wednesday, July 29, 2009/ Sravana 7, 1931 (Saka)**

<u>SUBJECT</u>	<u>PAGES</u>
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
* Starred Question Nos. 361 to 363	3-36
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 364 to 380	37-78
Unstarred Question Nos. 3384 to 3613	79-516

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	517-524
REPORT ON THE PARTICIPATION OF INDIAN PARLIAMENTARY DELEGATION IN THE 120TH ASSEMBLY OF THE INTER-PARLIAMENTARY UNION (IPU)	525
MATTERS UNDER RULE 377	526-542
(i) Need to expedite completion of the Koodankulam Nuclear Power Plant in Tamil Nadu	
Shri S.S. Ramasubbu	526-527
(ii) Need to provide special financial package for overall development of Hoshiarpur Parliamentary Constituency in Punjab	
Shrimati Santosh Chowdhary	528
(iii) Need to provide protection against the damage caused to crops by 'Neel Gai' in Faizabad, Barabanki and other adjoining districts in Uttar Pradesh	
Dr. Nirmal Khatri	529
(iv) Need to bring professional approach in the functioning of Doordarshan and All India Radio	
Shri K.P. Dhanapalan	530
(v) Need to overcome the shortage of power in the country	
Shri N.S.V Chitthan	531
(vi) Need to check the emission of Gases and pollution caused by chemical manufacturing units in Ujjain district of Madhya Pradesh posing grave threat to human life and environment	
Shri Premchand Guddu	532

- (vii) Need to shift the Divisional Office of Central Railway from Mumbai to Nagpur
- Shri Vilas Muttemwar 533
- (viii) Need to regularize and provide essential basic facilities in colonies of North East Delhi Parliamentary Constituency
- Shri Jai Prakash Agarwal 534
- (ix) Need to check the difference in prices of common generic medicines sold through different brand names by various drug manufacturing companies
- Shri Ganesh Singh 535
- (x) Need to accord special status to Rajasthan under Accelerated Irrigation Benefit Programme
- Shri Ram Singh Kaswan 536
- (xi) Need for four-laning of N.H.-92
- Shri Ashok Argal 537
- (xii) Need to shift Veerawada Railway Station to Gambhoi in Sabarkantha Parliamentary Constituency, Gujarat
- Shri Mahendrasinh P. Chauhan 537
- (xiii) Need to construct Railway Over Bridges in district Chandauli, Uttar Pradesh
- Shri Ramkishun 538
- (xiv) Need to provide special financial assistance to the farmers in drought-hit Balia and Deoria districts of Uttar Pradesh
- Shri Ramashankar Rajbhar 539

(xv)	Need to expedite the construction of railway bridge on river Kosi in district Supaul, Bihar	
	Shri Vishwa Mohan kumar	539
(xvi)	Need to set up a Bench of Supreme Court in Chennai, Tamil Nadu	
	Shri D. Venugopal	540
(xvii)	Need to expedite release of incentive fund under the Accelerated Power Development and Reforms Programme to Orissa	
	Shri B. Mahtab	541
(xviii)	Need to stop the construction of a dam across river Palar in Andhra Pradesh	
	Shri S. Semmalai	542
(xix)	Need to regularize the services of Extra-Departmental employees of Postal Department and extend the benefits of Sixth Central Pay Commission to them	
	Shri Inder Singh Namdhari	542
	RE: RISE IN PRICES OF ESSENTIAL COMMODITIES	543-546
	SUBMISSION BY MEMBER	
	Regarding commissioning of Gas Based Power Project at Dadri, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh	547-553
	DISCUSSION UNDER RULE 193	
	Issues arising out of Prime Minister's recent visit to foreign countries	554-609
	Shri Yashwant Sinha	554-568

Shri P.C. Chacko	569-576
Shri Mulayam Singh Yadav	577-582
Shri Sharad Yadav	583-590
Dr. Manmohan Singh	591-606
Shrimati Sushma Swaraj	605
Shri Basu Deb Acharia	607-609

ANNEXURE -I

Member-wise Index to Starred Questions	619
Member-wise Index to Unstarred Questions	620-623

ANNEXURE-II

Ministry-wise Index to Starred Questions	624
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	625-626

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Franciso Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Shri Beni Prasad Verma

Dr. Girija Vyas

SECRETARY GENERAL

Shri P.D.T. Achary

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, July 29, 2009/ Sravana 7, 1931 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, आप हमारी बात सुनने की कृपा करें। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह, आप कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : आज पूरे उत्तर भारत में बिजली का संकट है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न काल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : गाजियाबाद में वर्ष 2003 में 7,350 मेगावाट बिजली की योजना की स्थापना की गयी, उसका शिलान्यास किया, लेकिन वहां बिजली नहीं बन पा रही है। वहां केंद्र सरकार गैस क्यों नहीं दे रही है? पेट्रोलियम मंत्री गैस नहीं दे रहे हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न काल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : ...(व्यवधान) जब हाई कोर्ट से जीत गए ...(व्यवधान) यह दूसरा मामला है। ...(व्यवधान) भारत सरकार ने कोई पैरवी नहीं की। जब सुप्रीम कोर्ट मामला गया, ...(व्यवधान) ... सरकार अंडगा लगा रही है। दो मंत्रालयों के बीच के झगड़े से एनटीपीसी को तीस हजार करोड़ रूपए का घाटा होने जा रहा है ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी, कृपया प्रश्न काल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : यह बड़ा गंभीर सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर यह पैरवी कर रहे हैं। इस बात के लिए हम कहेंगे ...(व्यवधान) माननीय जोशी जी, यह गंभीर मामला है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइए।

श्री मुलायम सिंह यादव : बहुत घाटा हो रहा है। ...(व्यवधान) इससे पूरी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए बिजली की आपूर्ति हो जाती। आखिर गैस क्यों नहीं दी जा रही है? ...(व्यवधान) चाहे कोई उद्योगपति हो ...(व्यवधान) क्या उत्तर प्रदेश में अंधेरा बना रहे, उत्तर प्रदेश में कोई उद्योगपति आने न पाए? ...(व्यवधान) सरकार यहां बताए कि गैस क्यों नहीं दी जा रही है? इससे 7,350 मेगावाट बिजली पैदा होगी। पेट्रोलियम मिनिस्टर स्थिति स्पष्ट करें।...(व्यवधान)

(Q. No. 361)

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड : महोदया, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आज युद्धस्तर पर काम करने की आवश्यकता है। हमें अपने किसानों को जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचाना होगा अन्यथा हमारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी।

महोदया, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री महोदय से प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या आप प्रदूषण मानकों को और अधिक सख्त बनायेंगे और राष्ट्रीय कार्य योजना का ब्यौरा क्या है? ...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार: महोदया, यह बहुत गंभीर मामला है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया प्रश्न काल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, kindly give the reply.

SHRI JAIRAM RAMESH: Madam Speaker, last year in June of 2008, the Government of India announced a National Action Plan on Climate Change and the National Action Plan on Climate Change had different components. It had eight different missions and 24 critical initiatives for making India adapt to climate change. Five of these missions relate to adaptation to climate change and two of these missions relate to mitigating greenhouse gases, of which carbon dioxide is the most important. ... *(Interruptions)*

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न काल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

SHRI JAIRAM RAMESH: These missions are being implemented. The President's Address has said that these missions will be finalised and implementation thereof will start by the end of 2009. ... *(Interruptions)*

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड : अध्यक्ष महोदया, लॉ कमीशन ने वर्ष 2003, में अपनी 176वीं रिपोर्ट में पर्यावरण कोर्ट बनाने की सिफारिश की थी। मेरा मंत्री महोदय से प्रश्न है कि क्या सरकार ने पर्यावरण कोर्ट स्थापित करने का निर्णय ले लिया है? यदि हां, तो क्या ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन मानकों का उल्लंघन करने वालों को इस कोर्ट के दायरे में लाया जाएगा? ...(व्यवधान)

SHRI JAIRAM RAMESH: Madam Speaker, just last week the Union Cabinet approved the Bill to set up a National Green Tribunal to deal with cases relating to environment and forests. We are in the process of introducing this Bill in the Parliament in this Session itself. ... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : कृपया प्रश्न काल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

SHRI JAIRAM RAMESH: This National Green Tribunal is based on the recommendations of the Law Commission and it is through this National Green Tribunal that substantial cases of environment arising out of the implementation of various laws relating to environment and forests will be adjudicated. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Only what the Minister is saying will go on record.

(*Interruptions*) ... *

SHRI JAIRAM RAMESH: I urge the hon. Member to await introduction of this Bill. After this Bill is introduced, it will go to the concerned Standing Committee. We hope that by the Winter Session of this Parliament, the National Green Tribunal will come into being.

अध्यक्ष महोदया : अभी प्रश्न काल चलने दीजिए। हमने आपकी बात सुन ली है।

...(व्यवधान)

श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर : अध्यक्ष महोदया, मंत्री महोदय ने प्रश्न के 'ड' भाग का उत्तर नहीं दिया है। प्रश्न के 'ड' भाग में पूछा गया है कि सरकार द्वारा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के मानदंडों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? मुझे इसका उत्तर नहीं मिला है।

मेरा दूसरा प्रश्न है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप एक ही प्रश्न पूछिए।

श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर : महोदया, उसका पूरक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर : महोदया, अभी मैंने प्रश्न नहीं पूछा है, सिर्फ प्रश्न के उत्तर में जो कमी है, वह बताई है।...(व्यवधान)

क्लाइमेट चेंज अर्थात् जलवायु परिवर्तन दुनिया के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप बढ़ रहा है। इन सब आपदाओं का प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है। मीडिया रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हाल ही में इटली में सम्पन्न हुई जी-8 राष्ट्रों की बैठक में भारत ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए सहमति दी है। क्या यह सच है? मेरा प्रश्न है कि यदि भारत ने इस प्रकार की सहमति दी है तो हम किस सीमा तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाएंगे एवं इसका भारत की अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

SHRI JAIRAM RAMESH : Madam Speaker, in response to the first Question of the hon. Member, we do not have any laws, as of now, that control the emissions of Green House Gases (GHG) most notably Carbon-di-Oxide. There is no question of violation. As and when, this issue gets discussed over the next few years, we can consider imposing caps on the emissions. But, as of now, the policy of the Government of India is not to agree to any limits or any caps on the emissions of Carbon-di-Oxide, which accounts for about 65 per cent of the GHG emissions.

Now, as far as the second part of the Question is concerned, it is true that at the G-8 meeting held in L'Aquila in Italy, a statement was issued. This meeting was attended by our hon. Prime Minister. There was an aspirational goal, which is mentioned in this statement that all the countries -- that were represented at the forum -- aspire to limit the increase in the global temperature by 2°C by the year 2050. It is not a target, and it is not an operational objective. It is an aspirational goal. But you cannot take one sentence out of a three or four page document and say that India has compromised. India has not compromised because India's right to economic and social development is fully protected in this statement, and this goal of 2°C limit is only an aspirational goal, which all countries will try and will endeavour to meet.

Therefore, I want to assure the hon. Member that India has not capitulated; India has not compromised; and India has not weakened its position of climate change negotiation, which remains. We will not accept any caps legally binding emission reduction targets, now or later.

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदया, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे इस पर पूरे सदन को चर्चा करनी चाहिए। पूरे प्रश्न को देखकर लगता है कि एग्रीकल्चर में एमिशन को रोकने के लिए बात कही जा रही है। यह हमारे देश की कृषि के लिए बहुत घातक होगा अगर आप यह कहें कि धान से निकलने वाली मिथेन गैस और ग्रीन हाउस गैसों आदि को रोक दिया जाए यानी धान की खेती को रोक दिया जाए या यह कहा जाए कि जो ऐनीमल्स से मिथेन निकलती है, उसे रोक दिया जाए, इसलिए देश के कैटल स्टॉक को खत्म कर दिया जाए। आप हमें पहली बात यह बताएं कि एग्रीकल्चर के एमिशन के बारे में सरकार की क्या नीति है और वह नीति आप किस हद तक कारगर करवा रहे हैं? क्या एग्रीकल्चर के एमिशन को रोकने का सरकार का कोई इरादा है या इस एमिशन का देश सदुपयोग कर सके, उसके लिए कोई कार्यक्रम का इरादा है? क्या एग्रीकल्चर वेस्ट से पैदा होने वाली गैसेज़ को यूटीलाइज करने का कोई इरादा है? क्या आपकी ऐसी कोई स्कीम है?

दूसरा, क्या आप क्लाइमेट चेंज के संबंध में एक टाइम बाउंड प्रोग्राम कम्प्रीहेंसिव दृष्टि से सदन के सामने रखेंगे? ग्लेशियर्स का पिघलना, गैसेज़ का रुकना और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को इंटीग्रेटेड कम्प्रीहेंसिव प्लान के तहत आप कैसे करना चाहते हैं? क्या आप उसका खाका सदन के सामने बताएंगे? यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है।

SHRI JAIRAM RAMESH: Madam Speaker, the hon. Member has asked a series of questions. Let me try to answer each one of them. The first question that he has raised relates to whether India is going to accept any cap on the emission of methane from our agriculture. Let me reiterate clearly and categorically that India remains committed to the use of fertilizers. India remains committed to its agricultural strategy, and there is absolutely no question of imposing limits on the use of inputs which may lead to methane emissions. There is absolutely no question. I want to reassure the hon. Member that when we are talking of controlling emissions of Green House Gases, largely, we are thinking in the context of controlling or making

the carbon dioxide much lower, which is relatively easier, by using modern technology in our power stations.

As far as agriculture is concerned, I would like to inform the hon. Member, which he is well aware of, that in the National Action Plan on Climate Change, which most MPs would have seen, the hon. Member of Parliament would have certainly seen it, one of the eight Missions is the National Mission on Sustainable Agriculture. We need, not because the world is telling us to do so, to look at alternatives to chemical fertilizers. In the States of Punjab and Haryana, for example, the yield levels have reached a certain plateau because the incremental yield that we are getting from the use of fertilizers has levelled off. In a State like Andhra Pradesh, which accounts for 40 per cent of the pesticide consumption, the hon. Member is well aware of the social consequences of using such large quantities of pesticides. One of the Missions is a National Mission on Sustainable Agriculture which uses organic manure, which uses new methods as an alternative to the use of chemical fertilizers and chemical pesticides. I am glad to inform the hon. Member that the State of Andhra Pradesh, this year, almost 10 per cent of the total cultivated area in the State would come under non-pesticide use, would come under organic farming, which has major implications on cotton cultivation in the State.

So, we are moving towards sustainable agriculture, not because the world is telling us to reduce methane emissions, we are looking at sustainable agriculture because it is in our interest and it also increases the net returns that are available to farmers.

Finally, Madam Speaker, the hon. Member has raised the question of a comprehensive plan to deal with the effects of....

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, I think only one supplementary question should be answered. I find, increasingly, the Members are making so many parts in one question. It becomes very long.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : Madam, the question I have raised is related to this.

SHRI JAIRAM RAMESH: Madam, I am only a responsive Minister.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : I am only a responsible Member.

SHRI JAIRAM RAMESH: I have absolutely no hesitation in agreeing to a detailed discussion on this subject. I have absolutely no hesitation. Whenever you decide to have this discussion, I will be prepared.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : Will you give some incentives to organic farming?

श्री रेवती रमन सिंह : अध्यक्ष महोदया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इटली में 'गैस' पर भारत की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। लेकिन यदि हम उसका टैक्स देखें, तो भारत ने कहा है कि हम गैस कम करेंगे और कार्बन डाइआक्साइड कम करेंगे। आपने मेथेड बताया है कि इररिन्युअल एनर्जी हाइड्रो पावर ऑफ क्लीन कोल का इस्तेमाल उसमें होगा।

मान्यवर, क्लीन कोल के लिए आपने क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बनायी है, जिससे उसमें कार्बन डाइआक्साइड का कम से कम इमिशन हो? अभी जो एग्जीस्टिंग पावर हाउसेज हैं और जो नये खुल रहे हैं, उसमें क्या इसका इस्तेमाल होगा? क्या आपने इसे मेनडेटरी किया है और यदि नहीं किया है, तो आप इसे कब तक करेंगे?

श्री जयराम रमेश: यह कहना बिल्कुल गलत है कि जी-8 स्टेटमेंट में हमने ऐसा कोई आश्वासन दिया है कि हम कार्बन डाई आक्साइड एमिशन को घटाएंगे। इसका बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया है। मैं यह स्टेटमेंट, अगर माननीय सदस्य चाहें, उनको दे सकता हूँ, वे खुद देख सकते हैं कि वहां हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कोई आश्वासन हिन्दुस्तान की ओर से नहीं दिया है कि हम कार्बन डाई आक्साइड या ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कटौत करेंगे। उस मीटिंग में जो लोग शामिल हुए थे, जी-8 और चार अन्य देशों के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री, का बयान यही कहता है कि वर्ष 2050 तक हमारा यह प्रयास होगा कि जो अधिक टैपेचर होगा, वह दो डिग्री सेल्सियस तक सीमित रहे। यह एक एस्पिरेशनल उद्देश्य है, कोई टारगेट नहीं है, यह कोई सीमा नहीं है, कोई जिम्मेदारी हमने नहीं ली है। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जी-8 स्टेटमेंट में मंजूरी दी है, वह एक सामूहिक, ग्लोबल स्टेटमेंट है और उसमें हिन्दुस्तान की जिम्मेदारियों का कोई जिक्र नहीं है। हमारी जिम्मेदारी हमारी राष्ट्रीय कार्ययोजना के तहत होगी जिसकी घोषणा पिछले साल की गयी थी। उस कार्ययोजना के तहत जैसा कि मैंने पहले कहा है, आठ मिशन का जिक्र हुआ है और 24 ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, जिनमें जैसा माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा, क्लीन कोल एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे कोयला मंत्री जी यहां बैठे हैं, पावर सेक्टर में हम यह कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पावर स्टेशन की

एफिशिएंसी और बढ़ाई जाए। अगर एफिशिएंसी बढ़ेगी तो हमारी कार्बन डाई आक्साइड की एमिशन घटेगी। हिन्दुस्तान का पहला सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट अगले साल गुजरात के मुंदरा में कमीशन होगा और आने वाले सालों में आप देखेंगे कि एनटीपीसी और प्राइवेट कंपनियों द्वारा जो बिजली घर लगाए जाएंगे, उनमें ज्यादातर सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, जिससे उनमें कार्बन डाई आक्साइड एमिशन घटेगा। माननीय सदस्य ने कोल गैसीफिकेशन की बात की, हिन्दुस्तान का पहला कोल गैसीफिकेशन पर आधारित बिजली घर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आ रहा है। अगले तीन साल में उसकी कमीशनिंग की गुंजाइश है और जब ऐसा होगा तो हिन्दुस्तान दुनिया के ऐसे तीन या चार देशों में शामिल होगा जहां पर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है।

(Q. No.362)

श्री अनंत कुमार हेगड़े : महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक देश एक्सपोर्ट ज्यादा करना चाहता है और इम्पोर्ट कम करना चाहता है, लेकिन अपने देश में आंकड़े थोड़े अजीब से दिखते हैं। इम्पोर्ट बढ़ता जा रहा है और एक्सपोर्ट की बात छोड़ दीजिए, डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बराबर नहीं है। वर्ष 2004-05 में इम्पोर्ट 38 प्रतिशत था, टोटल प्रोडक्शन के आधार पर, वह लगातार वर्ष 2005-06 में बढ़कर 38.57 प्रतिशत हो गया, वर्ष 2006-07 में 45 प्रतिशत हो गया, वर्ष 2007-08 में 49 प्रतिशत हो गया और वर्ष 2008-09 में शायद इसके 50 प्रतिशत पार करने की संभावना है। यह अजीब स्थिति है।

इसके साथ-साथ अण्डग्राउण्ड माइनिंग के बारे में मैंने जो प्रश्न पूछा था, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, लेकिन 27 जुलाई, 2009 को इसी सदन में उत्तर देते समय मंत्री महोदय ने बताया है कि वर्ष 2008-09 में 492.94 मिलियन टन प्रोडक्शन था, लेकिन वर्ष 2009-10 के लिए हमने 435 मिलियन टन का टारगेट रखा है। हम एक ओर कहते हैं कि प्रोडक्शन ज्यादा करने की हमारी सोच है, लेकिन आपके ही आंकड़े कहते हैं कि जो टारगेट हमने वर्ष 2008-09 में एचीव किया था, वह टारगेट भी हम वर्ष 2009-10 के लिए नहीं रख रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछें।

श्री अनंत कुमार हेगड़े : प्रश्न ही पूछ रहा हूँ। प्रोडक्टिविटी, तंत्र ज्ञान और ओवरहैड्स के बारे में कहना चाहता हूँ कि दुनिया भर में जो प्रोडक्टिविटी है, हमारे देश में बहुत कम प्रोडक्टिविटी है। ओवरहैड्स भी जो मुख्य निर्यातक देश हैं, उनके मुकाबले 35 प्रतिशत ज्यादा है। मैं तंत्र ज्ञान और माइनिंग का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो श्री डी इलेक्ट्रिक है और बाकी जी तंत्र ज्ञान है, खासकर अभी पर्यावरण के बारे में, ग्रीन हाउस के बारे में सवाल के जवाब दिए जा रहे थे, उसे अपनाकर और हाई पावर सोलर लेज़र एनर्जी का यूज करके पाल्युशन फ्री माइनिंग की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदया: आपके प्रश्न की भूमिका बहुत लम्बी हो गई है। अब आप प्रश्न पूछें।

श्री अनंत कुमार हेगड़े : इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए अंडरग्राउंड माइनिंग में क्या टारगेट होगा, कैसे हम उसे एचीव कर पाएंगे? ये जो आंकड़े हैं, इनमें आपस में तालमेल नहीं दिखाई दे रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अंडरग्राउंड माइनिंग में इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए उत्पादन में क्या बढ़ोत्तरी होगी और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: आदरणीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है कि दूसरे देशों में आयात की मात्रा घटती जा रही है और हमारे देश में बढ़ रही है। सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूंगा कि

आज से 30-40 साल पहले जब कोल इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उस समय हमारे देश में उद्योग की स्थिति क्या थी और आज क्या है। आज के समय में जितनी तेजी से उद्योग बढ़े हैं, उतनी ही तेजी से कोयले की मांग भी बढ़ी है। हमारे मुल्क में 55 प्रतिशत कोयले के द्वारा बिजली का उत्पादन होता है। इससे उद्योगों को बिजली की आपूर्ति की जाती है। ऐसी सूरत में यह कहना कि दूसरे देशों में आयात की मात्रा घट रही है, हमारे देश में बढ़ रही है, उचित नहीं है। लेकिन बढ़ती हुई ऊर्जा की आवश्यकताओं को देखते हुए और बढ़ते हुए उद्योगों को देखते हुए भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि अगर कोई विदेश से कोयला मंगाना चाहता है तो हम उसे अलाऊ करें। हालांकि वह हमारे देश के कोयले से दोगुनी कीमत पर मिलता है, लेकिन उन्हें अगर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति दोगुनी कीमत पर करके उद्योग चलाने हैं, तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। जहां तक कोयले के उत्पादन की बात है, वह आठवीं योजना में 289.32 मिलियन टन था, नौवीं योजना में 327.79 मिलियन टन था, दसवीं योजना में 433.83 मिलियन टन हो गया। इसलिए यह कहना कि कोयले का उत्पादन बढ़ नहीं रहा है, यह उचित नहीं है। यह हो सकता है कि हम आवश्यकताओं के अनुरूप कोयले का उत्पादन उतनी तेजी से नहीं बढ़ा पा रहे, जितनी तेजी से बढ़ाना चाहिए।

श्री अनंत कुमार हेगड़े : ये सरकार के ही आंकड़े हैं, मेरे नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया मंत्री जी को जवाब देने दें।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: जहां तक अंडरग्राउंड माइनिंग की बात है, जिस समय कोयले का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उस समय अंडरग्राउंड माइनिंग ज्यादा हो रही थी। वह धीरे-धीरे कम हुई है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि ओपन-कास्ट माइनिंग में कोयले का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ाया जा सकता है, जितनी तेजी से हमारे देश में मांग बढ़ रही थी। इसमें देखा गया है कि अगर हम ओपन-कास्ट माइनिंग तेजी से करेंगे तो हम सुविधाजनक तरीके से अपने देश में कोयले का उत्पादन करके उसकी आसानी से आपूर्ति कर पाएंगे। इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। अब सरकार यह सोच रही है कि हम अंडरग्राउंड माइनिंग को भी तेजी से बढ़ाएं। उसके लिए एक सर्वेक्षण कराया है। उसकी रिपोर्ट के अनुकूल हम अंडरग्राउंड माइनिंग को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए बजट भी एलोकेट किया गया है। अंडरग्राउंड माइनिंग में सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि इसे शुरू करने में ही चार-पांच साल लग जाते हैं, जबकि ओपन-कास्ट माइनिंग छः महीने में ही शुरू हो जाती है और यह ज्यादा सुविधाजनक भी है तथा उत्पादक भी है। इसके अलावा यह सस्ती भी पड़ती है। इसलिए ओपन-कास्ट माइनिंग पर अभी तक ज्यादा ध्यान दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि रिसोर्स कम हो रहे हैं इसलिए अंडरग्राउंड माइनिंग को बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए जो भी

व्यवस्था करनी होगी, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले तीन-चार साल में वह कर देंगे। इससे हमारे देश में अंडरग्राउंड माइनिंग से भी काफी उत्पादन हो जाएगा।

श्री अनंत कुमार हेगड़े : अध्यक्ष महोदया, मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जब यूएस डिप्लोमेट हिलेरी क्लिंटन यहां आई थी तो “ज़ॉप डिपेंडेंसी ऑन कोल” की बात कही गयी। इसका प्रोडक्शन पर क्या असर होगा? अगर असर होगा तो कितनी मात्रा में होगा और नहीं होगा तो क्या आप हिलेरी क्लिंटन की प्रस्तावना को अस्वीकार करते हैं? अगर अस्वीकार करते हैं तो इसका नतीजा क्या होगा? यह जानकारी मुझे चाहिए।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: मैडम स्पीकर, कोयले के उत्पादन से, कोयले द्वारा थर्मल पावर स्टेशन चलाने से पर्यावरण का नुकसान होता है, पर्यावरण का क्षरण होता है, इसमें कोई शक नहीं है। इस मामले में, दुनिया के तमाम पर्यावरणविदों ने चिंता व्यक्त की है, हम भी चिंतित हैं, लेकिन हम अपने प्रोडक्शन को घटा नहीं सकते हैं, हम अपने इंडस्ट्रलाइजेशन को कम नहीं कर सकते हैं। दुनिया के दूसरे देश इसके लिए चिंता कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत नहीं मिल जाते हैं, तब तक हम कोयले के उत्पादन को कम नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम उसे बढ़ाते जाएंगे। जैसा अभी माननीय पर्यावरण मंत्री जी ने आपको और सदन को आश्वस्त किया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया के विकसित देश कितने चिंतित हो रहे हैं। हमारे अपने रिसोर्सज हैं, हमारी अपनी आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए हम हर कीमत पर कोशिश करेंगे। इसका असर अगर दुनिया के पर्यावरण पर विपरीत होता है तो दुनिया के देश हमें बताएं कि हमारे पास वैकल्पिक स्रोत क्या हैं? जब तक वैकल्पिक स्रोत हम विकसित नहीं कर लेंगे, तब तक हम अपने इस स्रोत को यूं ही जारी रखेंगे, जिससे कि हमारे देश का उत्पादन कम न होने पाए।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : धन्यवाद महोदया, अभी पहले प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने विस्तार से यह बताने का प्रयास किया कि पिछले तीस-चालीस वर्षों में, औद्योगीकरण होने के कारण, जो कोयले की मांग बढ़ी है, उसके कारण इन्हें आयात करना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता है कि इस तर्क में कोई दम है। हमारे पास कोयले का पर्याप्त भंडार है और अगर हमारी मांग 30 वर्षों में बढ़ती रही तो उसके अनुरूप हमें उत्पादन भी बढ़ाना चाहिए था, लेकिन हमने उसे बढ़ाया नहीं। माननीय मंत्री जी का एक बयान हमने अखबार में देखा, जिसमें जो आयातित कोयला है, उसे सर्टिफिकेट भी दे दिया गया। इन्होंने कहा कि जो आयातित कोयला है, उसकी गुणवत्ता अच्छी है। मैडम स्पीकर, कोयले की गुणवत्ता का अच्छा होना उसको अच्छी तरह वाश करने पर निर्भर करता है। वाशरी का इस्तेमाल आप जितना करेंगे, उतना ही कोयले की गुणवत्ता में सुधार होगा। आप अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए, आयातित कोयले को प्रमाण-पत्र दे रहे हैं। हम नहीं समझते हैं कि यह उचित है। माननीय मंत्री जी, हमारे पास कोयले का पर्याप्त भंडार है और जितनी

मांग हमारे देश में है, उतनी पूर्ति हम कोयले की कर सकते हैं, अगर हम उत्पादन को बढ़ाएं। माननीय मंत्री जी इस सच्चाई को जानते होंगे कि कोयला सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कई लोग, कई तरह की एजेन्सियां लगी हुई हैं, माफिया लोग कोयले से हीरा निकालने का काम कर रहे हैं और कोयले की बड़ी मात्रा में चोरी हो रही है। आप उस चोरी पर नियंत्रण करें तो बहुत हद तक यह समस्या दूर हो सकती है। लेकिन माननीय मंत्री जी ही यह बता सकेंगे कि वे उस पर कितना नियंत्रण कर पाएंगे? हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि जो भूमिगत कोयला खदान हैं, क्या सरकार ने कोई आकलन किया है कि उन खदानों में कोयले की कितनी मात्रा उपलब्ध है और मांग और आपूर्ति में जो गैप है उसे पूरा करने के लिए, आप उत्पादन का क्या लक्ष्य रख रहे हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : महोदया, माननीय सदस्य ने यह कहा है कि इम्पोर्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कोयले का पूरा उत्पादन नहीं कर पाते हैं। आंशिक रूप से माननीय सदस्य की बात सही है कि हम उतना उत्पादन नहीं कर पाते हैं, जितनी हमारे देश में डिमांड है। यह बात भी सत्य है कि हमारे देश में ए, बी, सी ग्रेड के कोयले का रिजर्व बहुत कम है। ज्यादातर डी, ई, एफ, जी ग्रेड के कोयले का ही उत्पादन होता है, जो कि थर्मल पावर स्टेशंस में काम आता है और जो स्पंज आयरन वाली इंडस्ट्रीज़ हैं या सीमेंट प्लांट्स हैं, उन्हें अच्छे कोयले की आवश्यकता होती है। हमारे देश में कोकिंग कोल का उत्पादन कुल रिजर्व केवल 9 परसेंट है, बाकि सब ओर्डनरी कोल है, इसमें ऐश कन्टेंट ज्यादा होता है। विदेशों से जो कोयला इम्पोर्ट किया जाता है, उसमें ऐश कन्टेंट कम होता है। उसकी उत्पादकता ज्यादा होती है, उसकी हीट पावर ज्यादा होती है। इसलिए जो लोग इंडस्ट्रीज़ को चलाना चाहते हैं, हमने उन्हें लिबर्टी दी है कि यदि वह चाहें तो विदेशों से कोयला मंगवा सकते हैं। जहां तक उत्पादन बढ़ाने की बात है, मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूँ कि कोयले का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। इसका हमारी मिनिस्ट्री ने एक्शन प्लान बनाया है। आने वाले समय में हमारे देश का कोयला उत्पादन भी बढ़ेगा। जहां तक कोयला चोरी की बात है, माननीय सदस्य बिहार से आते हैं और वह अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरीके से माफियाओं ने कोल सैक्टर पर कब्जा किया हुआ है। इस बात को पूरी तरह से स्वीकार कीजिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी को बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: अब नहीं है, लेकिन जिस समय की आप बात कर रहे हैं, आपको हम से ज्यादा जानकारी बिहार और झारखण्ड के बारे में होगी क्योंकि झारखण्ड 4-6 साल पहले तक आपके साथ

था।... (व्यवधान) माफियाओं ने जिस तरीके से कोल सैक्टर पर कब्जा किया हुआ है और कोल सैक्टर में जो करप्शन है, कोयले की चोरी होती है, इसे घटाने की और इस पर अंकुश लगाने की कोशिश हमारी सरकार खास तौर से नयी सरकार इस को पूरे तरीके से सैंट्रलाइज़ कर रही है। आपने देखा होगा कि पिछले महीने सीबीआई की दो रेड पड़ी हैं। एक डब्ल्यूसीसीएल और दूसरी सिंगरौली में पड़ी है। इसलिए हमारा प्रयास होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा कोयले की चोरी को रोक सकें और देश में कोयले के उत्पादन को बढ़ाकर अपनी औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।

श्री मदन लाल शर्मा: अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद करते हुए कहना चाहता हूँ कि इस देश में बहुत सी रियासतें हैं, लेकिन हमारी रियासत जम्मू-कश्मीर, खास तौर से मेरे क्षेत्र जम्मू-पुंछ में कालाकोट कोयले की खान है, लेकिन अरसादराज़ से मैं यह देख रहा हूँ कि वहां तसल्ली बख़्श काम नहीं हो रहा है और जरूरत के मुताबिक वहां से कोयला नहीं मिल रहा है। मेरी जानकारी के मुताबिक वहां महीने में 15 सौ टन कोयला निकलता है और एक हजार के करीब मजदूर काम करते हैं। वर्ष 1965 में कालाकोट पावर थर्मल प्लांट लगा था, लेकिन वर्ष 1980, पिछले बीस वर्षों से वह बंद पड़ा है। क्योंकि उस खान से जरूरत के मुताबिक कोयला नहीं निकाला जाता है। मैं समझता हूँ कि पैसा लगाकर जो पावर थर्मल प्लांट लगाया गया था, वह भी बंद है। रियासत जम्मू-कश्मीर बैकवर्ड स्टेट है। वहां बेरोजगारी बहुत है। मुझे मिनिस्टर साहब से पहले मिलने का मौका मिला, अधिकारी यहां तशरीफ़ रखते हैं। शायद इस विभाग को यह जानकारी भी नहीं थी कि हमारी रियासत और कालाकोट में कोई खान है।

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछिए।

श्री मदन लाल शर्मा : मैं मंत्री जी से यकीन चाहता हूँ कि वे फुर्सत निकाल कर कालाकोट का दौरा करें, वहां मौके का जायजा लें। जो-जो परेशानियां और दिक्कतें हैं, उन्हें दूर करने का क्या मंत्री जी यकीन दिलाते हैं?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : महोदया, माननीय सदस्य ने जम्मू की जिस कोयला खान के बारे में जिक्र किया है, इसका कोल इंडिया से कोई लेना-देना नहीं है। वह जो कोयला प्रोड्यूस करती है, उसका लोकल यूज़ होता है। उसमें ऐश कन्टेंट इतना ज्यादा है कि वह थर्मल पावर स्टेशन में काम नहीं आ सकता है। इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 17 हजार टन है, जो कि वहीं के लोकल कंजम्प्शन के काम आ जाता है। अगर इससे पावर प्लांट चलाने की कोई बात की जाए, तो इस बात की फिजीबिलिटी देखी गई थी कि क्या इससे पावर प्लांट चल सकता है। लेकिन यह पाया गया कि इससे पावर प्लांट नहीं चलाया जा सकता है।

SHRI KALYAN BANERJEE : Madam, Speaker, through you I would like to put a supplementary question to the hon. Minister. Rampant unauthorized coal mining is going on in Raniganj and in its adjoining areas, namely, at places like Andal, Jamuria under the Asansol Sub-Division in the State of West Bengal for decades together. Selling of such illegally mined coal is going on in open daylight and it is known to everyone. In the rarest of the rare cases, the local police have taken steps to prevent such unauthorized mining of coal in the area. I would like to know from the hon. Minister if the Government is really serious about preventing unauthorized coal mining in the State of West Bengal, particularly in the Asansol Sub-Division which comes under the direct control of the Eastern Coalfields Limited. It is also reported that the officers of Eastern Coalfields also are involved in such unauthorized coal mining activity.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने आसनसोल के जिन कोल माइन्स का जिक्र किया है, मैंने पहले ही बताया कि इललीगल कोल माइनिंग माफियाओं के सहयोग से क्षेत्रीय लोगों का एक पेशा बन गया है। माफिया उनको उकसाते हैं कि आप लोग इललीगल माइनिंग करिए और इललीगल माइनिंग करके हमें कोयला दीजिए। वे उनसे औने-पौने दाम पर कोल खरीद लेते हैं और बाद में बाजार में दुगने-तिगुने दामों पर बेचते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक बहुत बड़ी समस्या है। मैंने जब से चार्ज सम्भाला है, मैं पश्चिम बंगाल गया, पश्चिम बंगाल में मैं मुख्य मंत्री जी से मिला और उनसे अनुरोध किया कि आपकी नाक के नीचे इललीगल माइनिंग हो रही है जो हमारे लिए शर्म की बात है और आपके लिए भी चिंता की बात होनी चाहिए क्योंकि इललीगल माइनिंग तब तक नहीं रोकी जा सकती जब तक कि राज्य सरकारों का सहयोग न प्राप्त हो। आप अच्छी तरह जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस ये स्टेट सबजेक्ट्स हैं। अगर राज्य सरकार हमें पूरी तरह से सहयोग करे तो हम इललीगल माइनिंग को भी रोक सकते हैं और पिलफ्रेज को भी रोक सकते हैं। जिस समस्या की ओर हमारे माननीय सदस्य ने ध्यान दिया है, हमारा प्रयास है और हमें पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री जी ने यह एश्योर किया कि अगर आप वास्तव में इतने गंभीर हैं तो हम इललीगल माइनिंग रोकने के लिए वे सारे कड़े कदम उठाएंगे जितने कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में शायद इललीगल माइनिंग पर अंकुश लगेगा।

श्री उदय सिंह : झारखंड में राष्ट्रपति शासन है, क्या वहां इन्होंने रोक दिया?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : क्या आप उत्तर देना चाहते हैं?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्ष महोदया, मैं उत्तर देना चाहता हूँ। पिलफ्रेज और इललीगल माइनिंग, जिन स्टेट में कोयला पैदा होता है, वहां बराबर हो रही है चाहे वह झारखंड हो या पश्चिम बंगाल हो या छत्तीसगढ़ हो। कम से कम इस मामले में हमारे माननीय सदस्य अगर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो हम समझते हैं कि बहुत कुछ इसे रोकने में कामयाबी मिल सकती है और झारखंड में भी जब मैं गया था तो झारखंड के गवर्नर से मिला था।

SHRI BANSA GOPAL CHOWDHURY : The hon. Member took the name of West Bengal and not Jharkhand... *(Interruptions)*

MADAM SPEAKER: Mr. Minister, you do not have to respond to everything.

... *(Interruptions)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : वह धनबाद के हैं। उन्होंने धनबाद की बात कही। आप झारखंड के हैं। लेकिन इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हम सब मिलकर अगर इस गंभीर समस्या का निदान खोजेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि दुनिया में किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हाल ही में आप इस विभाग के मंत्री बने हैं, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि देश भर में सबसे बड़ा स्टॉक और बैस्ट क्वालिटी का कोल धनबाद के झरिया में पाया जाता है? वहां वर्षों से पूरे इलाके के अंदर आग लगी हुई है। वहां आग का धुंआ, आग की लौ निकलती रहती है। फिर उसके गड्ढों को भरने के लिए कितना पैसा बालू पर खर्च किया जाता है और कोल का बहुत बड़ा स्टॉक है। हम इन चीजों पर ध्यान न देकर इम्पोर्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं जिसमें देश का पैसा बाहर जा रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या यह प्रकाश में लाया गया है? यहां मिथेन गैस अंदर भरी हुई है।

हम इससे और पावर पैदा कर सकते थे और आग को बुझा सकते थे।

श्री अनंत कुमार : वे वॉल्केनो के ऊपर बैठे हैं।

श्री लालू प्रसाद : हां, ज्वालामुखी के ऊपर बैठे हैं। इसके कारण धनबाद और झरिया का इलाका खतरे में है क्योंकि यह वॉल्केनो के ऊपर बसा हुआ है। सरकार और आपके महकमे ने आग को बुझाने के लिए क्या उपाय किए हैं? हम लोगों ने कई बार इस सवाल को उठाया है कि मिथेन गैस के कारण कोयले का स्टॉक समाप्त हो रहा है जिससे हम दूसरों पर डिपेंडेंट हो रहे हैं।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय वरिष्ठ सांसद ने बात उठाई है और कहा है कि अब तो आपको प्रभार मिल गया है। मेरा कहना है कि आभार भी आपका है, आपके आभार से हमें प्रभार मिला

है, मैं आपका आभारी हूँ। माननीय सदस्य ने झरिया की जिस कोल फील्ड की बात उठाई है, इसमें शक नहीं है कि पिछले 40 वर्षों से इस कोल फील्ड में आग लगी हुई है। जब भी प्रयास किया गया कि वहां की बस्ती का रिहेबिलिटेशन कर दिया जाए, तब किसी न किसी कारण से विस्थापन का कार्य पूरा नहीं हो पाया, मैं किसी सरकार या किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहता हूँ। अभी बिहार में झरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है। इस अथॉरिटी को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वहां की बस्तियों को पुनर्वासित करे। बीसीसीएल के पास लगभग 4000 क्वार्टर्स हैं और वह इसे देने को तैयार है। बीसीसीएल ने पुनर्वास योजना बनाई है और वह इसके लिए सारा पैसा देने को तैयार है। हम उम्मीद करते हैं कि झरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी इस काम को जल्दी से जल्दी लोकल प्रशासन के सहयोग से अंजाम देगी। बीसीसीएल को सारा खर्चा करना है। झारखंड और पश्चिम बंगाल सरकार को फोर्स, ताकत, अधिकारी और समर्पण की भावना दिखानी होगी जिससे पुनर्स्थापन का कार्य जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। सौ दिन का एक्शन प्लान बनाया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि शायद तीन या चार महीने में ही विस्थापन का कार्य हो जाएगा। जब तक विस्थापन का कार्य पूरा नहीं होता तब तक हम वहां न तो माइनिंग कर सकते हैं और न आग बुझा सकते हैं।

(Q.No.363)

श्री महाबल मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या वैक्सीन बनाने के तीन यूनिट बंद हुए हैं? इसका क्या कारण है? क्या भविष्य में कोई यूनिट चालू कर रहे हैं?

SHRI DINESH TRIVEDI: Madam, it is a long answer which I have to give as I have go to the background of the closing of this vaccine unit. As a matter of fact, it would not be proper if I say that the units are closed. Actually the units are not closed. It is the licence which has been revoked and it is under the Department of the Ministry concerned and not independent PSUs. They are three of them. One is CRI, Kasauli in Himachal Pradesh, the second is the BCG Vaccine Laboratory in Tamil Nadu and the third one is PII in Kannur. These units have been giving us vaccines for the UIP Programme which the Ministry has, that is, the Universal Immunisation Programme.

The Drugs and Cosmetics Act, 1940 and Drugs and Cosmetics Rules, 1945 are the concerned Rules and Act which regulate import, manufacturing, selling, distribution of both drugs and cosmetics.

Madam Speaker, in 2001, Schedule A of this rule was amended. As per that amendment, something which is known as Good Manufacturing Practices, in short it is known as the GMP, was introduced. After the GMP was introduced, all the manufacturing units had to be given time to update all their units in order to adhere to the GMP. Most of the units had gone through inspections. So were our Units, all these three Units, in various things. Since August 2004 a lot of inspection and other things had started. There were three inspections. One was in 2004 and the other was in August 2007. Various teams, like WHO team, our own experts, and others went there to see whether our Units adhere to the GMP or not. Under the GMP, comes the infrastructure like buildings, the manufacturing process, whether the Units have enough expertise, staff or not, etc. All these consist of the GMP. Unfortunately our Units, for various reasons, could not adhere to the GMP.

I have the details. If you want I can go through the details. Madam Speaker, if you permit me then I can go through the details as to why we were de-recognised. ... *(Interruptions)* Hon. Members want the reply in short. I do not know what is short or long, but I have to give the factual reply.

Then, after inspection it was found that in some of the Units the buildings were not properly built; in other Units the man power was not what it was prescribed. With the result, our authority, the National Regulation Authority said that we cannot compromise on the quality of vaccines. We do not compromise on the quality and safety of the drugs, because these are the Units which manufacture vaccines and ultimately they go to the children. With the result, the Authority was very strict and it said, "It does not matter, even if they are our own Units, we would rather close them, rather than taking a chance with children's vaccines." That is the reason why our own Regulatory Authority revoked the licence. So, it is not really closed. The licence has been revoked. That is the reason at the moment why they are not producing anything. But at the same time, I will hasten to add this. ... *(Interruptions)*

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, I would request you to be concise.

... *(Interruptions)*

SHRI DINESH TRIVEDI: Madam Speaker, I will conclude.

The hon. President in her Address to the Parliament on 4th of June had also mentioned that all these Units are going to be opened by the Government. So, we stand by that and these Units are ultimately going to be opened and various project reports are there.. ... *(Interruptions)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

... *(व्यवधान)*

MADAM SPEAKER: Please address the Chair. Please sit down.

... *(Interruptions)*

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछिये।

... *(Interruptions)*

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, you do not have to reply unless I call you.

... (*Interruptions*)

श्री महाबल मिश्रा : अध्यक्ष महोदया, देश में आज तरह-तरह की बीमारियां आ रही हैं, जिनके बारे में जानकारी नहीं है। क्या सरकार भविष्य में ऐसा कोई वैक्सीन बनाने जा रही है, क्या सरकार की ऐसी कोई सोच है और देश में कितने वैक्सीन्स हैं और उनका नाम क्या है?

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, please be brief in answering the question.

SHRI DINESH TRIVEDI: Madam, again, if I have to give the history of all the vaccines, it is going to take time. ... (*Interruptions*) He is asking about the different diseases.... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, I am sure the hon. Member knows the history. You please be succinct and to the point in your answer.

SHRI DINESH TRIVEDI: He has asked about the diseases. We have this BCG.... (*Interruptions*)

श्री महाबल मिश्रा : बहुत छोटा सा क्वेश्चन है।

श्री दिनेश त्रिवेदी : आपने छोटे से क्वेश्चन में पूरी रामायण मांगी है। We have the BCG.... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, please have some patience. Please give a patient hearing and give him a chance. Hon. Minister, please continue.

SHRI DINESH TRIVEDI: We have this BCG which is basically for Tuberculosis, as we all know. We have Diptheria. We have the Pertussis which is whooping cough which we have in children. Then, we have Tetanus Toxoid which is TT – not Table Tennis. TT is Tetanus Toxoid. Then, we have the polio vaccine. We have Measles. All the immunization programmes have actually been started from 1900 where Small Pox and Typhoid, if you remember, were the diseases of that time. Then, again, in 1962, we started the BCG Programme.

As far as the new vaccines are concerned, Madam, it is a continuous process. At the moment, the Ministry is seized of the Swine Flu. The Swine Flu vaccine has not yet come. We are all researching Swine Flu. At the moment, the Pentavalent is

one vaccine which is under active consideration and a lot of decisions have been taken. In future, we are going to come with this Pentavalent vaccine which will be implemented so that the administration of it becomes much easier and more and more diseases are covered under this.

SHRI ANANTH KUMAR : Madam, there is a huge scarcity of vaccines in the country. Vaccines are directly related to infant mortality. In India, every year, there are 26 million child births taking place out of which 2.7 million die because of infant mortality. They die before their first birth day. That is the situation. Unfortunately, on 17th January, 2008, the then Minister for Health closed down procuring the life-saving vaccines from the three Public Sector Undertakings. They used to supply 80 per cent of the procurement. There is a PIL pending before the hon. Supreme Court alleging a huge vaccines scam. Instead of these three Public Sector Undertakings, actually now, the vaccines are being procured from the Green Signal Bio-Pharma and Watson Bio-Pharma. Therefore, my straight question to the hon. Health Minister is this. If there is a scam, what is the probe that the UPA Government is instituting to unravel the scam?

Secondly, what are the corrective measures they are going to take....

(Interruptions)

MADAM SPEAKER: Please put only one question.

SHRI ANANTH KUMAR : I am putting only one question. Part (b) of the question is this.


MADAM SPEAKER: Just ask one question.

SHRI ANANTH KUMAR : They have to restore the supply of vaccines. Actually, the hon. Minister himself has agreed that in 14 States, the life-saving vaccines are in deficit. They have given various statistics to the extent of 35-36 million vaccines in deficit in Uttar Pradesh, Bihar, Orissa, Karnataka and in various other States. That has been their answer. What is their Action Plan to restore the supply of vaccines where infant mortality is so high?

SHRI DINESH TRIVEDI: If one looks at the answer, it says very clearly that there is no shortage of vaccines. So, factually, I am afraid, in-between, for a few months, the supply was not really out of stock.

But the supply was less and that is why I gave a very long reply so that I thought that all the supplementaries could be covered. That was the purpose. As you know, vaccines are supplied by both the public sector and the private sector. ...

(Interruptions)

SHRI ANANTH KUMAR : Madam, there is huge deficiency of vaccines in the country even now. ... *(Interruptions)* 

MADAM SPEAKER: Please let him answer.

... *(Interruptions)*

MADAM SPEAKER: You have already asked the question. Let him reply now.

SHRI DINESH TRIVEDI: Madam, normally stocks for a couple of months are kept and if the stocks go below one month's supply, then only we technically say that we are out of supply. The fact of life is whether it is the public sector undertaking, whether it is the unit of the Ministry or whether it is the private sector ...

(Interruptions)

SHRI ANANTH KUMAR : Madam, he said in his reply that public and private manufacturers default on their supply by staggering their delivery in some States. This is the answer given. ... *(Interruptions)*

SHRI DINESH TRIVEDI: This is what I am telling. ... *(Interruptions)*

MADAM SPEAKER: Please let him reply.

... *(Interruptions)*

MADAM SPEAKER: If you have the patience, just hear me out. All these manufacturing units, whether they are in the public sector or they are in the private sector, overstate their capacity and we also have to appreciate that there is a lead time required for three months from the time we place the order and 21 days are added

... *(Interruptions)*

SHRI ANANTH KUMAR: Madam, my question was straight. What about the vaccine scam? What about the purchase from private companies? He is not answering to my straight question. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please let him reply.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: This dialogue cannot go on. Please let him reply.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Mr. Minister, I think you have given a very detailed reply. Do you want to add something now?

SHRI DINESH TRIVEDI: Madam, I have to answer in sequence. I have got to answer in sequence. ... (*Interruptions*) Let me answer in sequence. ... (*Interruptions*)

SHRI ANANTH KUMAR : Madam, it is a straight question. The Minister is not answering to my question. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Only the Minister's statement will go on record.

(*Interruptions*) ... *

SHRI DINESH TRIVEDI: Madam, in the other House ... (*Interruptions*) Let me answer. ... (*Interruptions*) If you sit down, I will answer. I have the answer for your question. ... (*Interruptions*) If you sit down, I will answer. Your time is going up. ... (*Interruptions*) Let me answer your question. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Would you let him answer?

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please let him answer.

... (*Interruptions*)

SHRI DINESH TRIVEDI: If you sit down, I will answer. ... (*Interruptions*) I am answering your question. You do not want to have the answer. ... (*Interruptions*)

* Not recorded.

You allow me to answer. Your time is going up. ... (*Interruptions*) Allow me to answer.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): महोदया, सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं थी। वैसे भी वैक्सीन जितनी पॉपुलेशन के लिए खरीदे जाते हैं, दुर्भाग्य से उनका पूरा उपयोग नहीं होता है। कई राज्यों में वैक्सीन की जितनी संख्या दी जाती है, उनका आधा भी खर्च नहीं होता है। वैक्सीन की कमी तो तब आएगी, जब 100 प्रतिशत वैक्सीन दिया और 120 प्रतिशत वैक्सीनेशन हो गया, 80 प्रतिशत वैक्सीन दिया और वैक्सीनेशन 100 प्रतिशत हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा जैसा कि मेरे साथी ने बताया कि प्रोडक्शन में कमी है, प्रोडक्शन और फील्ड में फर्क है, प्रोडक्शन में और फील्ड में कमी है। जहां तक फील्ड में कमी की बात है, वहां वैक्सीनेशन की कमी नहीं है।... (व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद: एक मिनट सुनेंगे तो आपको जवाब दिया जाएगा। ... (व्यवधान)

SHRI ANANTH KUMAR : Madam, according to his own report... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: No please.

... (*Interruptions*)



12.00 hrs**PAPERS LAID ON THE TABLE**

MADAM SPEAKER: Papers to be laid, Shri Pawan Kumar Bansal.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Brahmaputra Board, Guwahati, for the year 2007-2008, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Brahmaputra Board, Guwahati, for the year 2007-2008.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT- 553 /15/09)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES; MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN):

I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Outcome Budget (Hindi and English versions) of the Ministry of Earth Sciences for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No. LT- 554 /15/09)

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sree Chitra Triunal Institute for Medical Sciences and Technology, Thriuvananthapuram, for the year 2007-2008, alongwith Audited Accounts.

- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sree Chitra Triunal Institute for Medical Sciences and Technology, Thriuvananthapuram, for the year 2007-2008.
- (3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(Placed in Library, See No. LT- 555 /15/09)

- (4) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Bharat Immunologicals and Biologicals Corporation Limited and the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No. LT- 556 /15/09)

- (5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 3 of the All India Services Act, 1951:-

- (i) The Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Fourth Amendment Regulations, 2009 published in Notification No. G.S.R. 496(E) in Gazette of India dated the 7th July, 2009.
- (ii) The Indian Police Service (Pay) Third Amendment Rules, 2009 published in Notification No. G.S.R. 497(E) in Gazette of India dated the 7th July, 2009.
- (iii) The Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Third Amendment Regulations, 2009 published in Notification No. G.S.R. 498(E) in Gazette of India dated the 7th July, 2009.
- (iv) The Indian Forest Service (Pay) Second Amendment Rules, 2009 published in Notification No. G.S.R. 499(E) in Gazette of India dated the 7th July, 2009.

- (v) The Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Sixth Amendment Regulations, 2009 published in Notification No. G.S.R. 500(E) in Gazette of India dated the 7th July, 2009.
- (vi) The Indian Forest Service (Pay) Fifth Amendment Rules, 2009 published in Notification No. G.S.R. 501(E) in Gazette of India dated the 7th July, 2009.
- (vii) The Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Fifth Amendment Regulations, 2009 published in Notification No. G.S.R. 502(E) in Gazette of India dated the 7th July, 2009.
- (viii) The Indian Forest Service (Pay) Fourth Amendment Rules, 2009 published in Notification No. G.S.R. 503(E) in Gazette of India dated the 7th July, 2009.
- (ix) The Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Seventh Amendment Regulations, 2009 published in Notification No. G.S.R. 504(E) in Gazette of India dated the 7th July, 2009.
- (x) The Indian Forest Service (Pay) Sixth Amendment Rules, 2009 published in Notification No. G.S.R. 505(E) in Gazette of India dated the 7th July, 2009.
- (xi) The Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Fourth Amendment Regulations, 2009 published in Notification No. G.S.R. 506(E) in Gazette of India dated the 7th July, 2009.
- (xii) The Indian Forest Service (Pay) Third Amendment Rules, 2009 published in Notification No. G.S.R. 507(E) in Gazette of India dated the 7th July, 2009.

(Placed in Library, See No. LT- 557 /15/09)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI SHRIPRAKASH JAISWAL): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Neyveli Lignite Corporation Limited and the Ministry of Coal for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No. LT- 558 /15/09)

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Statistical Commission, New Delhi, for the year 2007-2008.

(ii) A copy of the Action Taken Report (Hindi and English versions) on the Recommendations of Annual Report of the National Statistical Commission, New Delhi, for the year 2007-2008.

(Placed in Library, See No. LT- 559 /15/09)

(3) A copy of the Outcome Budget (Hindi and English versions) of the Ministry of Statistics and Programme Implementation for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No. LT- 560 /15/09)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI JAIRAM RAMESH): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Outcome Budget (Hindi and English versions) of the Ministry of Environment and Forests for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No. LT- 561 /15/09)

(2) A copy of the Environment (Protection) Third Amendment Rules, 2009 (Hindi and English versions) published in the Notification No. G.S.R. 512(E)

in Gazette of India dated the 9th July, 2009 under Section 26 of the Environment (Protection) Act, 1986.

(Placed in Library, See No. LT- 562 /15/09)

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under Sections 3 and 6 of the Environment (Protection) Act, 1986:-

- (i) S.O. 1243(E) published in Gazette of India dated the 15th May, 2009 making certain amendments in the Notification No. S.O. 114(E) dated the 19th February, 1991.
- (ii) S.O. 1268(E) published in Gazette of India dated the 19th May, 2009 reconstituting the National Coastal Zone Management Authority consisting of the Chairperson, 10 Members and 1 Member Secretary, mentioned therein.
- (iii) S.O. 1675(E) published in Gazette of India dated the 9th July, 2009 constituting an Authority to be known as the Gujarat Coastal Zone Management Authority consisting of the Chairman, 13 Members and 1 Member Secretary, mentioned therein for a period of 3 years *w.e.f.* from the date of publication of the Notification.
- (iv) S.O. 1676(E) published in Gazette of India dated the 9th July, 2009 constituting an Authority to be known as the Andhra Pradesh Coastal Zone Management Authority consisting of the Chairman, 8 Members and 1 Member Secretary, mentioned therein, for a period of 3 years *w.e.f.* from the date of publication of the Notification.

(Placed in Library, See No. LT- 563 /15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS
(SHRI V. NARAYANASAMY): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya, Bhopal, for the year 2007-2008, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya, Bhopal, for the year 2007-2008.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT- 564 /15/09)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Asiatic Society, Kolkata, for the year 2007-2008, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Asiatic Society, Kolkata, for the year 2007-2008.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT- 565 /15/09)

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies, Kolkata, for the year 2007-2008, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies, Kolkata, for the year 2007-2008.

- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(Placed in Library, See No. LT- 566 /15/09)

- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Gandhi Smriti and Darshan Samiti, New Delhi, for the year 2007-2008.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Gandhi Smriti and Darshan Samiti, New Delhi, for the year 2007-2008, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Gandhi Smriti and Darshan Samiti, New Delhi, for the year 2007-2008.

- (8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

(Placed in Library, See No. LT- 567 /15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY

WELFARE (SHRI DINESH TRIVEDI): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Prevention of Food Adulteration (3rd Amendment) Rules, 2009 (Hindi and English versions) published in the Notification No. G.S.R. 431(E) in Gazette of India dated the 19th June, 2009 under Section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1955.

(Placed in Library, See No. LT- 568 /15/09)

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences, Aizawl, for the year 2007-2008, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences, Aizawl, for the year 2007-2008.
- (3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(Placed in Library, See No. LT- 569 /15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI S. GANDHISELVAN): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Homoeopathy, Kolkata, for the year 2007-2008, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Homoeopathy, Kolkata, for the year 2007-2008.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT- 570 /15/09)

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Siddha, Chennai, for the year 2007-2008, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Siddha, Chennai, for the year 2007-2008.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT- 571 /15/09)

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Academy of Ayurveda, New Delhi, for the year 2007-2008, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Academy of Ayurveda, New Delhi, for the year 2007-2008.
- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(Placed in Library, See No. LT- 572 /15/09)

- (7) A copy of the Drugs and Cosmetics (3rd Amendment) Rules, 2009 (Hindi and English versions) published in the Notification No. G.S.R. 157(E) in Gazette of India dated the 9th March, 2009 under Section 38 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940.
- (8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

(Placed in Library, See No. LT- 573 /15/09)

12.02 hrs.

**REPORT ON THE PARTICIPATION OF INDIAN PARLIAMENTARY
DELEGATION IN THE 120TH ASSEMBLY OF THE
INTER-PARLIAMENTARY UNION (IPU)**

SECRETARY-GENERAL: I beg to lay on the Table Hindi and English versions of the Report on the participation of Indian Parliamentary Delegation in the 120th Assembly of the Inter-Parliamentary Union held in Adis Ababa (Ethiopia) from 5 to 10 April, 2009.

(Placed in Library, See No. LT- 574 /15/09)

12.13 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377 *

MADAM SPEAKER: Matters under Rule 377 listed for today may be treated as laid on the Table of the House.

**(i)Need to expedite completion of the Koodankulum Nuclear Power Plant in
Tamil Nadu**

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): Sir, over the years, the demand for power had increased manifold but the supply is not adequate. Many of the States in the country are suffering from acute power shortage. The State of Tamil Nadu is reeling under severe power cuts and the shortage is around 1200 MW. This has affected domestic, industrial and agricultural operations.

Anticipating this kind of scenario, the Union Government had conceived the Koodankulum Nuclear Power Project. An inter-Governmental Agreement was signed on November 20, 1988 between the Government of India and erstwhile Soviet Union. However, the project remained mid-way after the post 1991 Soviet Union break-up.

Presently, two reactors are under construction. The Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) expects that the first unit when operational, can sell power at less than Rs. 2.50 per unit. In 2008 negotiations on building additional six reactors at the site began. It is expected that the capacity of each reactor will be 1000 MW.

The first of the units was expected to commence operations in December 2007 and the second in December 2008. However, there has been much delay mainly on account of equipment supplies from Russia. Finally, the date of

* Treated as laid on the Table.

commissioning of the first unit was rescheduled for December 2009 and the second one around March 2010. The delay in the commissioning of the Koodankulum Project is one of the main reasons for the severe power shortage of over 1000 MW in Tamil Nadu.

I, therefore, urge upon the Union Government to take immediate steps for the timely completion of the Koodankulum Project in Tamil Nadu.

**(ii) Need to provide special financial package for overall development of
Hoshiarpur Parliamentary Constituency in Punjab**

श्रीमती संतोष चौधरी (होशियारपुर): मेरे होशियारपुर संसदीय क्षेत्र का अधिकतर भाग पहाड़ी है जिसे कन्डी क्षेत्र भी कहा जाता है। यद्यपि होशियारपुर जिले को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है परन्तु यहां कुछ भी वांछित सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई हैं। प्राकृतिक आपदाओं ने इस क्षेत्र के नागरिकों का जीना दूभर कर रखा है। आज भी कन्डी क्षेत्र लोग मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आने जाने के साधनों से वंचित हैं। इस क्षेत्र में गरीब लोगों की जनसंख्या अधिक है। या तो वे भूमिहीन हैं अथवा थोड़ी-थोड़ी जमीन के मालिक हैं। जंगली जानवरों ने इतना आतंक फैला रखा है कि जिसके कारण कोई भी फसल उन्हें उपलब्ध नहीं होती है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एवं हिमालय प्रदेश जैसे पहाड़ी क्षेत्रों को भारत सरकार ने विशेष पैकेज देकर वहां के लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक दशा सुधारने का प्रयास किया है, परन्तु होशियारपुर का यह पहाड़ी स्थान जो कि हिमाचल का गेट वे कहलाता है, सुविधाओं से वंचित है।

भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि अन्य पहाड़ी क्षेत्रों की तरह होशियारपुर कन्डी क्षेत्र को विशेष औद्योगिक पैकेज दें।

(iii) Need to provide protection against the damage caused to crops by 'Neel Gai' in Faizabad, Barabanki and other adjoining districts in Uttar Pradesh

डॉ. निर्मल खत्री (फ़ैज़ाबाद): किसान हमारे देश की रीढ़ हैं। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद वह तमाम प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होता रहता है, जिस पर उसको दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की उचित व्यवस्था नहीं है। चाहे वह सूखा हो, अतिवृष्टि हो, बाढ़ हो या ओलावृष्टि हो। एक और समस्या हमारे इलाके जनपद फ़ैजाबाद, बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) व अन्य इलाकों में बड़ी विकट हो चली है वह है नील गायों द्वारा किसानों की फसलों की तबाही। नील गायों के झुण्ड खड़ी फसलों को रौंद रहे हैं, खा रहे हैं, किसान असहाय हैं, इनसे अपनी फसल को बचाने के लिए। अब तो यह व्यक्ति पर भी हमलावर हो जाते हैं।

नील गायों के प्रकोप से किसानों को बचाने के लिए सरकार ठोस कदम उठाये।

(iv) Need to bring professional approach in the functioning of Doordarshan and All India Radio

SHRI K. P. DHANAPALAN (CHALAKUDY): Doordarshan and All India Radio remains still the major source of news and entertainment for the majority of the population in this country even after the entry and flourishing of private players in the area of mass media. The liberal policies adopted by the Government over the years have encouraged the coming of more private players and resulted in increased competition amongst them. The increased number of visual and audio media does not substitute the need for effective and efficient Government owned institutions in the field of mass communications. In a democratic system the mass media has a vital role to play in protecting the social, secular and democratic values of a society.

The Government should address the various issues weakening the effective functioning of these institutions viz. lack of sufficient staff and non-redressal of the grievances of the employees. There is need to adopt professional approach in the functioning of these institutions. While addressing the various issues I would urge you to look into the issue of UPSC recruited programme officers at Doordarshan and AIR as they are left without a single promotion in their carrier which spans over a period of two decades.

While the mass communication field is growing in the country, the two major institutions of the Government in this area i.e. All India Radio and Doordarshan are weakening over the years. I would like to state that both these institutions need to be strengthened keeping in view the growing competition and professionalism in the field.

(v) Need to overcome the shortage of power in the country

SHRI N.S.V. CHITTHAN (DINDIGUL): India, the Asia's third largest economy, faced a power deficit of 73,050 million units in 2008. The 73,050 million-unit deficit was largely in Bihar, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mizoram, Nagaland, Tripura and Uttar Pradesh.

These states accounted for 80 to 90 percent of the total power demanded.

Given the fact that only around 56 percent of India's rural population or 78 million households do not have access to electricity, the mismatch between demand and supply will widen in time to come if the supply side is not improved.

The Government has estimated that India will require an installed capacity of over 200,000 megawatt (MW) by 2012 to meet the electricity demand, which will be 60 percent more of what the country has at present.

At present, about 26 percent of installed power generation capacity in India is hydropower against 50 percent in the 1960s, while around 66 percent is thermal generation including gas.

The nuclear energy constituted only about three percent of the country's total power generation, and non-conventional energy sources, of which wind energy is predominant, accounted for about five percent.

I, therefore, request the Central Government to take concrete steps to mitigate the difference in supply and demand of power in the country.

(vi) Need to check the emission of Gases and pollution caused by chemical manufacturing units in Ujjain district of Madhya Pradesh posing grave threat to human life and environment

श्री प्रेमचन्द गुड्डू (उज्जैन): मध्य प्रदेश के जिला उज्जैन नागदा में ग्वालियर केमिकल इण्डस्ट्रीज एवं आर्केमा केमिकल इण्डस्ट्रीज द्वारा निर्मित एल्यूमिनियम क्लोराइड से निकलने वाली क्लोरिन गैस तथा एसिड से आम जन जीवन, फसलें, चंबल नदी का जल प्रभावित हो रहा है। ग्वालियर केमिकल इण्डस्ट्रीज, आर्केमा केमिकल इण्डस्ट्रीज को मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल द्वारा लाइसेंस देकर विदेशी कम्पनियों के साथ एग्रीमेंट के साथ दोनों इण्डस्ट्रीज को बेचा जा रहा है।

मध्य प्रदेश में सन् 1984 में भोपाल स्थित अमेरिकन कम्पनी यूनीयन कार्बाइड से गैस रिसने के कारण एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। इसी प्रकार ग्वालियर केमिकल इण्डस्ट्रीज एवं आर्केमा केमिकल इण्डस्ट्रीज द्वारा निर्मित एल्यूमिनियम क्लोराइड से निकलने वाली क्लोरिन गैस तथा एसिड से भी बड़ा हादसा होने की पूरी संभावना है।

(vii) Need to shift the Divisional Office of Central Railway from Mumbai to Nagpur

SHRI VILAS MUTTEMVAR (NAGPUR): Presently, the Divisional Office of Central Railway is located at Mumbai. Mumbai being the Headquarters of Western Railway, the location of Divisional Office of Central Railway adds to the already existing congestion at Mumbai. As such shifting of the Divisional Office of Central Railway from Mumbai to Nagpur will not only relieve the congestion at Mumbai but will also give the required railway facilities to the people of Nagpur. Nagpur enjoys the status of being the most centralized place in the country. Nagpur in fact is already on the international map and it is the need of the hour that Railways should take advantage and facilitate to provide the efficient terminal services.

Nagpur is major trans-shipment centre for coal, foodgrains, cement, fruit etc. About 100 trains are passing from Nagpur almost daily for Kolkata, Bhubaneswar, Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu. Some trains are originating from Nagpur itself. Nagpur is having the required infrastructure for the establishment of the Divisional Office. While some of the Divisional Offices have been established at much smaller places but Nagpur which is the second capital of Maharashtra and developing as a major industrial and economic city is being lost sight of. I, would, therefore, urge upon the Hon. Railway Minister to have the Divisional Office of Central Railway shifted from Mumbai to Nagpur.

**(viii) Need to regularize and provide essential basic facilities in colonies of
North East Delhi Parliamentary Constituency**

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): राजधानी दिल्ली में कई सौ अनधिकृत कालोनियों को अधिकृत किया गया है, लेकिन इनमें अभी तक सीवर, जल, विद्युत, सड़क की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं करवायी गयी हैं, जिस कारण इन कालोनियों में रहने वाले लोग नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उत्तर-पूर्वी संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत नियमित की गयी कालोनियों की स्थिति अन्य कालोनियों की अपेक्षा बहुत ही बदतर है। वहां की नियमित की गयी कालोनियों में विकास संबंधी कार्य पूर्ण रूप से ठप्प पड़े हुए हैं। इस क्षेत्र की कालोनियों में भी जरूरी नागरिक सुविधायें उपलब्ध न कराये जाने के कारण नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में विशेषकर उत्तर-पूर्वी संसदीय क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफी आबादी होते हुए भी इस क्षेत्र को आबादी के हिसाब से पानी की आपूर्ति नहीं की जा रही है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उत्तर-पूर्वी संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत नियमित की गयी कालोनियों में सीवर, जल, विद्युत, सड़क की सुविधायें अविलम्ब उपलब्ध करवाये जाने तथा इस क्षेत्र की जिल अनधिकृत कालोनियों को अब तक नियमित नहीं किया गया है, उनको भी शीघ्र नियमित किए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाने के साथ-साथ इस क्षेत्र को आबादी के अनुपात से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए।

(ix) **Re: Need to check the difference in prices of common generic medicines sold through different brand names by various drug manufacturing companies.**

श्री गणेश सिंह (सतना): मैं केन्द्र सरकार का ध्यान जीवन रक्षक दवाइयों के दामों में भारी अंतर की ओर दिलाना चाहता हूँ। एक ही प्रकार की दवा के विभिन्न दवा कम्पनियों के रेट में भारी अंतर है। यह अंतर दो गुना से लेकर पांच गुने का है। कम्पनियां जेनरिक नाम के साथ-साथ ब्राण्ड नाम से भी दवा बनाती है और डॉक्टर ब्राण्ड नाम से दवा अपने दवाइ के पर्चे में लिखते हैं, जिससे कम्पनियों को करोड़ों का फायदा होता है। कम्पनी के ब्राण्ड नाम से दवा लिखने पर डॉक्टरों को पुरस्कृत भी विभिन्न प्रकार से किया जाता है। वैसे तो नियमानुसार डॉक्टर को जेनरिक नाम से दवा लिखने का प्रावधान है, पर ऐसा होता नहीं है। एक तुलनात्मक चार्ट इस प्रकार से है:-

दवा का जेनरिक नाम	ब्राण्ड नाम	कं. का नाम	मूल्य	ब्राण्ड नाम	कं. का नाम	मूल्य	ब्राण्ड नाम	कं. का नाम	मूल्य
विटामिन B12 500 एच.पी.	विटामिन	डीएस	63.57 10 गोली	रिसेप्ट	रेवेन्सी	88.60 10 गोली	जेनसान	एच.डी.सी.	45.33 10 गोली
असालोमेथिल 400 एच.पी.	इकोरेन	जेनरल	44.00 10 गोली	रिसेप्ट	प्रैको इंडिया	19.00 10 गोली	इलेवन	फ़िन्नुसान ए-टीआर/टीक	8.92 10 गोली
ओ फलोसासॉलिन 200 एच.पी.	जेमिडिन	रेवेन्सी	87.50 10 गोली	सेमिडिन	फोर्मेडिन	310.00 10 गोली	इएन	मर्डी	35.00 10 गोली
नोरसोडिन 100 एच.पी.	सोसल	सेनकाइन्ड	16.00 10 गोली	नोसल	जी.एच.टी.	32.00 10 गोली	निलसड	डी-नसल	23.00 10 गोली
सेट्टिनि	सेट्टिन	प्लैसो	37.00 10 गोली	सेट्टिन	जी.एच.टी.	28.00 10 गोली	कोप	सेनकाइन्ड	11.00 10 गोली
सिंक्रोप्रोस्टिन इन्जेक्शन	न्यूरोकाइन्ड	सेनकाइन्ड	9.90 1 एच.एल.	रेकुनुसन	फोसल	59.00 1 एच.एल.	मेगाडोबाल	सेनकाइन्ड	96.00 1 एच.एल.
ओमेप्रोन इन्जेक्शन	ओमेप	इवैन डी.व्हा.बी.ए.	14.44 2 एच.एल.	जेकर	सन फार्मा	30.00 2 एच.एल.	पिलेसड	इफका	14.90 2 एच.एल.
नैनुलोन डेक्लोरिड इन्जेक्शन	डेकानुलोन	इ-न सॉल्यूट	83.26	डिक्लोराल	एलफेट	79.06	सेटडेक	जसलपाल	106.00
सी-जॉइंट इन्जेक्शन	सेटिन	रेवेन्सी	307.60 1 एच.एल.	सी-जॉइंट	एच.अमेर	106.95 1 एच.एल.			

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि एक ही दवा के मूल्य में जो अंतर है जिससे अपभोक्ताओं को अधिक राशि देनी पड़ती है। इसलिए इसकी जांच कराई जाए।

(इति)

(x)Need to accord special status to Rajasthan under Accelerated Irrigation Benefit Programme

श्री राम सिंह कस्वां (चुरु): त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान को विशेष दर्जा देने की मांग काफी समय से की जा रही है ताकि उदार शर्तों पर केन्द्रीय ऋण सहायता की सुविधा ली जा सके। विशेष वर्ग के राज्यों के लिए परियोजनाओं की लागत का 90 प्रतिशत एवं साधारण वर्ग के राज्यों के लिए परियोजनाओं की लागत की 25 प्रतिशत शशि केन्द्रीय अनुदान के रूप में दी जाती है, अगर राजस्थान को विशेष दर्जा नहीं दिया जाता है तो राज्य के लिए त्वरित सिंचाई कार्यक्रमों का संचालन करना असंभव होगा। इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विशेष वर्ग के राज्यों की तुलना में राजस्थान राज्य की स्थिति अत्यंत नाजुक है। राज्य का 2/3 हिस्सा थार रेगिस्तान व सूखा क्षेत्र है, जहां बार-बार अकाल पड़ते हैं। राजस्थान का काफी हिस्सा जनजातीय क्षेत्र है, भारत पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े होने के कारण भी यह अति संवेदनशील है, राज्य में वर्षा बहुत कम होती है। अतः राज्य के विकास को गति देने हेतु यह अति आवश्यक है कि जम्मू-कश्मीर, हरियाणा एवं उत्तर पूर्वी राज्य की तरह राजस्थान राज्य को भी विशेष दर्जा दिया जाये।

(xi)Need for four-laning of N.H. –92

श्री अशोक अर्गल (भिंड): राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 92 ग्वालियर-भिण्ड-इटावा को जोड़ता है इसी के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 92 उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से मिलता है तथा उत्तर प्रदेश के अधिकांश वाहन इसी राजमार्ग से निकलते हैं। इस सड़क की हालत बहुत खराब है। मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 92 में बढ़ते हुए ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए 4 लेन का मार्ग बनाये जाने हेतु निर्देश देने का कष्ट करें।

**(xii)Need to shift Veerawada Railway Station to Gambhoi in Sabarkantha
Parliamentary Constituency, Gujarat**

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): मैं केन्द्र सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे निर्वाचन क्षेत्र साबरकांठा , गुजरात में अहमदाबाद-उदयपुर के रास्ते में हिम्मत नगर मीटर गेज रेलवे लाइन पर वीरावाडा नाम से एक रेलवे स्टेशन है। वास्तव में वीरावाडा स्टेशन केवल वाटडा गांव के लोगों के लिए ही है। यह स्टेशन इस क्षेत्र के आस-पास के गांवों के लोगों के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है और सुविधाजनक भी नहीं है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वीरावाडा स्टेशन को गांभोई गांव के निकट शिफ्ट किया जाए और इसका नाम भी वीरावाडा के बजाय गांभोई स्टेशन रखा जाए, क्योंकि गांभोई गांव के आस-पास साबरकांठा जिले के 50 अन्य गांव है। गांभोई इस क्षेत्र के वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में भी प्रसिद्ध है। यह हिम्मत नगर के बाद स्थित है। यह रेलवे लाइन गांभोई से होकर निकलती है। अतः वीरावाडा स्टेशन को गांभोई में शिफ्ट करना रेल प्रशासन के लिए अधिक सुविधाजनक होगा।

(xiii)Need to construct Railway Over Bridges in district Chandauli, Uttar Pradesh

श्री रामकिशुन (चन्दौली): उत्तर प्रदेश के जनपद चन्दौली में कई रेल लाइनें बिछाई गई हैं जिससे जनपद कइ भागों में बंट गया है। इन रेलवे लाइनों में ओवर ब्रिज न होने से जनता को जिले के एक कोने से दूसरे कोने तक आने-जाने में काफी कठिनाई और परेशानी उठानी पड़ती है तथा कई रेलवे लाइनों को पार करना पड़ता है। गेट बन्द होने की हालत में आम जनता का काफी समय प्रतीक्षा करने में ही लग जाता है। जिला मुख्यालय तथा अस्पताल आदि स्थानों पर जाने में असुविधा होती है। कभी-कभी रेलवे फाटक बन्द होने से मरीजों को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है। नक्सल प्रभावित जिला होने के नाते भी प्रशासनिक दृष्टिकोण तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्रशासन के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में दिक्कत होती है। इस जनपद में मुगलसराय-गया-हावड़ा लाइन, मुगलसराय-पटना लाइन तथा मुगलसराय-वाराणसी, मुगलसराय-इलाहाबाद लाइनों ने पूरे जनपद को 4-5 भागों में बांट के रख दिया है। इन लाइनों पर अधिक सवारी गाड़ियों एवं मालगाड़ियों का आवागमन होने से रेलवे फाटक बहुत देरी तक बन्द रहते हैं जिससे आम जनता का कीमती समय बर्बाद होता है। न व्यापारी अपना व्यापार ठीक से कर पाता है, न ही स्कूल कालेज जाने वाले छात्र समय से स्कूल पहुँच पाते हैं।

अतः सदन के माध्यम से मेरा माननीया रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि जनहित में चन्दौली जिला मुख्यालय स्थित रेलवे लाइन, गया मुगलसराय स्थित चन्दौली-सैदपुर मार्ग तथा अलीनगर से सकलडीहा मार्ग के मटकुट्टा रेलवे गेट एवं सैयदराजा जमनिया मार्ग के रेलवे गेट पर ओवर ब्रिजों का तत्काल निर्माण कार्य कराए जाने की मांग करता हूँ।

**(xiv) Need to provide special financial assistance to the farmers in drought-hit
Balua and Deoria districts of Uttar Pradesh**

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): जनपद बलिया व जनपद देवरिया समेत सम्पूर्ण पूर्वांचल में भयंकर सूखा पड़ा है। जिससे किसान खरीफ की बुआई भी नहीं कर सका है। जो कुछ बुआई हुई हे वे भी सूख रही है। पशु-पक्षी, जनजीवन इस भयंकर सूखा के कारण काफी परेशान है। केन्द्र सरकार इस स्थिति में विशेष पैकेज देकर किसानों को इस विपदा से उबारने में यथाशीघ्र कारगर उपाय करने का कष्ट करें।

(xv) Need to expedite the construction of railway bridge on river Kosi in district Supaul, Bihar

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल):आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान राष्ट्रहित एवं जनहित की समस्या की ओर आकृष्ट करते हुए कहना है कि बिहार प्रांत के सुपौल में कोसी नदी पर महासेतु रेल मार्ग का निर्माण कार्य 2009 तक पूरा होना था, किन्तु बजट में खर्च के हिसाब से धन की नगण्य व्यवस्था एवं कार्य के धीमी गति से चलने से ऐसा प्रतीत होता है कि 2015 तक भी महासेतु का निर्माण नहीं हो सकेगा एवं मिथिलांचल की चिर-परिचित मांग सपना बनकर रह जाएगी।

माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि कोसी महासेतु पर रेल लाइन का निर्माण कार्य त्वरित गति से चलाने का प्रबंध करने का कष्ट करें जिससे कि जनता की समस्या का निदान हो सके।

(xvi) Need to set up a Bench of Supreme Court in Chennai, Tamil Nadu

SHRI D. VENUGOPAL (TIRUVANNAMALAI): Democracy is generally the rule of law framed by the people's representatives who are elected directly by the people who cast their vote and decide. There can be legal disputes when two parties feel that they are right according to the law. To settle their disputes, they go to court of law seeking justice. But that justice, if delayed, is nothing but denying justice. In order to strengthen our democracy, we must ensure that our court cases are not kept pending for long, denying justice to the people caught in the web of our judicial system. But unfortunately, in our Supreme Court itself, there are at least fifty thousand cases pending today. Those who are involved in those cases have to frequent the national Capital, New Delhi, from their places of residence spread throughout the country. This expense and valuable man-hour loss can be avoided by speedy disposal of cases.

Before we could venture upon judicial reforms, we can right away establish more Benches of the Supreme Court in various State Capitals. This matter has been taken up with the Centre and the Chief Justice of India by the Government of Tamil Nadu. Hence, I urge upon the Union Government and the ministry of Law and Justice to hold consultations with the Hon'ble Supreme Court of India and make earnest efforts to establish a Bench of Supreme Court in Chennai to begin with as a pioneering venture, as per the request made by the Chief Minister of Tamil Nadu.

(xvii) Need to expedite release of incentive fund under the Accelerated Power Development and Reforms Programme to Orissa

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): The Accelerated Power Development and Reforms Programme (APDRP) has an incentive component to encourage SEB/Utilities to improve their performance and to reduce losses. Orissa Government had submitted a proposal to Government of India claiming incentive to the tune of Rs. 264.94 crore for the year 2003-04. Although the distribution network has been privatized in Orissa, the State Government has 49% shares and GRIDCO is a state Public Sector Undertaking. Yet, the Government of India has observed that assistance under APDRP would not be applicable for private companies. Such a approach amounts to penalizing the State Government for the pioneering effort in reforming the power sector and also defeats the very objective of the Orissa Electricity Reform Act, 1995 and the Electricity Act, 2003 which intends to promote competition in the electricity industry through private sector participation in the power sector.

Orissa has already lost substantial incentive under APDRP during Xth plan owing to the fact that the implementation was carried out through its private distribution companies. I urge upon the Government for early release of the incentive, which would be not only utilized for the benefit of the sector but also encourage/motivate utilities to reduce revenue losses.

(xviii)Need to stop the construction of a dam across river Palar in Andhra Pradesh

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): A disturbing news about the decision the Government of Andhra Pradesh to go ahead with the construction of a Dam across Palar River at Ganesapuram in Kuppam has created unrest in Tamil Nadu. Construction of the Dam would affect the irrigation as well as drinking water needs of Vellore, Thiruvallur, Thiruvannamalai, Kancheepuram and Chennai. Chairman, Central Water Commission convened the meeting of the officials from both States and asked Andhra Pradesh not to construct a dam across Palar river till the issue is settled. I feel the situation is volatile. The Government of India should immediately intervene in the matter and instruct the Andhra Pradesh Government to stop the construction work forthwith.

(xix)Need to regularize the services of Extra-Departmental employees of Postal Department and extend the benefits of Sixth Central Pay Commission to them

श्री इन्दर सिंह नामधारी (चतरा): सारे संचार माध्यमों के विकास के बावजूद आज पोस्टल विभाग की महत्ता कम नहीं हुई है। पोस्टल विभाग का अधिकतम काम इन विभाग के ई.डी. कर्मचारियों ने संभाल रखा है। लगभग डेढ़ शताब्दी से ई.डी. कर्मचारी पोस्टल विभाग की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्यरत है। न्याय की दृष्टि से आज जरूरत है कि ई.डी. कर्मचारियों का नियमितीकरण कर दिया जाए तथा इन न्याय से वंचित कर्मचारियों को पेंशन देने की योजना का भी लाभ मिले तथा छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों से भी इन ई.डी. कर्मचारियों को लाभान्वित किया जा सके।

12.04 hrs.**RE: RISE IN PRICES OF ESSENTIAL COMMODITIES**

MADAM SPEAKER: Hon. Members, now the House shall take up discussion under Rule 193. There will be no 'Zero Hour' at this time, it will be taken up later in the evening. We have fixed two hours for this discussion. I would urge upon all the hon. Members to be brief. Shri Basudeb Acharia to start the discussion.

... (Interruptions)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे आश्वासन दिया था कि ज़ीरो आवर में बोलने के लिए मौका देंगे। हू(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : नहीं, हमने कोई आश्वासन नहीं दिया था।

श्री मुलायम सिंह यादव : दो मिनट बोलने दें। हू(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : जी नहीं, बाद में। अभी नहीं। जो भी बैत थी, आप कह चुके हैं। देखिये, प्राइस राइज़ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, ऐसा सबने कहा है। उसके लिए दो घंटे का समय है। उस समय का हम पूरा पूरा सदुपयोग करना चाहते हैं। उसमें से एक क्षण भी व्यर्थ न हो यह सबकी इच्छा है। बसुदेव आचार्य जी, आप ठूँपया शुरू करें।

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : क्या कर रहे हैं आप? खोड़ा मदद कीजिए हमारी। हू(व्यवधान)

श्री तूफ़ानी सरोज (मछलीशहर): आपने कहा था कि ज़ीरो आवर में बैत सुन ली जाएगी। हू(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : आपने यह कहा था कि बाद में सुनेंगे। हू(व्यवधान) आपने कहा है।

अध्यक्ष महोदया : जो कुछ भी आपको कहना था, वह सुबह कह लिया। वह रिकार्ड में चला गया। ज़ीरो आवर की कोई बैत नहीं है। अभी कोई ज़ीरो आवर नहीं है। श्री बसुदेव आचार्य जी, आप बोलिये। हू(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : आपने हमें समय देने की बैत कही थी। दो मिनट समय देने की बैत कही थी आपने। आपने कहा था कि प्रश्न काल के बाद आप मौका देंगी। हू(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : केवल बसुदेव आचार्य जी की बैत रिकार्ड में जाएगी। ठूँपया आप आरंभ करें।

(Interruptions) ... *

12.04 ½ hrs.

(At this stage Shri Shailender Kumar and some other Members came and stood on the floor near the Table)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Madam Speaker... *(Interruptions)*

अध्यक्ष महोदया : प्राइस राइज़ पर डिस्कशन शुरू हो गया है। बसुदेव आचार्य जी, आप कृपया शुरू करें।

...(ब्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Madam, generally it was discussed...

(Interruptions)


अध्यक्ष महोदया : आप शांत हो जाइए। हमने यह बात नहीं कही थी। Do not attribute things to me which I have not said.

... *(Interruptions)*

अध्यक्ष महोदया : हमने नहीं कहा था।

...(ब्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी प्रश्न काल के शुरू में इस मुद्दे को उठा चुके हैं और वह रिकार्ड में भी चला गया है। अब आप यह डिस्कशन कृपया शुरू होने दीजिए।

...(ब्यवधान) 

MADAM SPEAKER: The House is adjourned till 12.15 p.m.

12.06 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fifteen Minutes past Twelve of the Clock.

12.15 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Fifteen Minutes past Twelve of the Clock.

(Shrimati Sumitra Mahajan *in the Chair*)

RE: RISE IN PRICES OF ESSENTIAL COMMODITIES – Contd.

... (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN (SHRIMATI SUMITRA MAHAJAN): Now, Shri Basu Deb Acharia.

... (व्यवधान)

सभापति महोदया: माननीय मुलायम सिंह जी, आप पहले दो-तीन मिनट बोल कर अपनी बात उठा चुके हैं। आचार्य जी, आप अपनी बात प्रारम्भ करें। केवल बसुदेव आचार्य जी की बात रिकार्ड में जाएगी।

... (व्यवधान)

सभापति महोदया: क्या आप महंगाई पर चर्चा करना नहीं चाहते हैं?

... (व्यवधान)

MADAM CHAIRMAN: Nothing will go on record. Only what Shri Basu Deb Acharia says will go on record.

(*Interruptions*) ... *

MADAM CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(*Interruptions*) ... *

सभापति महोदया: बसुदेव आचार्य जी, आप बात करना नहीं चाहते हैं?

... (व्यवधान)

सभापति महोदया: अगर आप महंगाई पर चर्चा नहीं चाहते हैं तो बात अलग है।

... (व्यवधान)

*Not recorded.

सभापति महोदया: मुलायम सिंह जी, आपको पहले दो मिनट बोलने का समय मिल चुका है।

...(ब्यवधान)

सभापति महोदया: बसुदेव आचार्य जी, अगर आप कुछ नहीं बोलना चाहते हैं.....।

...(ब्यवधान)

MADAM CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

12.17 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Fourteen
of the Clock.*

14.00 hrs.

(The Lok Sabha reassembled at Fourteen of the Clock)

**RE: COMMISSIONING OF GAS BASED POWER PROJECT AT DADRI,
GAUTAM BUDH NAGAR, UP**

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, केवल आप बोलिए। आपके पीछे जो माननीय सदस्य खड़े हैं, कृपया उन्हें बैठने के लिए कहिए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार ने गाजियाबाद में एक पॉवर प्लांट की स्थापना की स्वीकृति दी थी। वह 37,500 मैगावाट का प्लांट गैस आधारित है। हम लगातार केन्द्रीय सरकार से गैस देने की प्रार्थना करते रहे, लेकिन उसने गैस नहीं दी। अगर केन्द्र सरकार उक्त गैस आधारित विद्युत प्लांट को गैस दे देती, तो उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और अन्य प्रान्तों में बिजली पहुंच जाती और अंधेरे प्रदेशों में रोशनी हो जाती। उत्तर प्रदेश को तो केवल 13-14 सौ मैगावाट बिजली की जरूरत थी, लेकिन ये गैस नहीं दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका विषय हो गया। अब आप बैठ जाइए।

श्री मुलायम सिंह यादव : अभी नहीं हुआ है।

महोदय, ये गैस नहीं दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि उस प्लांट के लिए केन्द्र सरकार गैस दे।

महोदय, दूसरी बात यह है कि देश में बिजली का संकट है और बिना बिजली के आम आदमी परेशान है। जब यह मामला हाईकोर्ट में गया, तो हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि उक्त प्लांट हेतु सरकार को गैस देनी चाहिए। हाईकोर्ट में सरकार ने कोई पैरवी नहीं की। अब केन्द्र सरकार हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील करने गई है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि इसका क्या मतलब है?

सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्यों गई? बिजली पैदा करने के लिए उस प्लांट को गैस केन्द्र सरकार को देनी है, लेकिन गैस नहीं दी जा रही है। सरकार यह भी बताना नहीं चाहती है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। मेरे अनुसार यह सरकार एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाना चाहती है। ...(व्यवधान) हमारे लिए कहते हैं कि हम अनिल अम्बानी से मिले हुए हैं। ...(व्यवधान) हमें कोई मतलब नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका विषय हो गया।

श्री मुलायम सिंह यादव : अभी नहीं हुआ है। हमें बिजली चाहिए। केन्द्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्यों गई? उस प्लांट को गैस नहीं देनी पड़े, इसलिए यह सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है। यानी गैस को रोकने के लिए यह सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है। इससे 30 हजार करोड़ रुपए का नुकसान एन.टी.पी.सी. को होगा। सरकार एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई। सरकार का यह कदम खुल्लमखुल्ला, जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद करने के बराबर है। देश का विकास बिजली के बिना सम्भव नहीं है। प्लांट को गैस नहीं देने के कारण एन.टी.पी.सी., जो सरकारी संस्था है, उसे 30 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात रख दी है।

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्यों गई है? सरकार देश को 30 हजार करोड़ रुपए का घाटा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों गई?

उपाध्यक्ष महोदय : आपका विषय हो गया।

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विषय तब तक पूरा नहीं होगा, जब तक सरकार की ओर से उत्तर सदन में नहीं आ जाएगा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों गई? उपाध्यक्ष महोदय, जब तक जबाव नहीं आएगा, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। 30 हजार करोड़ रुपए का घाटा सरकार के उपक्रम को इसलिए दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाना चाहती है। हम पर आरोप लगाए जाते हैं। यदि अनिल अम्बानी और और मुकेश अम्बानी का विवाद है, तो यह दो उद्योगपतियों का विवाद है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : विषय तो आपने सदन में प्रस्तुत कर दिया है।

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदय, उत्तर प्रदेश में बिजली प्लांट को केन्द्र सरकार गैस नहीं देना चाहती है, फिर दूसरे सूबों में इसी प्रकार के बिजली के प्लांट तीन जगह और लग रहे हैं, वहां गैस क्यों दी जा रही है? उत्तर प्रदेश को आप अंधेरे में क्यों रखना चाहते हैं? दिल्ली में बिजली की परेशानी है, राजस्थान में बिजली की कमी है और हरियाणा में कठिनाई है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आइटम नंबर 12.

श्रीमती सुषमा स्वराज की तरफ से अनुरोध प्राप्त हुआ है कि उनकी तरफ से सदन में श्री यशवन्त सिन्हा को चर्चा प्रारम्भ करने की अनुमति दी जाए।

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है। हमारी बात का उत्तर माननीय मंत्री महोदय दें, हम यह अनुरोध करना चाहते हैं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, श्री मुलायम सिंह का भाषण रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। माननीय सदस्य श्री यशवन्त सिन्हा के अतिरिक्त अन्य किसी भी माननीय सदस्य का भाषण रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।

...(व्यवधान) *

उपाध्यक्ष महोदय : बाकी की बात रिकार्ड नहीं होगी, आपकी ही रिकार्ड होगी।

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग): उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग कृपया बैठ जायें। आपने अपनी बात रख दी है। अब सरकार अपना जवाब देगी या नहीं देगी, यह सरकार पर निर्भर है, इसलिए आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग कृपया बैठ जाइये, सदन को चलने दीजिए। श्री यशवन्त सिन्हा जी।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यशवन्त सिन्हा जी, आप शुरू कीजिए। रिकार्ड में सिर्फ यशवन्त सिन्हा जी की बात जाएगी। कृपया बैठ जायें।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): मेरी इस बात पर माननीय सदस्य श्री मुलायम सिंह जी सहमत होंगे कि जब हाउस में एकदम कोई मसला उठाया जाता है कि सरकार क्यों सुप्रीम कोर्ट में गई या क्या मसला है, वह यहां इस वक्त हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना मैं विश्वास जरूर दिलाता हूं कि जो बात यहां कही जाती है, मैं उस बात को हमारे जो सम्बन्धित मंत्री हैं, उनके इल्म में जरूर ले आता हूं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपके विषय में मंत्री जी ने बोल दिया है।

श्री मुलायम सिंह यादव : नहीं, वह सवाल नहीं आया। मेरा कहना है कि मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी जवाब दे सकते हैं, विदेश मंत्री भी जवाब दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है, नहीं तो प्रधानमंत्री जी दे सकते हैं, कोई तो जवाब दे सकता है।...(व्यवधान)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Sir, this matter was raised immediately after the Question Hour and the House was adjourned for two hours. We could not transact any business. Again the same matter is being raised. ... *(Interruptions)* Will the House be held to ransom like this and that we cannot discuss anything else? ... *(Interruptions)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आपकी बात आपने रख दी है, सरकार ने भी सुन ली है। सरकार उचित समय पर जवाब देगी, आज आप हाउस चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : जवाब कब देंगे, समय बता दीजिए। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह हमारा डिसाइड करने का काम नहीं है, यह सरकार का काम है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया सदन को चलने दीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): आप एक तिथि बता दें कि कब जवाब देंगे।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह काम चेयर से नहीं होता है।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : यह देश का सवाल है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री यशवंत सिन्हा।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : मंत्री जी का इस पर जवाब आना चाहिए। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सदन को चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): यह मामला इन्होंने सदन के संज्ञान में ला दिया है। ...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 3.00 p.m.

14.11 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fifteen of the Clock.

15.00 hrs .

(The Lok Sabha reassembled at Fifteen of the Clock)

(Madam Speaker in the Chair)

SUBMISSION BY MEMBER

**RE: COMMISSIONING OF GAS BASED POWER PROJECT AT DADRI,
GAUTAM BUDH NAGAR, UTTAR PRADESH-Contd.**

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया शान्त हो जाइए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, मेरा निवेदन है कि सरकार की तरफ से उत्तर आना चाहिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं, आप सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : मंत्री जी मेरी बात सुनकर ही बोलेंगे।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): मैं इनकी एक-एक बात का जवाब नहीं दे सकता हूँ।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप सुबह बोल चुके हैं। उन्हें उत्तर देने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : मुलायम सिंह जी, आज चार बार ऐसा हो चुका है।...(व्यवधान) सुबह क्वश्चन आवर से पहले, क्वश्चन आवर के बाद और बाद में भी इस बारे में दो बार जिक्र होता रहा है। इन्होंने यह बात उठाई है। मैं आपके माध्यम से सदन को इतना ही बताना चाहता हूँ और इन्हें विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ कि संबंधित मंत्री इस पर सोमवार को अपनी स्टेटमेंट दे देंगे, वे रिस्पॉंड कर देंगे।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब शान्त हो जाइए।

...(व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Why was the issue of price rise -- listed for discussion today -- not discussed in the House? Is Mr. Anil Ambani so important that the issue of price rise is going to be dropped from the table of discussion? ... (*Interruptions*) We are fixing up time for the discussion on price rise in the Business Advisory Committee (BAC). ... (*Interruptions*) The issue of price rise is an important issue. You had called the name of Mr. Basudeb Acharia to initiate the discussion on this issue, but it was not discussed. It is unfortunate. ... (*Interruptions*) Members are coming to discuss the most vital and burning issue of the country, but it is not being allowed to be discussed in the House. Somebody's gas line has been ... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: All this will not go on record.

(*Interruptions*) ...*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : वे प्राइस राइज़ के बारे में बात कर रहे हैं, आप बैठ जाइए। आज प्राइस राइज़ पर डिस्कशन थी लेकिन नहीं हो पाया। उनकी चिन्ता है, वे बोल रहे हैं।

... (व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : It is a disgrace. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: We are having the meeting of BAC in a little while. We will discuss it, and we will fix the time for it.

* Not recorded.

15.02 hrs**DISCUSSION UNDER RULE 193****Issues arising out of Prime Minister's recent visit to foreign countries**

MADAM SPEAKER: The House shall now take up Discussion under Rule 193.

Shri Yashwant Sinha.

... (*Interruptions*)

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस चर्चा के लिए समय मुकर्रर किया। मैं इस बात का भी आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपने नेता का भी आभारी हूँ जिन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर पार्टी का पक्ष रखने के लिए मुझे बोलने का अवसर दिया। हाल के दिनों में दिल्ली मेट्रो के कई पिलर्स क्रैक कर गए, कुछ गिर भी गए। उसकी जांच अलग चल रही है लेकिन अभी प्रधान मंत्री जी की विदेश यात्राओं के दौरान इस देश की विदेश नीति के जो पिलर्स थे, उसमें बहुत सारे क्रैक पड़ गए हैं, बहुत सारे गिर गए हैं। देश की विदेश नीति बराबर राष्ट्रीय सहमति के आधार पर चली है। जो भी सरकार में होता है, वह महत्वपूर्ण मुद्दों पर विपक्षी दलों को भी विश्वास में लेता है, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होती है और फिर आगे की रणनीति तय की जाती है ताकि देश में वह सहमति बनी रहे। मैं बहुत अफसोस के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि पिछले कई वर्षों से यह सहमति लगभग समाप्त हो चुकी है, क्योंकि वह परम्परा ही समाप्त हो गई कि सबको विश्वास में लेकर साथ चलना चाहिए। पाकिस्तान के संबंध में हमारी जो परम्परागत नीति रही, उसमें राष्ट्रीय सहमति एक बहुत ही मजबूत आधार था। मुझे लगता है, मैडम, शायद यह पहला मौका है जब इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर राष्ट्रीय सहमति न केवल चरमरा गयी, क्रैक हो गयी बल्कि ध्वस्त हो गयी, वह पिलर ही गिर गया। शायद यह पहला मौका है। मैं आपके माध्यम से सदन को विश्वास में लेना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मुंबई पर जो हमला हुआ था, वह सिर्फ एक साधारण आतंकवादी हमला या घटना नहीं थी, मुंबई पर हमला हमारे देश की सम्प्रभुता पर हमला था, वह पाकिस्तान का भारत के ऊपर हमला था। मुंबई हमले के बाद इसी सदन में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जिसे मैं यहां कोट कर रहा हूँ :

“Firstly, we have to galvanize the international community into dealing with sternly and effectively with the *epicentre of terrorism which is located in Pakistan.*”

The infrastructure of terrorism has to be dismantled permanently. The Prime Minister also informed the House that he had told several Heads of State and Government who had called him up that India would not be satisfied with only assurances. He said the use of terrorism as an instrument of State policy is no longer acceptable.”

These are not my words, Madam; these are the words of the Prime Minister of India. उसके बाद on July 16, the Prime Minister met the President of Pakistan, President Zardari, in Yekaterinburg and admonished him in the hearing of the whole world. He told him:

“I am happy to meet you, but my mandate is limited to telling you that the territory of Pakistan must not be allowed to be used for terrorism against India.”

Strong words; we all felt very proud of our Prime Minister; here was our Prime Minister, fresh from his victory at the polls, confident, assertive, ready to tell Pakistan and the rest of the world, “Do not mess around with us”. That was the message that he had conveyed, and we felt proud that the Prime Minister had conveyed this message on behalf of the whole country. ... (*Interruptions*)

SHRI J.M. AARON RASHID (THENI): It is a feather in the cap of the hon. Prime Minister.

SHRI YASHWANT SINHA (HAZARIBAGH): I will praise him whenever he deserves praise.

In less than a month, at Sharm-el-Sheikh, there was a complete turnaround from this stated position, and a Joint Statement was issued. In the Joint Statement, there are many points, and I would like to take them by one by one which stand out. ये क्या बिन्दु हैं,


“They considered the entire gamut of bilateral relations with a view to charting the way forward in India-Pakistan relations. [I emphasize the words *entire gamut of bilateral relations*.]

Second, both leaders agreed that terrorism is the main threat to both countries.

Third, Prime Minister Singh reiterated the need to bring the perpetrators of the Mumbai attack to justice. Prime Minister Gilani assured that Pakistan will do everything in this regard.

Fourth, Prime Minister Gilani mentioned that Pakistan has some information on threats in Balochistan and other areas.

Fifth, both Prime Ministers recognized that dialogue is the only way forward. Action on terrorism should not be linked to the composite dialogue process and these should not be bracketed.”

The sixth point is, the Prime Minister Singh said that India was ready to discuss all issues with Pakistan including all outstanding issues. Seventh point is, the Prime Minister Singh reiterated India's interest. Please note that the Prime Minister Singh reiterated India's interest in a stable, democratic, Islamic, Republic of Pakistan. And finally, both leaders agreed that the two countries will  real time-credible, actionable information on any future threats. Both Foreign Secretaries will meet as often as necessary and report to the Foreign Ministers who will meet on the sidelines of the forthcoming UN General Assembly.

Now, let us take up these issues from the Joint Statement that I have just placed before you. The first is, the two Prime Ministers discussed the entire gamut of bilateral relations. It was not merely confined to cross border terrorism. It was not merely confined to holding Pakistan guilty of the acts of terrorism that it has unleashed on our sacred soil. We discussed, the Prime Minister discussed the whole gamut of bilateral relations. So, the whole thing was expanded. Secondly, when we say that both leaders agreed that terrorism is the main threat to both countries, then they put India and Pakistan at par. The distinction between the aggressor and the victim was obliterated, completely obliterated because we are both victims of terrorism. So, where is the question of being the perpetrator of terrorism and where is the question of being the victim of terrorism? Then Pakistan gave the assurance that it would do all within its power to bring the perpetrators of the Mumbai attacks to justice. We know that the Home Minister of Pakistan has said that they have

absolutely no evidence against Hafiz Saeed of Jammata-ud-Dawa. I heard our own distinguished Home Minister tell the television channels today that we have given enough evidence to Pakistan to prosecute Hafiz Saeed and yet the Pakistan Home Minister says that India has given no evidence, they have freed Hafiz Saeed, there is nothing pending against Hafiz Saeed. The mastermind of the Mumbai attack has been let loose by Pakistan. No action is being taken against him. And we say that they will take all the action which is necessary.

Now I come to Balochistan. Now why on earth was Balochistan included? We have nothing to hide. Yes, of course, we have nothing to hide. We have nothing to hide, Madam, on many other issues. So, shall we put all those issues in a bilateral document where we have nothing to hide? Is this an argument that if we have nothing to hide, we will put it in the bilateral document? I was going through some of the newspaper reports just now because the Pakistanis now, at the official level, at the level of their Home Minister and the Prime Minister have started talking about Balochistan no sooner did the ink dry on this joint statement. And today, the Pakistani Home Minister has said that Pakistan will use the Balochistan reference to the hilt. He said that evidence of Indian involvement in Balochistan would be presented at international forums at the appropriate time. And they have seriously accused India of supplying arms to the Baluchs. They have accused India of using our Consulates in Afghanistan to train them and give the money and arms. This is the allegation, Madam, that Pakistan has been raising ever since those Consulates in Afghanistan were established. My distinguished colleague the former Foreign Minister Mr. Jaswant Singh is here. It was during his time that decision was taken that we would establish these four Consulates in Afghanistan. Since then Pakistan has been uncomfortable. I would like to tell the House, through you Madam, as Foreign Minister of India I travelled to Afghanistan and spent not two hours but two days in Afghanistan, and saw with my own eyes the kind of respect that the people of Afghanistan have for India. You have to go there to see this very palpable respect and love. उनका भारतीय लोगों के साथ बहुत प्यार मुहब्बत है। जहां-जहां

में गया, उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दिखाई और बहुत सम्मान किया, इसलिए हमें किसी पर निर्भर नहीं करना चाहिए। अफगानिस्तान और भारत में जो मित्रता है, वह टाइमटेस्टेड मित्रता है, वह सदियों की मित्रता है। इस मित्रता को कोई समाप्त नहीं कर सकता है, पाकिस्तान तो बिलकुल नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने जी तोड़ परिश्रम किया है कि भारत अपने कॉन्सोलेट्स को वहां बंद कर दे। उन्होंने अफगान सरकार से इसकी शिकायत की, प्रेजिडेंट करजई ने उसे स्वीकार नहीं किया, उसे नकार दिया। उन्होंने अमेरिकंस को जाकर शिकायत की, उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया, उन्होंने इसे नकार दिया। उसके बाद जब वे हार गए, तब उन्होंने हमारी काबुल अम्बेसी के ऊपर आतंकवादी हमला किया और हमारे लोग मारे गए, राजनयिक मारे गए, हमारे डिफेंस अटैशे मारे गए तथा दूसरे लोग भी मारे गए। दुनियाभर में इस बात की चर्चा हुई, क्योंकि इसके पीछे पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ था। सीआईए ने इंटरसेप्ट्स पकड़े। भारत सरकार के साथ उस सूचना को शेयर किया, जिसमें साबित हुआ कि हकानी का हाथ था, जो पाकिस्तान का टेरेरिस्ट है। उसे कहकर आईएसआई ने हमारे दूतावास पर हमला कराया। अब ज्वायंट स्टेटमेंट में बलूचिस्तान को ले आए और यह सारा मामला अब थमने वाला नहीं है। मेरा अगर कुछ भी अनुभव विदेश नीति के बारे में है, तो मैं चेतावनी के स्वर में इस बात को कहना चाहता हूं कि बलूचिस्तान भारत को आने वाले दिनों में बहुत तकलीफ देने वाला है। हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाएंगे, पाकिस्तान का प्रतिनिधि खड़ा हो कर हमारे खिलाफ बलूचिस्तान की बात उठाएगा और हम शर्मिदा हो कर उनके सामने झुकेंगे। आज ही बीबीसी पर मैंने देखा, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट अहमद रशीद का एक लेख है, जिस बात की तरफ कई लोगों ने इशारा किया, उसने बिलकुल साफ कहा है कि -



“When Pakistani and Indian leaders met in Egypt on 16th July, Prime Minister Yusuf Raza Gilani handed over an intelligence dossier to his Indian counterpart Manmohan Singh outlining India’s alleged role in destabilising Pakistan from Afghanistan. This included funding and training of Balooch militants for the separatist insurgency in Balochistan province, and providing support for the Pakistan Taliban, in particular its leader Baitulla Mehsud.”

मैं प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि जब वे इस डिबेट में इंटरविन करें, तो सदन को विश्वास में लेते हुए जरूर बताएं कि क्या उन्हें ऐसा कोई डोज़ियर मिला या नहीं मिला।

THE PRIME MINISTER (DR. MANMOHAN SINGH): I can categorically say no such dossier was ever given to me.

SHRI YASHWANT SINHA (HAZARIBAGH): I am happy. We will rather believe our own Prime Minister than any journalist. I raised this issue only because I wanted the Prime Minister to get up and state in this House that no such dossier has been given and we will say that the issue stands settled for the time being here.

SHRI PINAKI MISRA (PURI): Indeed, no such dossier exists. That is the point.

श्री यशवंत सिन्हा : बहुत चर्चा इस बात की हुई कि हमारे प्रधान मंत्री जी क्यों इस बात के लिए तैयार हो गए कि टैरिज्म और कम्पोजिट डायलॉग प्रौसेस लिंक नहीं होगा। In fact, the joint Statement says that they will not be linked and goes on to emphasise that they will not be bracketed. दुबारा उस बात को जैसे न कहा कि 'all issues and all outstanding issues' उसी तरह कहा कि  will not be linked and they will not be bracketed. Now, I have heard, because  the spin doctors of the Government had been at work और सलैक्टिव लीक मीडिया में होती रही है। बहुत तरह की बातें मीडिया के थ्रू आई हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि डीलिकड अगर हो गया, and they will not be bracketed तो आप इसे किस कंटैक्स्ट में पढ़ेंगे? क्योंकि जब एक ज्वाइंट स्टेटमेंट प्रधान मंत्री जी ने इसके पहले राष्ट्रपति मुशरफ के साथ 2005 में इशू किया था तो उसमें साफ तौर पर कहा गया था that terrorism will not be allowed to impede the peace process. हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसी दिन बयान जारी करके कहा कि इसका मतलब आप आतंकवादियों को आश्वस्त कर रहे हैं कि आप आतंकवाद करते रहो और हम बातचीत भी करते रहेंगे। वे खुद उस लाइन पर नहीं चल पाए, यह दूसरी बात है। डीलिक नहीं होगा। वह डीलिक हो जाएगा, उसके बाद हम यह कह रहे हैं कि all issues, including all outstanding issues जब आप ऑल इश्यूज कह रहे हैं तो उसमें ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज क्यों नहीं इंकलूडेड हैं? ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज से क्या मतलब है और अगर मुझे जरा भी इन चीजों का ज्ञान है तो मैडम, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब भारत पाकिस्तान के कंटैक्स्ट में आप ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज की बात करते हैं तो उसमें जम्मू-कश्मीर शामिल होता है और पाकिस्तानियों ने इस बात को स्पष्ट किया है। पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा है कि ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज का मतलब जम्मू और कश्मीर है। मुझे कोई एतराज नहीं है, कम्पोजिट डायलॉग में जम्मू और कश्मीर भी एक मुद्दा है। आप बात कीजिए। We have nothing to hide on Jammu and Kashmir also. लेकिन उससे बचकर स्पिन डॉक्टर गवर्नमेंट को यह बता रहे हैं कि बड़ा भारी अचीवमेंट हमारा हो गया। that the 'K'

word did not occur. बड़ा भारी अचीवमेंट हो गया तो आउटस्टैंडिंग इश्यूज क्यों लिखा है? With all humility I would like to ask the Prime Minister of India, the Prime Minister of the democratic, socialist, secular republic of India, why did he agree to call Pakistan, the Islamic Republic of Pakistan? Is India committed to islamisation of Pakistan?

कल अगर पाकिस्तान वाले खुद तय करें, we will become secular ... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: please sit down.

... (Interruptions)

SHRI YASHWANT SINHA : Is India committed, is India interested in Pakistan remaining Islamic all the time? क्या मतलब है? And, this is a statement, this sentence is not a joint statement, coming from the Prime Minister of India. इस बात को भारत के प्रधान मंत्री कहते हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हैं जिसमें हम कहते हैं पाकिस्तान। बहुत आगे बढ़ते हैं तो हम कहते हैं रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हम अपनी तरफ से कभी नहीं कहते हैं। वे कहें, हमें इसे कहने की क्या जरूरत है।... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please sit down.

... (Interruptions)

श्री यशवंत सिन्हा : महोदया, पाकिस्तान इन्फार्मेशन शेयरिंग है कि टेररिज्म के बारे में हम एक दूसरे के साथ रियल टाइम क्रेडेबल इन्फार्मेशन शेयर करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यही तो नीयत थी जब हमने हवाना में कहा कि हम ज्वाइंट टेरर मेकेनिज्म बनाएंगे। पाकिस्तान के साथ कम्पोजिट डॉक्यूमेंट में टेररिज्म भी एक मुद्दा है। दोनों मुल्कों के होम सैक्रेट्री समय-समय पर मिलते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। इससे भी संतुष्ट न होते हुए प्रधानमंत्री जी ने हवाना में वर्ष 2006 में अलग से दोनों मुल्कों के बीच ज्वाइंट टेरर मेकेनिज्म बनाया। अब हम 2006 से 2009 की बात कर रहे हैं, क्या इन तीन वर्षों में दोनों मुल्कों के बीच रियल टाइम क्रेडेबल इन्फार्मेशन शेयरिंग नहीं हुआ? हमारे पास अमेरिकन दस्तावेज हैं जिसमें अमेरिकन्स ने कहा है कि वे इसमें एम्पायर की भूमिका निभा रहे हैं, इन दोनों देशों की इन्टेलिजेंस एजेंसियों को साथ ला रहे हैं और इन दोनों के बीच जब मतभेद होता है तब वे इसमें जज का काम करते हैं, इसके साथ वे एन्श्योर कर रहे हैं कि दोनों देशों की इन्टेलिजेंस एजेंसियां साथ मिलकर काम करें। जब सितंबर में यूएन जनरल असेम्बली का सेशन होगा तब दोनों देशों के विदेश मंत्री आपस में मिलेंगे। लेकिन इससे पहले ही हम कह रहे हैं - the Foreign Secretaries will meet as often as necessary. अभी जुलाई खत्म

हो रहा है, अगस्त का एक महीना बचा है। सितंबर में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग होगी लेकिन as often as necessary कितनी बार मिलेंगे? पांच बार मिलेंगे? दस बार मिलेंगे? क्या बात करेंगे?

महोदया, मैं बहुत गंभीरता के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट शर्म अल-शेख में इश्यू हुआ, शायद इसकी स्याही भी नहीं सूखी होगी जबकि दोनों प्रधानमंत्रियों ने उस स्टेटमेंट को चिथड़े-चिथड़े करके फेंक दिया। शायद दुनिया में दो देशों के बीच ऐसा कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं हुआ होगा जिसका इन्टरप्रेशन इतना वाइडली अपार्ट है जैसा कि प्राइम मिनिस्टर गिलानी और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने किया। प्राइम मिनिस्टर गिलानी ने बाहर निकलते कहा -

“It is a great diplomatic victory for Pakistan.”

I heard it with my own ears. He came out and said that it was a great diplomatic victory for Pakistan. He interpreted the Joint Statement to mean that India had agreed to revive the composite dialogue process. हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा जब वे शर्म अल-शेख में मीडिया को मिले। शायद इनको जाकर किसी ने बताया होगा पाकिस्तानियों ने लीड ले लिया है, आप भी मीडिया को मिलिए। ये मीडिया को एक घंटे के बाद मिले और कहा -

“Unless and until the terrorism is tackled and terror infrastructure dismantled, I will not be able to carry public opinion with me.”

You are absolutely right Mr. Prime Minister. The public opinion in India will not be with you unless you hold Pakistan to these two issues – terrorism must end and the infrastructure of terrorism must be destroyed in Pakistan for ever. ये सब कुछ हो गया, लेकिन फिर क्या हुआ? जब यहां देश में इस बात की चर्चा शुरू हुई कि प्रधानमंत्री जी शर्म-अलशेख से क्या करके आ गए तब सरकार के स्पिन डॉक्टर एक्टिव हो गए। ... (व्यवधान) अब हमारे विदेश राज्य मंत्री यहां बैठे हैं, बहुत अनुभवी हैं। इनसे ज्यादा डिप्लोमेसी में अनुभव किसका होगा? इन्होंने यूनाइटेड नेशन्स में काम किया है। यूनाइटेड नेशन्स में तो खाली डिप्लोमेसी होती है। इन्होंने क्या कहा -

“No, no. This is only a diplomatic paper and not a legal document. Dismiss it as a diplomatic paper.”

This was a Joint Statement. यह सरकार पहले तो भूल गई थी, लेकिन अब जनवरी 6, 2004 के उस स्टेटमेंट की दुहाई देती है, जो प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय इश्यू हुआ था, जब वह इस्लामाबाद सार्क समिट के लिए गए थे। Let me remind him that this was only a Joint Press Statement. It was not even a Joint Statement. What was issued in Islamabad on



January 06, 2004 was a Joint Press Statement और आज आप ही की सरकार उसकी दुहाई देती है, जब मैंने प्रधान मंत्री जी को कोट किया, जब उन्होंने कहा Pakistan's territory should not be allowed to be used. What was the language? That language was in that January 06, 2004 statement. मुझे यह कहते हुए अफसोस है। फिर किसी पदाधिकारी ने कहा कि यह बैड ड्राफ्टिंग है और मामला यहीं पर नहीं रुका, उन्होंने कहा बैड ड्राफ्टिंग है, These things happen. Bad drafting and these things happen; it is not a legal document; it is only a diplomatic paper. तो मैं चाहता हूँ कि सरकार उठकर इस सदन में आज बोल दें कि हम नहीं मानते, वह बैड ड्राफ्टिंग है।

अब जो भी हुआ, जो भी परिस्थिति थी। लेकिन विदेशी मामलों का मेरा जितना अनुभव है, मैं इतना कहना चाहूँगा कि जब ड्राफ्टिंग होती है और खासकर जब समित मीटिंग्स होती हैं तो ड्राफ्ट अचानक तैयार नहीं हो जाता। ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए बहुत समय लगाया जाता है। ड्राफ्ट के एक-एक शब्द को देखा जाता है। ड्राफ्ट में कोमा, फुल स्टॉप कहां है, उसे भी देखा जाता है और हर चीज पर ध्यान देने के बाद ही ड्राफ्ट फाइनलाइज होता है। फिर किस तरह ड्राफ्ट बना। मैंने किसी अखबार में पढ़ा, फिर स्पिन डाक्टर्स के सहारे, कि नहीं, नहीं, वहां तो दोनों प्रधान मंत्री कुछ समय के लिए मिले, उसके बाद दोनों देशों के विदेश सचिवों को बुलाकर कहा कि हम लोगों की यह बातचीत हो गई है, अब इस पर ड्राफ्ट कर लो और दो घंटे दोनों विदेश सचिव बैठकर ड्राफ्टिंग करते रहे। विदेश मंत्री जी कहां थे, मुझे पता नहीं। लेकिन दोनों ड्राफ्टिंग करते रहे और उसके बाद उन्होंने अपने-अपने प्रिंसिपल्स को ड्राफ्ट दिखाया होगा और तब ड्राफ्ट अप्रूव हुआ होगा। मुझे भी वर्ष 2004 के ड्राफ्ट का कुछ अनुभव है और मैं इस सदन में जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि जब इस तरह का फाइनल ड्राफ्ट श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सामने आया तो उन्होंने एक-एक लाइन, एक-एक शब्द पढ़ा और उसके बाद उसमें अमैन्डमेंट सजैस्ट किया। इस-इस वाक्य को इस वाक्य के पहले ले जाओ और जो लोग बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर वे लोग नहीं माने तब, हम लोगों के इस्लामाबाद से जाने का समय हो रहा था और प्रधान मंत्री, श्री वाजपेयी ने कहा कि अगर वे मानेंगे तो यह इश्यु होगा और नहीं मानेंगे तो हम घर जायेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि कोई स्टेटमेंट जारी हो। कोई जरूरी नहीं है कि हर मीटिंग के बाद कोई स्टेटमेंट जारी हो और हमें सूट नहीं करता है, हम स्टेटमेंट जारी नहीं करेंगे। हम लोगों ने आगरा में स्टेटमेंट नहीं किया। नहीं हुआ, नहीं हुआ, बातचीत हुई, नतीजा नहीं निकला, स्टेटमेंट जारी नहीं होगा तो प्रधान मंत्री जी ने कहा I am prepared to walk more than half the

distance. I am saying he has walked all the way.* He has gone to the Pakistani camp and acted exactly as they said. Where is the half way? ... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Hon. Member, you may take your seat for a minute. There is a point of order.

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam Speaker, I would like to quote Rule 353 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.


It says:

“No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a Member against any person unless the Member has given (adequate advance notice) to the Speaker and also to the Minister concerned so that he Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply:”

मैडम, यह कह रहे हैं कि ... (*Interruptions*) * पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान में कौन जा रहा है?

It should be deleted.

MADAM SPEAKER: Hon. Member, I have to look into it. You have made your point.

... (*Interruption*) 

 MADAM SPEAKER: Shri Sinha, please continue.

... (*Interruptions*)

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, मैं इस मामले पर प्रधानमंत्री जी से चन्द सवाल करना चाहता हूँ।

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I will look into it.

... (*Interruptions*)

SHRI YASHWANT SINHA : I want to put some questions to the hon. Prime Minister and I hope he will be good enough to answer them. The first question is this. Firstly, has the trust deficit between India and Pakistan, after the

* Expunged as ordered by the Chair.

Joint Statement and meeting, widened or narrowed? Secondly, what changed between 16th June, when he met President Zardari, and 16th July, when he met Prime Minister Gilani at Sharm El Sheik? What has brought about this complete change of heart? What has happened? Thirdly, Pakistan has already gone to town on Baluchistan. But the Prime Minister has said that there was no dossier given. So, I am not asking that question. Then, what are the achievements of the anti-terror mechanism set up after 2006 in Havana? The Prime Minister has said it in his Joint Statement of 4th April, 2005. It was a ringing statement saying that the peace process between India and Pakistan was now irreversible. Does he stand by it now, that the peace process between India and Pakistan is irreversible and that they will go on doing what they like? फिर भी यह चलता रहेगा? पाकिस्तान के मसले पर मैं प्रधानमंत्री जी से बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा कि इतिहास की शुरुआत सन् 2004 से नहीं हुई जिस दिन वह प्रधानमंत्री बने। भारत-पाकिस्तान संबंधों का एक लम्बा इतिहास है। मेरा कहना है कि जो भी इन लम्बे संबंधों के डगर हैं, ठहराव हैं, मुकाम हैं, उन्हें इग्नोर करके चलेगा, तब भी उसे कभी भी सफलता नहीं मिलेगी।

अध्यक्ष महोदया, प्रधानमंत्री जी ने मुशर्रफ साहब से बात की, हमने भी की। मुशर्रफ साहब जब राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी - "In the Line of Fire". आप इस पुस्तक को पढ़िये। As President of Pakistan, he is writing that book and let me tell you, when I went through that book, the feeling that he has about India. भारत उनका शत्रु देश है। ऐसा उन्होंने ने पचास जगह पर लिखा है कि भारत हमारा शत्रु देश है I gave them a bloody nose here; Kargil was a great success. आप इस तरह के लोगों से डील कर रहे हैं ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Whatever is unparliamentary in the hon. Member's speech may be deleted.

... *(Interruptions)*


श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, मैं प्रधानमंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि जो शर्म-अल-शेख में हुआ है, सातों समुद्र का पानी इकट्ठा करके अगर उस शर्म को धोने का प्रयास हम लोग करेंगे तो वह शर्म नहीं धुलने वाली है। All the waters of Neptune will not wash away the shame of Sharm-el-Sheikh.... *(Interruptions)* अध्यक्ष महोदया, इंडिया टुडे में बहुत से लोगों ने लिखा है। लेकिन इंडिया टुडे ने इस सरकार का इतना समर्थन किया, इतना समर्थन किया कि हमारे जैसे लोग न्युकलीयर

डील के मामले में परेशान हो गये थे। इश्यू ऑफ्टर इश्यू वे न्यूक्लियर डील में सरकार का समर्थन करते रहे। इंडिया टुडे ने अपने लेटेस्ट अंक में फ्रंट पेज पर टिमिड इंडिया कहा है। इसमें अंदर की तरफ लिखा है कि “As a result of the surrender at Sharm-el-Sheikh, the impression has gone out that India is negotiable” This is what they have said.

महोदया, इसके बाद प्रधानमंत्री जी इटली में लाकिला गये। इसमें दो इश्यू हैं, एक क्लाइमेट चेंज का इश्यू है, मैं अभी प्रश्न काल में सुन रहा था और श्री जयराम रमेश जी ने कहा कि हम क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शंस को स्वीकार नहीं करेंगे, कैप्स को स्वीकार नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ कि जो दो डिग्री सेल्सियस कम करने की बात हुई है, वहां तक लिमिट करने की बात हुई है और दूसरी बात पीकिंग की हुई है, It must peak.

महोदया, मैं आपके माध्यम से थोड़े शब्दों में सदन में कहना चाहता हूँ कि आज *per capita* emission of green house gases in the US is 20 tonnes. भारत का स्थान पर-कैपिटा-एमीशन में 137वां है। अगर आप इसके ऊपर कैप स्वीकार कर लेंगे कि प्रतिबंध लगे under that peaking formula, we will be limited to only three tonnes. इसीलिए मैं चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी इस सदन में खड़े होकर आश्वस्त करें कि भारत किसी भी परिस्थिति में प्रतिबंध को स्वीकार नहीं करेगा। कोपनहेगन में जब क्लाइमेट चेंज का कांफ्रेंस होगा तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस सदन को सूचना देना चाहता हूँ कि अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ऑलरेडी इस संबंध में एक कानून पास कर दिया है। जिसके अंतर्गत जो देश अमेरिका के स्टैंडर्ड पर नहीं चलेंगे, उन देशों की उन वस्तुओं के ऊपर जो अमेरिका को निर्यात होंगी, वे प्यूनितिव टैरिफ लगायेंगे। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स को यह अधिकार दिया गया है, वह बिल सीनेट से पास होगा और उसके बाद लॉ बन जाएगा। आज मैं इस सदन के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर सरकार ने इस इश्यू पर झुकने का काम किया तो हम इस इश्यू पर भी सरकार को आड़े हाथों लेंगे।

महोदया, इसके बाद न्यूक्लियर डील के बारे आया कि ENR – Enrichment and Reprocessing Technology हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। हमारे नेता सदन यहां बैठे हैं, इन्होंने दूसरे सदन में बयान दिया कि we are not deeply concerned तो किसी अखबार वाले ने पूछा कि “Are you mildly concerned? Are you casually concerned if you are not totally concerned? Are you moderately concerned?” लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि, इस पर बहुत बहस हुई जुलाई 2008 के बाद, जब इसी सदन में पिछली सरकार ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, जैसे हम सब लोगों ने न्यूक्लियर डील को भूलने का काम किया। न्यूक्लियर डील के ऊपर चर्चा ही नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ने कहा

था कि वह पार्लियामेंट के सामने आएंगे, वे नहीं आए। हमने किसी ने चर्चा नहीं मांगी और इसलिए हम भूल गये कि हमारा जो वन-टू-थ्री एग्रीमेंट यूएस के साथ हुआ था, जब वह अमेरिका में कानून बना तो उस कानून में सैक्शन 204 में बिल्कुल साफ लिखा है कि भारत को अमेरिका इनरिचमेंट और रीप्रोसेसिंग टैक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स नहीं देगा। इसके बाद यह भी लिखा है कि वह एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के साथ काम करेगा ताकि कोई और दूसरा देश वह टैक्नोलॉजी और इक्विपमेंट भारत को न दे पाए। अब यहां पर अपने डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं कि नहीं, नहीं हम री-प्रोसेस करेंगे। प्रधानमंत्री जी फ्रांस गये, यहां खबर छपी कि प्रेसीडेंट सरकोजी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि हम फ्रांस से जो फ्यूल लेंगे, उसे वह री-प्रोसेस कर सकते हैं, रूस से कर सकते हैं। री-प्रोसेसिंग का सवाल नहीं है, सवाल है **technology and equipment for the reprocessing**. हम अभी तक जो अपना फ्यूल खर्च करते रहे हैं, उसका री-प्रोसेसिंग तो करते ही हैं। अमेरिका ने सिर्फ यह कंडीशन लगाई है कि अमेरिका से हम जो लेंगे, उसके लिए हमें एक विशेष संयंत्र बनाना पड़ेगा। हम अपने इक्विपमेंट से, अपने पैसे से, अपनी टैक्नोलॉजी से उसको बनाएँगे और उसके बाद वह हमें परमीशन देगा या नहीं, यह आगे की बात है। यह बिल्कुल साफ है कि नॉन एनपीटी मुल्क जिसमें भारत है, उसको किसी भी हालत में नहीं दिया जाएगा। इसमें इन्होंने खुद कहा जब ये अमेरिका गए और उस समय के राष्ट्रपति बुश के साथ इनकी शायद अंतिम मुलाकात हुई, तो सदन को याद होगा, उन्होंने कहा -  “The people of India love you, Mr. Bush.” वही मिस्टर बुश ने जब 10 सितम्बर को अपना प्रेज़ीडेंशियल रिकमंडेशन भेजा, उसमें उन्होंने कहा - हम नहीं देंगे भारत को सेंसिटिव टैक्नोलॉजी। कोंडेलीज़ा राइस ने सदन की जो हाउस कमेटी है फॉरेन अफेयर्स की, हाउस ऑफ रेप्रेज़ेन्टेटिव्स की, उसके अध्यक्ष हार्वर्ड बैरमैन को यह एश्योरेंस दिया - **There is not only no question of transferring the technology to India, but we will work with the NSG to make sure that the NSG puts a ban.** एनएसजी में जितने 45 मैम्बर्स हैं, उसमें चीन को छोड़कर इन्हीं आठ देशों के पास यह कैपेबिलिटी है कि वह टैक्नोलॉजी और इक्विपमेंट दे सकते हैं। उन्होंने मना कर दिया। एनएसजी में अभी सहमति नहीं हुई है, लेकिन लाक्विला, इटली में जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, उसमें इन्होंने उसको मना कर दिया। क्या हम कहें कि अमेरिका दोषी हैं? नहीं। क्योंकि अमेरिका ने बराबर स्पष्ट किया है, हम लोग भी बराबर स्पष्ट करते रहे। प्रधान मंत्री जी दोनों सदनों में खड़े होकर कहते रहे - **full civil nuclear cooperation and trade**, इन्होंने कहा नहीं मानेंगे, अगर इस तरह का प्रतिबंध लगेगा। मेरे पास उनके सारे स्टेटमेंट्स हैं जो उन्होंने दोनों सदनों में दिये हैं। मैं क्या कहूँ? मैं इतना ही कह सकता हूँ बहुत दुख के साथ कि प्रधान मंत्री जी ने

जितने प्लैजेज़ दिये दोनों हाउसेज़ को, उसको तोड़ने का काम उन्होंने किया है, he has not been able to keep those promises. ...(व्यवधान)

महोदया, अंतिम मुद्दा मैं उठाना चाहता हूँ। इस सदन में मैंने उठाया था end use से जो एग्रीमेंट हुआ था। End use से एग्रीमेंट हमने क्यों किया यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। उस दिन विदेश मंत्री जी सदन में आए। जो स्टेटमेंट इन्होंने किया, उसमें सिर्फ दो वाक्य हैं End use एग्रीमेंट के बारे में, मॉनीटरिंग एग्रीमेंट के बारे में। हम जितने अंधकार में पहले थे, उतने ही अंधकार में आज भी हैं। इसलिए मैं प्रधान मंत्री जी से और विदेश मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जब वे जवाब देने के लिए खड़े हों तो सदन को विश्वास में लेते हुए बताएँ कि End use से एग्रीमेंट में उन्होंने अमेरिका के साथ क्या किया है? इसी बीच में फिर स्पिन डॉक्टर्स गवर्नमेंट के चालू हो गए। चालू हो गए तो उन्होंने क्या कहा - एनडीए जब शासन में थी तो हमने भी अमेरिका से वैपन लोकेटिंग राडार्स खरीदे थे। उसमें मीडिया में यहाँ तक कहलवाया गया कि उसमें End use से एग्रीमेंट लगा हुआ है। यह भी कहा गया कि अमेरिकन इंस्पेक्टर्स ने आकर यहाँ पर उन राडार्स की जाँच भी की। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, मेरे पास सरकारी फाइलें नहीं हैं, आपके पास सरकारी फाइलें हैं, कृपया खड़े होकर स्पष्ट करें कि जब हमने वैपन्स लोकेटिंग राडार 2002 में अमेरिका से खरीदा तो क्या उसमें End use से एग्रीमेंट था? मेरी सूचना है कि नहीं था। आप सदन को गुमराह करेंगे तो मेरे पास उस दस्तावेज़ की कॉपी है। मैं बता दूँगा कि क्या लिखा है। समझे? ...(व्यवधान) इसलिए आप यहाँ पर ज्यादा हल्ला-गुल्ला मत कीजिए। ...(व्यवधान) इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि क्या किया है, सदन को विश्वास में लीजिए। End use से एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एन्डयूस एग्रीमेंट, क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर डील और पाकिस्तान, चार जो बड़े-बड़े खम्भे थे, जिस पर हमारी विदेश नीति टिकी हुई थी, वह मेट्रो की तरह ध्वस्त हो गई है। मेट्रो को उठाने के लिए कंक्रीट का पिलर तो फिर से खड़ा किया जा सकता है, लेकिन विदेश नीति का पिलर, जिस पर इस देश की प्रतिष्ठा टिकी हुई है, वह अगर गिर जाए तो हमारी प्रतिष्ठा गिरती है।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Do not interrupt. Please sit down.

श्री यशवंत सिन्हा : महोदया, मैं यह कहना चाहता हूँ कि विदेश नीति में इतनी भयानक भूल, इतने कम समय में, शायद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई है that within such a short period of time, we have piled up one mistake after another. I do not know where the foreign policy of India today is.

SHRI P.C. CHACKO (THRISSUR): Madam Speaker, we have been waiting with great attention and interest that the senior leader of the main Opposition Party, an experienced foreign policy expert and former External Affairs Minister, will throw some light on the issue which we are discussing.

Madam, I must say that Yashwant Sinha Ji, with all his experience and information in his hands and the articulation, could not prove the point which he was arguing. He has been always an expert in arguing weak cases but today he has miserably failed in his attempt.

I feel that, at least, he will justify his own Party's programme of *Padyatra* from Parliament to Rashtrapati Bhavan yesterday. We thought that he would be able to justify that *Padyatra*. Not only that Yashwant Sinha Ji has disappointed this whole House but he has disappointed his own Party men. I have been watching the faces of his colleagues sitting at the back and the pale of gloom on the faces of his colleagues is an ample proof that Yashwant Sinha Ji could not even convince his own Party colleagues.

Madam, I legitimately expected that like Mr. Jaswant Singh, the other day, had complimented our Finance Minister, after these allegations which they have to do as a ritual to justify their stand, finally he will come out with, at least, a word of compliment to our hon. Prime Minister. Even that he did not do. I am really sorry about it.

Madam, he has seen some cracks in the pillars on the Metro Rail here, which we have all seen. He has seen some cracks in our foreign policy pillars also, which none of us are able to see those cracks in the foreign policy pillars... (*Interruptions*) Madam, there was something which also I will tell them and if they are interested they should patiently listen to it.

Madam, the foreign policy pillars of this country were not shaken when the hon. Prime Minister went to Sharm-el-Sheikh but when the former Prime Minister went in a bus from here to Lahore. When he reached Lahore, at that point of time,

our foreign policy pillars were shaking because in Kargil the Pakistani soldiers were infiltrating into India.

Madam, he has rightly said that Mumbai Attack was an attack on the sovereignty of India. Yes, we do agree. That was reiterated in clear terms by the Prime Minister in this Joint Statement – I will read that wording later. But Madam, there was another attack, which we, sitting here in this House, cannot forget. This happened in 2001 when Shri Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister of this country. Hon. Advani *ji* was the Home Minister of this country. This very citadel of the Indian Parliament was attacked. ... (*Interruptions*) It is good to remember Bombay. We will always remember Bombay... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please listen to him.

... (*Interruptions*)

SHRI P.C. CHACKO : But, when this Parliament was attacked... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down. Please listen to him.

... (*Interruptions*)

SHRI P.C. CHACKO : As once said by our hon. Prime Minister, the *lohpurush*, the strong man of BJP, was sleeping when he was the Home Minister and when this Parliament was attacked. It was an eye ball to eye ball fight. It was almost a war on India.

15.56 hrs.

(Shrimati Sumitra Mahajan *in the Chair*)

What happened after the Parliament attack? Then happened the Agra Summit. Yashwant Sinha *ji* is against any dialogue with Pakistan. Is that the position of India? Is that the position of this country that we will not talk to Pakistan, we will not talk to any other country? Sorry, Yashwant Sinha *ji*, that is not the position of this country. We are for the dialogue in the country and your Prime Minister with all fanfare went to Agra for discussion. What happened there? President Musharraf came to Agra. You hosted him and he was taken around Taj Mahal. The whole country was watching. He went back without signing a joint

declaration. He went back accusing India. That is what happened there. The Agra conclave was held in the background of the attack on the Parliament. Please do not forget this. You may be quoting many instances; there are umpteen instances we can quote that you never had the self-respect when you raised the issue with Pakistan. You were never bold enough to speak to them in the language in which the Prime Minister is speaking. I would like to quote:

“Prime Minister Singh reiterated the need to bring the perpetrators of the Mumbai attacks to justice. Prime Minister Gilani assured that Pakistan will do everything in its power in this regard.”

Has Pakistan ever agreed or ever come to these terms in the past? Can Yashwant Sinha *ji* tell us? Pakistan was always saying that we have nothing to do with the Bombay attack. Pakistan was always saying that Kasab is not a citizen of Pakistan. Pakistan was always saying: “Why should we bother about it? We have nothing; we are not going to do any inquiry.” When our Prime Minister said that the perpetrators of that crime should be brought to book, what was the reaction of Mr. Gilani? Yashwant Sinha *ji*, you please accept, when the Prime Minister of this country talked in unmistakable terms, what is the sentiment of this country? ...

(Interruptions)

सभापति महोदयः आप अपने ही व्यक्ति को डिस्टर्ब कर रहे हैं।

... *(Interruptions)*

SHRI P.C. CHACKO : Madam Chairman, it is all the more interesting. They are speaking in the name of the people... *(Interruptions)* Hon. Yashwant Sinha *ji*, the Spokesperson of the principal Opposition Party, I request the BJP Members to at least see how they pick up courage to speak on behalf of the people. It is a party which even elected a Prime Minister before the election. No other party has ever elected a Prime Minister before the election. But they were outright rejected by the people. Such a party is coming and is today speaking on behalf of the people. Here a Prime Minister is sitting who was elected by the people... *(Interruptions)*

I am not yielding. Here a Prime Minister is sitting who has got the support of the people of this country. There is a person who spoke on behalf of the BJP which is a party rejected by the people. With what courage you are speaking on behalf of the people?

16.00 hrs.

So, please do not speak on behalf of the people; speak on behalf of you.

Madam, there were some instances. I am not going into the details. When the BJP Government went to discuss with the President Musharaf in Agra, those days there was an interesting inside story in the BJP. Madam Chairperson, you may also be knowing about that. The Home Minister of this country was not aware of what was going to happen in Agra. That was the talk in those days. Shri Advani's view was that he was not aware of what was happening in Agra. Finally, insulting this country, Musharaf went from Agra issuing a statement against this country. These are all facts. ... (*Interruptions*)

SHRI YASHWANT SINHA : Shri Advani was present in Agra at that time. आप क्या बोल रहे हैं।... (व्यवधान)

सभापति महोदया : आप बैठिए। आप अपने टाइम पर बोलिए।

... (व्यवधान)

MADAM CHAIRMAN : Shri Chacko, you will have to conclude now.

... (*Interruptions*)

SHRI P.C. CHACKO : Madam, please tell them not to disturb me. Even senior Members are disturbing me. What to do? ... (*Interruptions*)

I now come to the point about the composite dialogue; that is the main point which Shri Yashwant Sinha was explaining. About the dialogue, our position is that we are for the dialogue. As to when the composite dialogue should start, we have made it very clear. It should not be linked to the composite dialogue; that is what they have complained. 'Linked to the composite dialogue' means what? Madam, one can have a simple reading and even a reading between the lines. It is not that

Shri Yashwant Sinha ji cannot understand this. He is distorting and misleading this House. Madam, what is happening is that whether there is dialogue or no dialogue, we want Pakistan to take action. That is the meaning of this sentence. We want Pakistan immediately to proceed with anti-terrorism actions. Against terrorism, any action cannot wait. Pakistan should take action against terrorism. So, we want Pakistan to take action against terrorism. India and Pakistan have jointly declared that every step will be taken by both the countries against terrorism. That means, the composite dialogue will take place at some point of time. We will decide the time; we have to decide and we will decide when we start the dialogue. At the same time, we are for the dialogue. This is made very clear.

Madam, you see the action taken by Pakistan. Pakistan initially refused to admit that it is their citizen who created the problem in Mumbai. Now, you see what they have done. Madam, there is a diplomatic success of the Prime Minister and the Foreign Minister of this country. Why do they not admit that? Shri Yashwant Sinha is a former External Affairs Minister and also a former bureaucrat.

Madam, what is happening in this field? Pakistan has arrested five terrorists who had links with the Mumbai incident. Those terrorists are going to put to trial in Pakistan. We are not happy and we are not satisfied with that. Our Prime Minister has told Pakistan in unambiguous terms that you book everyone with this incident of Mumbai, until then we are not happy. Now, the process has started. Pakistan is on the defensive. Till now, they were saying that Pakistan has nothing to do with that. Now, they have admitted and said: "Yes, Kasab is a citizen of Pakistan. We have booked five of them. We are continuing with the inquiry." Whose success it is? Shri Yashwant Sinha should say that.

Madam, the then BJP Government could not even achieve one-tenth of what this Government is achieving today. Madam, at the same time, I still want to reiterate that India has got a position; India has got a very firm position. For your information, I want to say that India will go for the composite dialogue only when Pakistan is taking concrete action to book all the culprits behind the incident in

Mumbai to the satisfaction of this country. It is our prerogative to fix the time for the composite dialogue, and we will decide that.

Madam, there is some very interesting reference that is being made; a reference about Baluchistan. Shri Yashwant Sinha has said that a reference about Baluchistan has never been mentioned in the Statement in the history of this country. He said that after the discussion, the Statement has mentioned about Baluchistan, and this he said as if the whole sky is going to fall down; he wanted to know why Baluchistan has been mentioned in that.

Madam, Baluchistan is an internal affair of Pakistan. If Pakistan wants to mention about Baluchistan, why should we oppose it? I do not understand the logic of his argument. He also said that Kashmir should not be a part of an international dialogue and discussion. It is our internal affair. We fought it like anything. I think, Yashwant Sinhaji also might have taken that line when he was holding responsible positions, that Pakistan cannot be mentioned in an international document. We did not allow Kashmir to be mentioned in this document. But Balochistan is mentioned in this document. Okay; it is Pakistan's internal affair. If it is brought into the text, it is not going to affect us in anyway. We have not contributed; we have not talked with them. It is not binding on us. If the Pakistani Prime Minister feels that he has some information about Balochistan, okay, let him give us the information. Let whatever information may come. We condemned terrorism in any form, in any part of the world perpetuated by anybody in unmistakable terms. That is the message of this text.

At the same time, merely mentioning Balochistan is not everything. Who is teaching us lessons on patriotism? I am sorry – before also I said it in this House – that the then External Affairs Minister of the BJP-led Government escorted a dreaded terrorist in a special flight to Kandahar... (*Interruptions*)

How soon do you forget this? Shahnawaz Hussainji, how can you forget it?... (*Interruptions*) The people would never forget it... (*Interruptions*) After the attack on our Parliament, you were celebrating in Agra! After you escorted a

dreaded terrorist to Kandahar, now you are blaming the Congress! Please, we do not need any lesson from the BJP on patriotism.

Madam, it was raised as to why the hon. Prime Minister has agreed that Pakistan is an Islamic country. It is very interesting. According to the Constitution of Pakistan, Pakistan is an Islamic Republic... (*Interruptions*) You may agree; you may not agree but that is part of the history.

Yashwant Sinhaji, do not find fault with anything and everything. You are a senior person. We still respect you for certain things. Only you are a convert to BJP; you are not originally a BJP man... (*Interruptions*) How can you find fault with each and everything?

Madam, what is happening in the neighbourhood? Our relations with Bangladesh, our relations with Bhutan, our relations with Nepal, our relations with China, our relations with Sri Lanka are cordial. In and around -- you were also sitting in that Chair -- what is the position today? What we achieved in the last 365 days, you would not have achieved even one-tenth of that in 10 years time – I can challenge you... (*Interruptions*)

About the Statement, I am happy and I am thankful to you that you have raised this issue. You made an exercise in vain, doing a *Padyatra* from here to Rashtrapati Bhavan. Hon. Rashtrapatiiji might be very much amused that you had made this representation. But you cannot befool the people of this country. You may try. You may still go on trying ... (*Interruptions*)

SHRI YASHWANT SINHA : Please, do not bring Rashtrapatiiji here... (*Interruptions*)

SHRI P.C. CHACKO : But in the recent General Elections also, after having this verdict, if you are not convinced, nobody can help you. Even God cannot help you because you do not know the psychology of the people of this country... (*Interruptions*)

Madam, the core issue is that we want to see that Pakistan behaves as a responsible nation. We have made it very clear to Pakistan that Pakistan should

behave properly. I cannot think of a better wording. They said about poor drafting, good drafting, etc. Those who were good draftsmen in the past can say that, but today, this is containing the exact warning that India should give to our neighbours when they are misbehaving. We want them to behave. That is the message given to them.

This Statement is only a routine thing. Indeed, in such international meetings, joint statements are being issued. There is nothing new in it. But we are happy that a Statement has come out. We are happy that Pakistan has agreed to their responsibility. We are happy that Pakistan has agreed— whether they would do it or not, is a matter to be seen... (*Interruptions*) Composite dialogue is an agenda for the future. We would decide the timing.

Action against terrorism is an immediate issue, which we have already said. They are making a hill out of a mole. They are trying to create a wrong impression. They are trying to distort. They are trying to create a misunderstanding among the people. I think, at this late hour, the BJP would realize their folly and they would withdraw from this kind of misleading campaign.

With these words, I conclude.

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : सभापति महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आज आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। प्रत्येक देश की विदेश नीति होती है और उसमें सर्वोपरि है राष्ट्र का हित। दूसरी बात, जितने ज्यादा से ज्यादा देश हमारे मित्र बन सकें, वह सफल विदेश नीति होती है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी अपना बयान देंगे, तब स्पष्ट हो जाएगा कि सच्चाई क्या है? लेकिन देश और आम-जनता में संदेश चला गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ कि आप कितनी भी सफाई दें, लेकिन गलत संदेश चला गया है कि पाकिस्तान के साथ जो बातचीत हुयी, वह दबाव में हुयी। ...(व्यवधान) मैं कहना कोई और शब्द चाहता था, लेकिन ठीक है, दबाव में हुयी। हम इतना जरूर कहेंगे कि जो विदेश नीति है, जो स्थापित हुयी है, उससे आप हटे तो जरूर हैं, क्योंकि या तो इतनी कड़ाई के साथ आपने सामयिक बयान न दिया होता, जिस कड़ाई के साथ आपने कहा कि हम कोई बातचीत नहीं कर सकते, जब तक कि जो आतंकवादी हमारे यहां आए, जिन्होंने मुंबई में निर्दोष लोगों की हत्याएं कीं, हमला किया, जब तक पाकिस्तान उनको सजा नहीं देता या उन्हें हिंदुस्तान के हाथ में पकड़कर नहीं देता है। यह मांग पूरे देश की, पूरे सदन की और आपकी खुद की थी।

सबसे पहला सवाल यही है कि बातचीत क्यों हुयी? जब आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गयी, जैसी करनी चाहिए थी और इसके बाद उन्होंने उनको आपके हवाले नहीं किया, तो पहले ही सोच-समझकर बयान देना चाहिए था। आप बयान से पलटे हैं। आप बयान से पलट गए, उससे ठीक उलटा हो गया और पाकिस्तान से बातचीत हो गयी। यह बातचीत क्यों हुयी, किस शर्त के आधार पर हुयी?

दूसरी बात यह है कि कितनी गलतियां होंगी? क्या ईरान के संबंध में गलती नहीं हो रही है? आज हम आपको सावधान करना चाहते हैं। आप जरा इतिहास पढ़िए कि ईरान ने कब हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया? जब यूएनओ में हम अकेले पड़ गए थे, तब अकेले ईरान हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ था। लेकिन उस ईरान के साथ क्या आपने बात की? विदेश नीति में, अपने देश के मित्र बनाने की बहुत सारी बातें होती हैं। अमेरिका के साथ जो आपकी बातचीत हुयी, क्या ईरान के संबंध में उससे कोई बात हुयी? ईरान पर अमेरिका घात लगाए बैठा हुआ है, जैसा उसने ईराक के साथ किया। इसलिए आप भी कम दोषी नहीं हैं। ईराक के मामले में हम इसी सदन में थे और बहुत मजबूती के साथ हम खड़े रहे थे। कई नेताओं की और विपक्ष की बातचीत दादा सोमनाथ चटर्जी के चैंबर में हुयी थी। उस समय आप निंदा नहीं कर सके। कुछ और नहीं कर सकते थे, लेकिन निंदा भी नहीं कर सके। फिर आपने फैसला यह किया कि हिंदी में लिख दो निंदा और अंग्रेजी में हल्का शब्द, डिप्लोमैट लिख दिया। आपकी हिम्मत नहीं हो सकी कि निंदा कहें। ...(व्यवधान) सुषमा जी हैं नहीं, अब क्या कहें। ...(व्यवधान) शब्द का इंटरप्रिटेशन किया गया। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : हर एक का उठकर बोलना आवश्यक नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव : यह ठीक है कि विदेश नीति में राष्ट्रहित सर्वोपरि है, लेकिन गलतियां हुयी हैं। हम उन गलतियों के बारे में जरूर कहेंगे कि ये बार-बार न हों। बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। उस गलती को, कुछ भी हो, कैसे भी हो, ताशकंद में, उसे बरदाश्त नहीं कर सकते। हम अपने इतने महान प्रधानमंत्री को खो बैठे हैं। किन परिस्थितियों में क्या बीमारी की वजह से, क्या झटका लगा, क्या आशंका हुयी, क्या देश से जो खबरें गयी, वह गलत को बरदाश्त नहीं कर सके या कुदरती गलती हुयी। इसी तरह से पाकिस्तान के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि युद्ध होता है, तो हिंदुस्तान जीतता है और बातचीत होती है, तो उसमें हिंदुस्तान हारता है। यह हम स्वीकार करते हैं, जो अभी बातचीत हुयी, उसमें हम जीते नहीं हैं।

बातचीत में हमें जीतना चाहिए। उस बातचीत में हम नहीं जीते हैं, हम पीछे रह गए। आप पीछे रह गए क्योंकि आप पिछली विदेश यात्रा में कह चुके थे। जी-8 की मीटिंग में दोहा राउंड के 2010 तक पूरा करने का आश्वासन देना हमारी घोषित नीति के खिलाफ है। जो हमारी नीति है, उस नीति के बारे में हम बार-बार दोहराते रहे हैं कि हम गुटनिरपेक्ष नीति से हट रहे हैं। गुटनिरपेक्षता की नीति जो आजादी के बाद तय हुई थी, उसमें बहुत लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी जिसकी नेहरू जी ने अगुवाई की थी और हमारी गुटनिरपेक्ष नीति के चलते दुनिया के तमाम देशों को यह उम्मीद हो चुकी थी जो पिछड़े थे, गरीब थे, छोटे मुल्क थे, कि हिन्दुस्तान गुटनिरपेक्ष की नीति चलाएगा तो उससे हमारी मदद होगी। इस तरह से छोटे और कमजोर देशों में एक सुरक्षा की भावना पैदा हो गई थी। प्रधान मंत्री जी, हमें यह विचार करना पड़ेगा कि अब हम कहां खड़े हैं और हमें कहां जाना था। अभी कहां खड़े हैं और आगे कहां जाना है। इस पर आपको गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। हम यह जरूर जानते थे कि विदेश नीति के मामले में आपको बहुत अनुभव है। आपने विदेश नीति के बारे में कई तरह से काम किया है। आप विदेश मंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत अनुभव है जिस पर हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन उस अनुभव के अनुसार आपकी कहीं न कहीं कमजोरी आई है। आप इस संदेश को पूरे देश की जनता में कैसे ठीक कर पाएंगे, यह देखना आपका काम है। इससे हम भी संतुष्ट नहीं हैं। हम कहना चाहेंगे कि इससे पहले कमलनाथ जी और जेटली जी का स्टैंड फिर भी सही था। यह मानना पड़ेगा माननीय जसवंत सिंह जी, विदेश मंत्री रहे, वह हमारे साथ थे। श्री जेटली और कमलनाथ जी ने जो स्टैंड लिया था, वैसा स्टैंड क्यों नहीं लिया गया, यह विदेश मंत्री जानें कि क्या वजह थी। कमलनाथ जी ने जो अच्छा काम किया था, उस बारे में हम लम्बा भाषण नहीं देना चाहते हैं।...(व्यवधान) मैं दोनों की बात कह रहा हूं कि श्री अरुण जेटली और कमलनाथ जी का स्टैंड अच्छा था। लेकिन आपने भी एक स्टैंड नहीं लेने दिया। ...(व्यवधान) डीएमके के विदेश मंत्री श्री मारन अभी नहीं हैं।

उन्होंने बहुत मजबूत स्टैंड लिया था। फिर पता चला कि आपके यहां से उन्हें टेलीफोन चला गया।... (व्यवधान) माननीय जोशी जी, आप मिनिस्टर थे। मारन साहब ने जो स्टैंड लिया था, वह बहुत अच्छा स्टैंड था। किसानों के लिए, खेती के लिए, पैदावार के लिए लिया था, लेकिन उसके बाद यहां से टेलीफोन चला गया तो उन्हें थोड़ा सा हटना पड़ा। ऐसा नहीं है, गलतियां हो रही हैं, लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं, उनकी गलती भारी है। यह सही है कि विदेश नीति सर्वसम्मति से ही चलती है। देश के हित में चलती है, देश सर्वोपरि है। संबंध सर्वोपरि नहीं हैं, देश हित सर्वोपरि है। अच्छे संबंध चाहे किसी से भी हों, लेकिन जहां तक देश का सवाल है, देश पहले है। सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने जो आया, पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री जरदारी ने कहा। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही नहीं करेगा, अपने यहां चलाए जा रहे आतंकवादी कैम्पों को नहीं तोड़ेगा, तब तक पाकिस्तान से कोई वार्ता नहीं हो सकती, यह आपका स्पष्ट बयान है। फिर पाकिस्तान से बात क्यों हुई? क्या वजह है? यदि आप इसे स्पष्ट करेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अभी जो शर्म अल शेख में गुटनिरपेक्ष देशों की बैठक हुई, उसमें जो साझा बयान जारी किया गया है, उसमें हमारे यहां से दो भूलें हैं। मैं इसे देश के हित में दो भूलें मानता हूँ क्योंकि आतंकवाद को आपकी वार्ता से अलग कर दिया गया। इसका सीधा अर्थ है पाकिस्तान कैसा भी आतंकवाद करता रहे, कोई वार्ता होती ही नहीं है।

आतंकवाद तो पहला मुद्दा था। आतंकवाद से हमारे देश का अपमान हुआ है। मुंबई में आकर पाकिस्तान के आतंकवादी हमला कर जाएं? उनमें से एक आतंकवादी पकड़ा भी गया, उससे तो सारा भेद आपको मिल गया, इससे बड़ा सबूत और क्या मिलेगा आपको, उससे ज्यादा सफाई और कौन देगा। जब एक आतंकवादी पकड़ा गया है, तो सारी जानकारी आपको मिल गयी होगी। अगर पता चल गया है, तो इस सदन को बताना चाहिए कि आपने क्या-क्या किया? कहां पर उसकी योजना बनी थी? कौन से षडयंत्रकारी थे? कहां-कहां और वे हमले करना चाहते हैं? हिन्दुस्तान का और क्या नुकसान करना चाहते हैं वे आतंकवादी? पार्लियामेंट पर हमला हो चुका है, अब और वे आतंकवादी कहां हमला करना चाहते हैं? लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आ रहा है। हम लोग जितने भी समाजवादी हैं, वे सभी पड़ोसी देशों एवं अन्य देशों से दोस्ती चाहते हैं, दोस्ती होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि आपके दोस्त ज्यादा से ज्यादा हों, विरोधी कम से कम हों, वही सफल राजनीति और सफल विदेशनीति होती है। दोस्त कितने बने? मैंने उस दिन भी कहा था, दोस्ती अलग है और सम्बन्ध अलग बात है। इस बात का आप ध्यान रखना। अभी आपके पड़ोसी देशों में दोस्त कौन है? आप बताएं कि पड़ोसी देशों में कौन-कौन हमारे दोस्त हैं, पाकिस्तान तो होने का सवाल नहीं है, चीन आपका दोस्त नहीं है, और तो और हमारा आश्रित देश नेपाल भी नहीं है। अभी मैं चार दिनों के लिए नेपाल गया था, नेपाल की पूरी जनता आपके साथ है, लेकिन वह भी आपका दोस्त नहीं बन पा रहा है। श्रीलंका बुरे दिनों में हमारे साथ रहा, वर्ष 1962 की लड़ाई में अगर कोई देश हमारे

साथ खड़ा हुआ था, तो वह श्रीलंका था। क्या आज श्रीलंका आपका दोस्त है? दोस्त नहीं है, सम्बन्ध अच्छे हो सकते हैं। दोस्ती और अच्छे सम्बन्ध में भेद समझ लेना। आज आपका दुनिया में जो कोई भी दोस्त हो, उसका नाम प्रधानमंत्री जी या विदेशमंत्री जरूर यहां बताएं, जिससे देश की जनता और हम लोग समझ सकें। हमें भी राजनीति करनी है, बोलना है, कहीं जाना है, हमारी पार्टियों से सवाल पूछे जाते हैं, हम भी तो जवाब दे सकें कि फलां देश हिन्दुस्तान के दोस्त हैं। आज हम कहां पहुंच गए हैं, आज हिन्दुस्तान का कोई दोस्त है ही नहीं। सम्बन्ध अच्छे कितने रह सकते हैं, कब तक रह सकते हैं, वह अलग बात है, लेकिन दोस्त कोई नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि विदेशनीति को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाइए। अगर दोस्त हिन्दुस्तान अब नहीं बना पाएगा तो कब बना पाएगा। इन्दिरा जी के वक्त अपना जहाजी बेड़ा भेजकर अमेरिका ने धमकी दी थी, लेकिन इन्दिरा जी धमकी के आगे नहीं झुकी थीं। उन्होंने मना कर दिया था, तब तो हिन्दुस्तान इतना मजबूत भी नहीं था। आज हिन्दुस्तान इतना मजबूत है, हर तरह से मजबूत है, उस समय से, वर्ष 1970-71 से ज्यादा मजबूत है, कई गुना मजबूत है, तो आज हिम्मत क्यों नहीं है? माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर देश का सम्मान और स्वाभिमान बचाना है, मजबूत करना है तो इच्छाशक्ति, संकल्पशक्ति और साहस, ये तीन चीजें होना अनिवार्य हैं। लेकिन आज इनमें से एक भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है। संकल्प था, अब वह भी हट गया। इच्छाशक्ति भी दिखाई नहीं दे रही है और साहस दिखाई नहीं दे रहा है। पाकिस्तान का इतना साहस कि वह हमें परेशान कर दे। हम पाकिस्तान से दोस्ती चाहते हैं, हम यह मानकर चलते हैं कि हमारा छोटा भाई है, लेकिन पाकिस्तान की इतना हिम्मत होती है। हम उससे कितने गुना ज्यादा हैं, बड़े हैं, हमारी फौज भी ज्यादा है, टेरिटरी भी ज्यादा और उससे हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, फिर भी वहां से आतंकवादी आकर मुंबई पर हमला कर दें? आपकी पार्लियामेंट पर हमला कर दें, जहां चाहे वहां हमला कर दें? इतनी हिम्मत हो गयी है उनकी? इसकी वजह क्या है? कारगिल पर कब्जा कर लें, एक साल पहले जाकर वहां बैठ जाएं, पूरा खाने-पीने का इंतजाम कर ले, तो उनको आपका डर क्यों नहीं है? हमला करने में, आपसे दुश्मनी करने में, शत्रुता करने में पड़ोसी देशों की हिम्मत क्यों हो रही है? वे क्यों नहीं डरते हैं? इसके लिए मैंने बता दिया है, तीन चीजें चाहिए - संकल्पशक्ति, इच्छाशक्ति और साहस। इन पर आपको विचार करना होगा। यही देश के हित में है।

जहां तक हस्ताक्षर का सवाल है, यह सही है कि सारी दुनिया में इस चर्चा से पाकिस्तान को लाभ हुआ है, हिंदुस्तान को नुकसान हुआ है। अगर आप विपक्ष को विश्वास में नहीं लेंगे तो क्या होगा? जब पाकिस्तान से टूटकर बंगलादेश बना, तब दुनिया में हिंदुस्तान का पक्ष रखने के लिए किसको भेजा गया था? उस समय जयप्रकाश जी को विश्व में हिंदुस्तान का पक्ष रखने के लिए भेजा गया था कि इतने लोग बंगला देश से आ रहे हैं, शरणार्थी आ रहे हैं। उनके लिए हम कहां से खाना दें, उन्हें कहां ठहराएं? उस समय पूरी



दुनिया में जयप्रकाश जी ने हिंदुस्तान का पक्ष रखा था। हमारे जयप्रकाश जी से उस समय बहुत मतभेद थे। उस समय हमें बहुत परेशान किया गया था और इमरजेंसी भी लागू की गयी थी। सब कुछ इंदिरा जी ने किया था लेकिन एक मामले में मैं इंदिरा जी की तारीफ करता हूँ, उन्हें याद करता हूँ कि इस मामले में इंदिरा जी ने जयप्रकाश जी को विश्व में भेजा था। इस मामले में इंदिरा जी का कोई जवाब नहीं था। जयप्रकाश जी ने सारी दुनिया में हमारे पक्ष में वातावरण बनाया और तब इंदिरा जी ने पाकिस्तान पर हमला किया था। तब पाकिस्तान से टूटकर बंगला देश बना। पाकिस्तान टूटा तो क्या पाकिस्तान उस बात को भूल जाएगा? आपने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिये थे, उस बात को पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकता है। अगर आप उसके दोस्त बन जाते हैं तो हम तुरंत आपको माला पहना देंगे। यह सही है, यह देश का सवाल है। राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन राजनीति में नाम किसका रहेगा, जो बड़ा काम करके जाएगा, चमत्कारी काम करके जाएगा। आप कहते हैं कि हमने समर्थन दिया, तो समर्थन तो हमने आपकी वजह से दिया। बार-बार हमसे आप लड़ रहे थे। अभी माननीय बहनजी मुझसे बहुत लड़ गयीं कि आपने समर्थन दे दिया। मैंने कहा कि आप सरकार गिराओगे तो सरकार को समर्थन अब भी दे देंगे, सरकार गिरने नहीं देंगे। लेकिन अपनी नीतियों और सिद्धांतों से मैंने कोई समझौता नहीं किया है। अगर आप नीतियां बदल देते, तो स्थितियां ऐसी नहीं होतीं। अभी आपके अध्यक्ष जी को सुना तो वही मंदिर-मस्जिद की बात, कहां भूख है, कहां रोजगार है, कहां खेती है, कहां किसान है, क्या व्यापार धंधा है, क्या रणनीति हो रही है, क्या विदेश नीति की चर्चा हो रही है, हिंदुस्तान कहां है लेकिन आपको मंदिर-मस्जिद अभी तक दिखाई देता है। मंदिर-मस्जिद को अब कौन पूछता है? मंदिर-मस्जिद पर हमारा-आपका झगड़ा थोड़े ही हुआ था, हम तो तमाशबीन थे। यहां सब तमाशबीन बैठे थे, इस बात को याद रखना, लड़ तो हम और जोशी जी रहे थे।

16.27 hrs.

(Madam Speaker in the Chair)

उन दिनों को हम जानते हैं। उन दिनों को हम इसलिए याद कर रहे हैं कि 11 दिन मुझे एक घंटा भी सोने नहीं दिया गया, तब हम मस्जिद की हिफाजत कर पाये थे। लेकिन आप मंदिर-मस्जिद से हट ही नहीं रहे हैं। यहां पर इच्छा-शक्ति, संकल्प-शक्ति है ही नहीं।

हमारी सेना मजबूत, हमारी खेती मजबूत, हमारा सब कुछ मजबूत है। मैं पंजाब के लोगों की सराहना करता हूँ, आज पंजाब सीमा पर अच्छा रोल अदा कर रहा है। आज वहां किसी प्रकार की अशांति नहीं है। कुछ और प्रदेशों में जैसे सीमा पर नफरत फैल रही है या अशांति है लेकिन पंजाब की सीमा पर आज शांति है। यह देश के लिए और हमारे लिए शुभ है। जब भी देश पर कोई कठिनाई या हमला होता है तो सबसे पहले

उसका दंश पंजाब झेलता है। लेकिन आज पंजाब शांत है और यह हमारे लिए अच्छी बात है। मैं कुछ उन सूबों का नाम लेना नहीं चाहता हूं बुरा मान जाएंगे, वहां दूरियां आपस में हैं। ... (व्यवधान)

कुछ ऐसी बातें थी जो मैं कहना चाहता था और वे मैंने कह दी हैं। माननीय यशवंत सिन्हा जी ने जो बातें कह दी हैं, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी, आप बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, यह मैं पहले ही कह चुका हूं लेकिन बेपरवाह मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपका दबाव में कोई कुछ नहीं कर पाएगा, जनता साथ है, सेना पूरी मजबूत है, किसी की हिम्मत नहीं है, आप जो हस्ताक्षर कर आये हो, उन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक दीजिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): महोदया, 26/11 मुम्बई का जो हमला था, उस हमले के बाद एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से अपने-अपने वक्तव्य दिए गए, चाहे वह गृह मंत्री हो, चाहे वह फौज के मंत्री हो, चाहे विदेश मंत्री हो। जितने बयान इस तरफ से दिए गए, उतने ही बयान पाकिस्तान की तरफ से भी दिए गए। इस बारे में प्रधानमंत्री जी के बयान भी शामिल हैं। सारी परिस्थिति को देख कर हमने अपनी जगह निश्चित की कि हम वार्ता नहीं करेंगे, जब तक कि क्रास बार्डर टेरेरिज्म समाप्त न हो जाए। यह हमने तय नहीं किया था, आपकी तरफ से आपके मंत्रियों ने तय किया था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 62 वर्ष हो गए हैं, यह सिलसिला जारी है और मैं नहीं मानता हूँ कि यह सरकारों के हाथ की चीज है। इतिहास ने जिस तरह से देश के हिस्से किए, महात्मा जी को छोड़कर, इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, हम इस तरह खड़े हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ युद्ध कीजिए। वे हालात पहले आपके हाथ में थे, लेकिन अब नहीं हैं। जो परम्परागत फौज थी, उसकी लड़ाई से हम लोग जीतते थे, वह हालत आज नहीं है। 26/11 पर इतनी तरह के बयान दिए गए, वे किसी एक व्यक्ति ने नहीं दिए। आपकी सरकार की तरफ से आपके अधिकारियों ने दिए, प्रधानमंत्री जी ने भी दिए। गिलानी साहब का और प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य है, उसमें आतंकवाद और वार्ता, दोनों साथ-साथ चल सकते हैं, आपने यह तय कर लिया। आपने माना और उन्होंने माना, सवाल यह नहीं है। आप देश में उन्माद खड़ा करते हैं, मैं कभी-कभी कहता हूँ कि उन्माद हो और सोचा-समझा एक आंदोलन हो। घटनाएं होती हैं और हम उसके साथ बहते हैं। आज हालत यह है कि आपका जो वक्तव्य है, वह संयुक्त है। न्यूक्लियर डील बहुत दूर की बात नहीं है, बहुत विस्तार से न्यूक्लियर डील के बारे में बताया गया, मैं उस पर अपने विचार नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे बोलने का समय कम है। उस पर केवल सरकार के बयान नहीं थे, वामपंथियों को छोड़ कर बाकी सब लोगों के थे और अंत में तो मुलायम सिंह जी ने न्यूक्लियर डील के खिलाफ लखनऊ में सम्मेलन किया था तथा बाद में उस पर समर्थन भी हो गया।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : हम सोमवार को जवाब दे देंगे।

अध्यक्ष महोदया : आप कृपया आपसी संवाद मत कीजिए।

श्री शरद यादव : बिजली देने का वायदा किया था। आप दोनों के बीच में क्या करार हुआ, वह पता नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो न्यूक्लियर डील थी, उस पर आपकी सरकार के मंत्री से लेकर आपकी पार्टी एकाकार थी।

आपसे ज्यादा आपकी पूरी पार्टी युद्ध में रत थी। कांग्रेस पार्टी की नेता भी उसमें शरीक थी। पूरी मजबूती से आप दोनों जैसे वॉलीवॉल खेलते हैं, बाकायदा आप गोल कर रहे थे। लेकिन इस मामले में मैं नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी और आपके बीच में...(व्यवधान) सुनाई नहीं पड़ रहा है आप क्या कह रहे



हैं।...(व्यवधान) फुटबॉल में गोल होता है।...(व्यवधान) में शब्द बदल गया। मैं कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं हूँ।...(व्यवधान)

हॉकी का गोल होता है तो पार्टी और आपकी सरकार दोनों गोल कर रहे थे और इस बयान के बाद पार्टी के स्पोक्समैन जो हैं, मैं दूरदर्शन देखता हूँ, मैं दूसरे चैनल कम देखता हूँ लेकिन दूरदर्शन पर मैंने देखा कि आपके जितने स्पोक्समैन थे, वे जवाब की जगह बगलें झांक रहे हैं। यानी यह जो फर्क है, यही अन्तर बताता है कि यह जो आपका वक्तव्य आया है, इसमें कहीं न कहीं दुविधा में आप भी हैं। आपको भी कहीं न कहीं लगता है कि जो आपने कदम उठाया है, वह कदम देश के लिए सही नहीं है। जो बलूचिस्तान है, हम लोगों ने बचपन में काबलीवाला किस्सा पढ़ा है, जो बलूचिस्तान है, उसमें सीमान्त गांधी थे। जिस बात को हम अकेला भुगत रहे हैं, महात्मा गांधी जी के साथ एक आदमी था- सीमान्त गांधी, अब्दुल गफ्फार खां। मैंने जब होश संभाला, मैं जब यूनिवर्सिटी का प्रेसीडेंट था, तो सबसे ज्यादा हिन्दुस्तान में पहली बार कहीं उनका स्वागत हुआ तो वह मेरे विश्वविद्यालय में हुआ था। वह अकेले बलूचिस्तान के ऐसे आदमी थे, हिन्दुस्तान की जो जंग है, आजादी की लड़ाई है, दोनों तरफ के लोग कहते हैं कि इस आजादी को अंजाम देने का काम यदि किसी आदमी ने महात्मा गांधी के बाद किया तो दो-चार आदमियों में जिनका नाम आता है, उनमें वह नाम सीमान्त गांधी हैं। वह देश के बंटवारे के खिलाफ थे, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान को आप भेड़ियों के सामने डाल रहे हैं।...(व्यवधान) फलूचिस्तान बलूचिस्तान से बिल्कुल लगा हुआ है।...(व्यवधान) उनका असर यहां भी था। आंदोलन में जो लोग थे, वे यहां के ही थे। अगर आप उसकी जॉग्रफी के ऊपर छेड़खानी करेंगे तो मैं अकेले भूगोल भर की बात नहीं कर रहा हूँ। ...(व्यवधान) बलूचिस्तान जो है, अकतूलिस्तान जो है, वह सब मिला हुआ इलाका है और उसके बाद गांधी का असर यहां तक सारे फ्रन्टियर में, सारे नॉर्थ-ईस्ट में था। आपने उसका जिक्र कर दिया। आप कहते हैं, पी.सी.चाक्को बोल रहे थे कि कोई बड़ा भारी मुद्दा नहीं है। आप गजब बात कह रहे हैं। 60 वर्ष में जब उसका जिक्र नहीं है तो अब जो उसका जिक्र हुआ और जो सीधी बात है कि हमारी भावनाओं, यानी इस देश में या फलूचिस्तान से लेकर बलूचिस्तान में चाहे वह पूरा का पूरा अफगान है, हमारे और उनके बीच में एक सहज मानवीय संवेदनाओं का आदान-प्रदान है। बगैर कहे, बगैर बोले, वे महसूस करते हैं कि हम उनके मित्र हैं और हम महसूस करते हैं कि वे हमारे मित्र हैं। इसका जिक्र कभी नहीं होता। हमने इसका जिक्र किया। जिक्र चाहे वह सिर्फ नाम के वास्ते हुआ और इस जिक्र के बाद आपकी सरकार के मुल्हाजिम हैं, यह बात हम नहीं कह रहे हैं, यशवंत सिन्हा नहीं कह रहे हैं, मुलायम सिंह नहीं कह रहे हैं, आपकी सरकार के जो मुल्हाजिम हैं, जो शर्म-अल-शेख में थे, वे कहते हैं कि जो वक्तव्य बना है, उसमें जो ड्राफ्टिंग है, उसमें थोड़ी-बहुत इधर-उधर गड़बड़ हो गई है।

गजब बात है कि भारत सरकार से इसी के लिए तनखाह पा रहे हो, इसी चीज के लिए अफसर हो और जब ड्राफ्टिंग हुई तो हिन्दुस्तान में आकर बोल रहे हो कि यह गलती ड्राफ्टिंग में हो गई, बैड ड्राफ्टिंग है। यह गजब बात है। ... (व्यवधान) विदेश मंत्री हैं, विदेश सचिव हैं। विदेश सचिव यह बात आकर कहे और अभी तक भी कन्टीन्यु करे? या तो आप सही हैं या वे सही हैं। हिन्दुस्तान को जानने का हक है कि बैड ड्राफ्टिंग थी या सही ड्राफ्टिंग थी, सही थी या गलत थी। देश की सरकार की दो जीभ नहीं हो सकती हैं। एक बात मुलाजिम बोले और दूसरी बात देश का प्रधानमंत्री बोले, इस तरह दो जुबान नहीं हो सकती। आप चुप है, आपने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। देश दुविधा में है। देश महसूस करता है कि गड़बड़ हो गई। आप नहीं महसूस कर रहे लेकिन देश महसूस करता है। देश इसलिए महसूस करता है क्योंकि बयान में दो जुबान हैं। मुलायम सिंह जी, दो जुबान का देश जब तक रहेगा तब तक यह किसी से मुकाबला नहीं कर सकता है। हिन्दुस्तान की लाचारी और बेबसी रोज बढ़ेगी। गरीबी और कंगाली का समुद्र खड़ा होगा। लूट यहां से यहां तक होगी जब तक देश मजबूत नहीं होगा, जब तक दो जीभ चलेंगी।... (व्यवधान) आप कह रहे थे राज्य मंत्री बहुत बड़े डिप्लोमेट हैं। अरे भाई, यूएनओ को कौन सुन रहा है? मुझे याद है जब वे हिन्दुस्तान आने वाले थे तब मैं अटल जी की सरकार में मंत्री था। यूएनओ के सैक्रेट्री दक्षिण अफ्रीका, घाना के कोफी अनान यहां आना चाहते थे और यहां की सरकार उदासीन थी। यह बात मुझे कहनी नहीं चाहिए। मैंने यह बात कही कि वे आना चाहते हैं तब यूनाइटेड नेशन खड़ा रहा और इराक, अफगानिस्तान पर हमला हो गया। मंत्री जी यूएनओ में रहे हैं, वहां रहने के बाद यहां हारकर चले आए। मैं नहीं मानता, वे कह रहे हैं कि यह दो मुल्कों के बीच में ट्रीटी नहीं है, करार नहीं है। हां, मैं पाकिस्तान की तरफ से कमजोरी मानता हूं, वहां यह भी पता नहीं चल रहा कि जरदारी साहब मजबूत हैं या गिलानी साहब मजबूत हैं। लेकिन मैं गिलानी साहब की चतुराई को मान गया कि वे शर्म अल-शेख में जाकर आपके साथ एक ऐसा वक्तव्य लेकर बोल गए और पाकिस्तान जाते ही शोर मचा दिया - जीत गए, जीत गए। हमारे यहां यूपीए, कांग्रेस पार्टी है, यहां आप जरूर खड़े हैं लेकिन आप दोनों के बीच बोली और भाषा का कोई तालमेल नहीं है। आपके बीच में कोई एक समबोध नहीं है, समलक्ष्य नहीं है और फिर आप कहते हैं कि कोई गड़बड़ नहीं हुई। जिस तरह से 26-11 को इस तरफ या उस तरफ से जितने बयान आए, गजब हो गया जो मंत्री हैं वे भी बोल रहे हैं, डिफेंस मंत्री हैं, वे भी बोल रहे हैं, विदेश मंत्री भी बोल रहे हैं, ऐसा लगा कि ताल ठोक रहे हैं। आप एक से एक बयान दे रहे हो और फिर जाकर कहते हो कि आतंकवाद और वार्ता में कोई अंतर्विरोध नहीं है। यह गजब बात है। मैं मानता हूं कि अंतर्विरोध है। यदि आपने ताकत के साथ कहा होता कि जब तक आतंकवाद वहां खत्म नहीं होगा तब तक हम किसी कीमत पर नहीं करेंगे। आपने कहने के बाद पलटने का काम किया। 26-11 को ज्यादा वक्त नहीं हुआ, ज्यादा

समय नहीं हुआ, वहां जो स्थिति हुई है, उसमें वार्ता भी चलती रहेगी और आतंकवाद का घालमेल, वहां से यहां चलता रहेगा। इस बारे में यशवंत सिन्हा और बहुत से माननीय सदस्य बोले हैं।...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : 13 दिसंबर, 2001 के बाद बस बंद कर दी, रेल बंद कर दी, हाई कमिश्नर को वापिस बुला लिया लेकिन फिर बात क्यों शुरू कर दी?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शरद यादव जी के अलावा किसी और की बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

...(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : जगदम्बिका पाल जी, मैं आपकी बात समझ गया, आप कह रहे हैं कि संसद पर हमले के बाद हमने बस यात्रा की।...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : आपने हाई कमिश्नर वापस बुला लिया और फिर आपने टॉक शुरू कर दी, उसका क्या कारण था?

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदया, मैं इनकी बात पर ज्यादा बोलना इसलिए नहीं चाहता कि हम यहां बैठे हैं तो आप वहां किसलिए बैठे हैं। आप कब तक इतिहास की चर्चा करके अपने गुनाहों को दबाने का काम करेंगे। ...(व्यवधान) आप गुनाहों को कब तक दबाते रहेंगे? आज हर मंत्री खड़ा होता है...(व्यवधान) मैं आपकी बात समझ गया हूं। अब हर मंत्री खड़ा होता है। पिछली एनडीए की सरकार में क्या हुआ। एनडीए में यह गलती हो गई, एनडीए में वह गलती हो गई। भाई ठीक है, यदि गलती हो गई तो हम यहां बैठे हैं। कोई न कोई गलती हमसे हुई है। हम यहां बैठे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि सदन से चले जाएं। आपका जो कहना है उसका मतलब यह है कि हमने संसद पर हमला होने के बाद बस यात्रा खोली तो वह संदर्भ अलग है। उस पर यदि बहस करना चाहें तो आप ले आइये, हम उस पर जरूर बहस करेंगे। हम यह भी कह रहे हैं कि उसमें यदि कहीं गलती हो गई तो हमारे जैसा आदमी मान जायेगा। सवाल सीधा है, मैं यह कह रहा हूं कि 26/11 के बाद आपने जिस तरह से देश के अंदर वातावरण बनाने का काम किया और फिर उसके बाद आप पूरी तरह से पलटी खाकर रिवर्स गियर में चलाने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इससे देश आहत है।

* Not recorded.

आपसे कोई बताये या न बताये, लेकिन मैं बता रहा हूँ और जो लोग 26/11 के बाद आपकी आरती उतार रहे थे, गीत गा रहे थे, घंटी बजा रहे थे, तबला बजा रहा था, हारमोनियम बजा रहे थे, संगीत की सभा चल रही थी। वह सभा आज बिगड़ी हुई है। कोई कुछ बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई अलग सारंगी बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है। आज सबके स्वर अलग-अलग हैं। पहले एक साथ जो बाजा बज रहा था, वह आज सब अलग-अलग हो गये हैं। सबके स्वर अलग-अलग हो गये हैं। वह वहीं नहीं हुआ, देश में नहीं हुआ, अखबारों में नहीं हुआ, मीडिया में नहीं हुआ, आपकी सरकार में भी स्वर अलग-अलग हैं। पार्टी मौन है, पार्टी बोलती है कि सरकार बोलेगी, ठीक जवाब देगी। परंतु बहुत दिनों के बाद बोले। प्रधानमंत्री जी ने कहा होगा कि यह क्या चल रहा है तो बयानबाजी इतने तक आई है। सीधी बात है, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, मैं एंड यूजर के मामले में नहीं जाता। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान आज कैसी हालत में हैं, मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन आजादी के साथ ही हमने अपने हिस्से कर लिये और हिस्से करके इस देश का 30-40 फीसदी पैसा हम फौज पर खर्च करते हैं और वे भी फौज पर खर्च करते हैं। इसके बाद हम जनता के बीच में संकल्प के साथ अपनी तरफ से कोई स्टैंड लेते हैं, किसी जगह खड़े होने की कोशिश करते हैं, उससे फिर हम हट जाते हैं। हम बाकायदा संकल्प लेते हैं, लेकिन उस संकल्प के कोई मायने नहीं है, क्योंकि उस संकल्प पर हम चलने का काम नहीं कर रहे हैं।

महोदया, मैं निश्चित तौर पर एक निवेदन करना चाहूंगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो हालात हैं, उन्हें बनाने में कोई सरकार नहीं बदली है। पहले भी आपकी सरकार थी और अब फिर आपकी सरकार है। जब हालात बदले नहीं है तो मुम्बई पर जो हमला हुआ था, सरकार के जरिये उसके ऊपर आपने पूरे देश भर को साथ में लिया था। उस समय जब मुम्बई में मोमबत्ती जला रहे थे, मेरा बस चलता, कोई मेरी बात को लिख रहा होता तो वह कह रहे थे कि चलो मुख्यमंत्री से दो मिनट में इस्तीफा ले लेते हैं। मेरे ख्याल से वे लोग कभी वोट डालने भी नहीं जाते, वे सब लोग वहां इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने वाले लोगों के साथ आपने स्वर में स्वर मिलाया। आपने सोचकर, सब तरह से विचार करके स्थिति को देखा। आप कहते हो कि वार्ता के बगैर काम नहीं चलेगा। यदि आपकी यह बात सही है तो फिर 26/11 के बाद आपने पूरे देश में जो हालात बनाये थे, हम तब भी उसके विरोध में थे और आज भी विरोध में हैं। आप ही सरकार में थे, आपकी पार्टी थी, फिर आपने यह उन्माद क्यों खड़ा किया? फिर उन्माद के बाद यह वार्ता क्यों शुरू कर रहे हैं? पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद का हमला जारी है, उसमें कोई कमी नहीं आयी है। मैं प्रधानमंत्री जी से देश की विदेश नीति को ताकतवर और मजबूत बनाने के लिये निवेदन कर रहा हूँ। नेपाल के संबंधों को लेकर मैं प्रधानमंत्री जी से दो बार मिला हूँ। हम दुनिया के देशों में ज्यादा कहीं गये नहीं हैं। मैं अकेला आदमी 35



वर्षों से यहां हूं। मैं विदेश इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि हमारा देश दिक्कत में है, हमें बाहर जाने की फुरसत ही नहीं मिलती है। यहां के गरीब और लाचार लोग ज्यादा सोये हुये हैं, तकलीफ और दिक्कत में हैं। मैं कहीं नहीं गया। मैं इतना जरूर जानता हूं कि उस देश की विदेश नीति तभी ठीक होती है ...(व्यवधान)
लाल सिंह जी, आप पीछे बैठकर क्यों बोलते हैं, आप कहिये, मैं जवाब दूंगा। आप ऐसा मत करें।

अध्यक्ष महोदया : यादव जी, आप चेयर को संबोधित कर के बोलिये।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदया, मैं निवेदन कर रहा हूं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिये। अगर छेड़ना है तो पार्लियामेंट में चलता है। मैं जगदम्बिका पाल जी से भी कह रहा था। क्या कहना चाहते हैं, बोलिये?

अध्यक्ष महोदया : आप शान्त रहें।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, यह ठीक नहीं है। जब पीछे से बोलते हैं तो हाल गूँज जाता है। अगर सभा में ऐसे कोई बोल दे तो गड़बड़ हो जाती है और हम डिरेल हो जाते हैं।

अध्यक्ष महोदया, मैं निवेदन कर रहा था कि इस देश में विदेश नीति 62 साल से आम सहमति के साथ चलती रही है। हो सकता है कि हम बातचीत करने में, चर्चा करने में आपसे असहमत हों, या सहमत हों। आप सब काम करके फिर सदन में आते हैं। पिछले 15-20 साल से दुनिया का बाजार खुला है। दुनिया बदली है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इतने ताकतवर हैं। जिस देश की जनता मजबूत होती है, वह देश मजबूत होता है। चीन का आदमी कहीं चला जाये, उसकी विदेश नीति मजबूत है। उनके यहां ऐसी गरीबी नहीं है जैसी यहां लूट मची हुई है। वहां और यहां की गरीबी में फर्क है। सीधी बात यह है कि विदेश नीति में सहमति है। अगर आप चाहते तो विरोधी दल के नेता श्री आडवाणी जी को बुलाकर बात करते, क्या आपने बातचीत की ? कांग्रेस को तो नया जनादेश मिला है, आपका हौसला बढ़ना चाहिये था, मन और दिल बड़ा होना चाहिये था। विदेश नीति आम सहमति से होती है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि मुम्बई में हमले के बाद देश में एक आम सहमति बनी थी कि देश में हमले के बाद पाकिस्तान से तब तक वार्ता नहीं की जायेगी जब तक देश से आतंकवाद खत्म नहीं होता। आपने पहले या अब कहा होता तो ठीक होता। इसलिए मेरी विनती है कि विदेश नीति आम सहमति से होनी चाहिये, इसमें चाहे आपका प्रधानमंत्री हो या हमारी पार्टी का हो। हमारी सरकार भी 10-11 महीने नहीं, उसके बाद पांच साल रही। कांग्रेस की सरकार ज्यादा लम्बे समय तक चली है। विदेश नीति बनाने में कांग्रेस का ज्यादा योगदान रहा है। जो आम सहमति थी, वह अब खंडित हो रही है। वह आम सहमति अब बहस में आ रही है। आज चाहे यशवंत सिन्हा हों या मुलायम सिंह जी हों, चाहे मैं हूं, हम निश्चित तौर पर यही आपसे कहना चाहते हैं कि आम सहमति का रास्ता आम सहमति की परम्परा

है, वह खंडित हो रही है। अगर विदेश नीति खंडित होगी तो चाहे आपका पक्ष हो या हमारा पक्ष हो, तकलीफ होती है।

तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि हम कई तरह कि दिक्कत और हालात में फंसे हैं। मुलायम सिंह जी ने ठीक बात कही कि हमारे चारों तरफ जो देश हैं, उनके साथ हमारा रिश्ता यारी का नहीं है। रिश्ता तो है, लेकिन वह यारी का नहीं है, दिलों का नहीं है और दिलों के मेल के बगैर कोई रास्ता नहीं बनता है। निश्चित तौर से हम जब से आजाद हुए हैं, पहले हम रूस के बाजू में छिपे हुए थे। मैं यह नहीं कहता हूँ कि आप अमेरिका से दोस्ती मत कीजिए, दोस्ती हो, लेकिन इस दोस्ती में ख्याल रखा जा कि हमारे राष्ट्रीय हित कहीं उनके दबाव में खूंटी पर न टंग जाएं। हम यह देख सकते हैं, हम यह कर सकते हैं, हमारे देश का जो पुरुषार्थ है, हमारे देश की जो इतनी बड़ी आबादी है उसके मुकाबले हम उतनी बुरी हालत में नहीं है, उतने पीछे नहीं हैं। चीन हमसे सात, आठ गुणा आगे चला गया है, लेकिन हमारी हालत भी ऐसी नहीं है। आप यदि ठीक से संकल्प के साथ कोई रास्ता पकड़ेंगे तो हम आपसे अलग नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन इस बयान पर महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं सरकार के साथ सहमत नहीं हूँ। मैं वार्ता के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ऐसी वार्ता कि हम लगातार आतंकवाद के शिकार होते रहें, हमारे बेबस और लाचार लोग यहां से वहां तक मरते रहें। मैं इसके बारे में एक बात कहूंगा कि पूरी दुनिया में एक वातावरण बना था, सारी दुनिया मुंबई हमले को महसूस करती थी और उससे पूरी दुनिया मर्माहत हुई थी। उस मर्माहत को आपने थोड़ी दूर तक ले जाने का काम भी किया था, लेकिन शर्म-अल-शेख में जो आपका संयुक्त वक्तव्य है, उसने उस धारणा को चोट पहुंचाने का काम किया है। दुनिया में हमारा जो समर्थन बढ़ा था, वह समर्थन भी आज डावांडोल है। इससे अमेरिका के हित जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान की फौज और उनका जो इलाका है स्वात घाटी, जहां रेडियो मुल्ला रहता है। स्वात घाटी में अमेरिका और पाकिस्तान की फौज दोनों साथ-साथ लड़ रही हैं।

अध्यक्ष महोदया : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री शरद यादव : वे तो उनके हितों को देखकर ही बात करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अमेरिका अपने हितों के अनुसार, हमारे हितों के अनुसार नहीं, अपने हितों के अनुसार बहुत से काम करता रहेगा। मैं यह महसूस करता हूँ। अमेरिका के साथ हमारा झुकाव, मैं कई बातों को देखकर कहता हूँ कि यहां बुश साहब आये थे तो जो बम सूंघने वाले कुत्ते होते हैं, वे महात्मा गांधी जी की समाधि पर चले गये थे।

अध्यक्ष महोदया : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री शरद यादव : महोदया, यह सीधी बात है कि हमें महसूस होता है कि इसमें अमेरिका अपने हितों के लिए हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है। जो आम सहमति से जो विदेश नीति चली है, जिस आम सहमति से हमने 62 वर्ष इस देश को चलाया है, इस मामले में राज और सरकार और ट्रेजरी बैंक और अपोजिशन का कोई मामला नहीं है। आप इस आम सहमति को फिर से कायम कीजिए और यह वक्तव्य देश को ठीक तरह से आगे लेकर कीजिए। हम ऐसा महसूस करते हैं कि वह काम अधूरा है, इसलिए आम सहमति खंडित हुई है, विखंडित हुई है।

THE PRIME MINISTER (DR. MANMOHAN SINGH): Madam, Speaker, I am very grateful to Shri Yashwant Sinha, Shri Mulayam Singhji, Shri Sharad Yadavji for their comments on the Joint Statement that was issued after Sharm-el-Sheikh and also for what I said in the G-8 meetings in Italy. I will cover all the points and clarify all the issues.

17.00 hrs.

Madam Speaker, as I have said many times before, we cannot wish away the fact that Pakistan is our neighbour. We should be good neighbours. If we live in peace, as good neighbours do, both of us can focus our energies on many problems that confront our people, our acute poverty which afflicts millions and millions of people in South Asia. If there is cooperation between us, and not conflict, vast opportunities will open up for trade, travel and development that will create prosperity in both countries.

It is, therefore, in our vital interest to make sincere efforts to live in peace with Pakistan. But despite the best of intentions, we cannot move forward if terrorist attacks launched from Pakistani soil continue to kill and injure our citizens, here and abroad. That is the national position and I stand by that.

Madam, I have said time and again and I repeat it right now again. It is impossible for any Government in India to work towards full normalisation of relations with Pakistan unless the Government of Pakistan fulfils, in letter and spirit, its commitment not to allow its territory to be used in any manner for terrorist activities against India.

This was a commitment, as my friend, Shri Yashwant Sinha mentioned, made to my distinguished predecessor, Shri Atal Bihari Vajpayee, and it has been repeated to me in every meeting I have had with the Pakistani leadership. The people of India expect these assurances to be honoured and this Government recognises that as the common national consensus.

Madam, the attack on Mumbai last November outraged our nation and cast a deep shadow over our relation with Pakistan. The reality and the horror of it were brought into Indian homes over three traumatic days that still haunt us. The people of India demand that this must never happen again.

Over the past seven months, we followed a policy, using all effective bilateral and multilateral instruments at our command, to ensure that Pakistan acts, with credibility and sincerity, as we would expect of any civilized nation.

Soon after the attacks, the United Nations Security Council imposed sanctions on Lashkar-e-Toiba and its front organisations, including the Jamaat-ud-Dawa. It also imposed sanctions on four individuals connected with the organisation, including one of the masterminds behind the Mumbai attacks, Zaki-ur-Rehman Lakhvi.

We exercised great restraint under very difficult circumstances but made it clear that Pakistan must act. On 5th January, 2009, we handed over to Pakistan the details of the links to Pakistan that were revealed by our investigators. Some action followed and Pakistan formally responded to us on two occasions regarding the progress of their own investigations in February 2009 and then just two days before my departure for Paris and Sharm-El-Sheikh.

The latest dossier is a 34-page document that gives the details of the planning and sequence of events, details of the investigations carried out by the special Federal Investigation Agency Team of Pakistan, a copy of the FIR lodged, and the details and photographs of the accused in custody and those declared as proclaimed offenders. It provides details of the communication networks used, financing of the operation and seizures made in Pakistan, including maps, life boats, literature on

navigational training, intelligence manuals, back packs, etc. This is Pakistan's dossier supplied to us. It states that the investigation has established beyond doubt that Lashkar-e-tiba activists conspired, financed and executed the attacks. Five of the accused have been arrested, including Zaki-ur- Rehman Lakhvi and Zarar Shah; and thirteen others have been declared proclaimed offenders. A charge sheet has since been filed against them under Pakistan's Anti Terrorism Act, and other relevant laws.

We have been told that the investigations are nearly complete and that a trial will now proceed. We have also been asked for some further information and we will provide this shortly.

This, Madam Speaker, is the first time that Pakistan has ever formally briefed us on the results of the investigation into a terrorist attack in India. It has never happened before. This, I repeat, is the first time. It is also the first time that they have admitted that their nationals and a terrorist organisation based in Pakistan carried out a ghastly terrorist attack in India.

Madam Speaker, the reality is that this is far more than the NDA Government was ever able to extract from Pakistan, despite all their tall talks. This is true of the entire duration of the NDA regime. They were never able to get Pakistan to admit what they have admitted now. So, I say with all respect to Shri Yashwant Sinha, that the UPA Government needs no lessons from the Opposition on how to conduct foreign affairs or secure our nation against terrorist threats.

Madam Speaker, while noting the steps Pakistan has taken, I have to say that, they do not go far enough. We hope that the trial will make quick progress and that exemplary punishment will be meted out to those who committed this horrific crime against humanity. We need evidence that action is being taken to outlaw, disarm, and shut down the terrorist groups and their front organisations that still operate on Pakistani soil and which continue to pose a grave threat to our country.

Madam Speaker, in the final analysis the reality is that despite all the friends that we may have – and we wish to make as many friends, as Shri Mulayam Singh ji

said, as possible – the harsh reality of the modern world power structure is such that when it comes to matters relating to our internal security and defence, we will have to depend on ourselves. Self-help is the best help. There is no substitute to strengthening our defence capabilities, our national security structure and our emergency response mechanism. I wish to assure the House that the Government is giving these matters the highest priority and attention.

Several important steps have been taken to modernise, rationalise and strengthen our defence security and intelligence apparatus. A detailed plan to address internal security challenges is being implemented in a time-bound manner. The Government is maintaining utmost vigilance in the area of internal security. Measures have been taken to ensure enhanced information and intelligence sharing on a real time basis. The policy of zero tolerance towards terrorism, from whatever source it originates, has been put in place.

Madam, in the area of Defence, steps are underway to substantially improve our coastal and maritime security. Large acquisitions of major weapon systems and platforms have been approved for the modernisation of our Army, Navy and Air Force. There has been a special focus to improve the welfare of the Armed Forces personnel. We will spare no effort and no expense to defend our nation against any threat to our sovereignty, unity and integrity. This is the sacred and bounden duty of any Government of this great country.

Madam, Speaker, but we do not dilute our positions or our resolve to defeat terrorism by talking to any country. Other major powers affected by Pakistan based terrorism are also engaging with Pakistan. Unless we talk directly to Pakistan, we will have to rely on third parties to do so. This I submit to this august House that this particular route has very severe limitations as to its effectiveness and for the longer term view of what South Asia should be, the growing involvement of foreign powers in the affairs of South Asia is not something to our liking. I say, therefore, with strength and conviction that dialogue and engagement is the best way forward. This has been the history of our relations with Pakistan over the last decade.

Shri Atal Bihari Vajpayee took a decision of political courage to visit Lahore in 1999. Then came Kargil and the hijacking of an Indian Airlines plane to Kandahar. Yet, he invited General Musharraf to Agra and again tried to make peace. The nation witnessed the terrible attack on Parliament in 2001. There followed an extremely difficult phase in our relationship. The Armed Forces of the two countries stood fully mobilized. But to his great credit, Shri Vajpayee was not deterred, as a statesman should not be. In 2004, he went to Islamabad, where a Joint Statement was issued that set out a vision for a cooperative relationship. I must remind the House that the Opposition Parties supported those bold steps. I for one share Shri Vajpayee's vision and I have also felt his frustration in dealing with Pakistan.

In my meetings with President Zardari in Yekaterinburg and with the Prime Minister Gilani in Sharm-El-Sheikh, I conveyed in the strongest possible terms our concerns and expectations. I conveyed to them the deep anger and hurt of the people of India due to the persistence of terrorist attacks on our people. I told them that the operations of all terrorist groups that threaten India must end permanently. I urged them to make no distinctions between different terrorist organisations. I said that it was not enough to say that Pakistan is itself a victim of terrorism. They must show the same political will and take the same strong and sustained action against terrorist groups operating on their eastern border as they now seem to be taking against the groups on their western border.

Both President Zardari and Prime Minister Gilani assured me that the Pakistan Government was serious and that effective action would be taken against the perpetrators of the Mumbai carnage.

Shri Yashwant Sinha asked me what was the change between my meeting with President Zardari and later my meeting with Prime Minister Gilani. In-between came the dossier which showed progress though not adequate progress of the type that I had already indicated. He asked me: "Will you trust Pakistan?" Let me say that in the affairs of two neighbours, the best approach is, what the late President

Reagan once said: “trust but verify.” We have no other way of moving forward unless we want to go to war.

I was told by both President Zardari and Prime Minister Gilani that Mumbai was the work of non-State actors. I said that this gave little satisfaction to us and that it was the duty of their Government to ensure that such acts were not perpetrated from their territory. I told them that another attack of this kind would put an intolerable strain on our relationship and that they must take all possible measures to prevent a recurrence.

Madam Speaker, after I returned from Sharm-el-Sheikh, I made a Statement in Parliament which clarified and elaborated not just the Joint Statement issued following my meeting with Prime Minister Gilani but also what we discussed.

I wish to reiterate that the President and the Prime Minister of Pakistan know, after our recent meetings, that we can have a meaningful dialogue with Pakistan only if they fulfil their commitment, in letter and spirit, not to allow their territory to be used in any manner for terrorist activities against India. This message was repeated when the Foreign Ministers and the Foreign Secretaries met.

I stand by what I have said in Parliament - that there has been no dilution of our position in this regard.

An interpretation has been sought to be given that the Statement says that we will continue to engage in a composite dialogue whether Pakistan takes action against terrorism or not. This is not correct. The Joint Statement emphasised that action on terrorism cannot be linked to dialogue. Pakistan knows very well that with terrorism being such a mortal and global threat, no civilised country can set terms and conditions for rooting it out. It is an absolute and compelling imperative that cannot be dependent on resumption of the composite dialogue. In the Joint Statement itself, the two sides have agreed to share real-time, credible and actionable information on any future terrorist threats.

Madam Speaker, when I spoke to Prime Minister Gilani about terrorism from Pakistan, he mentioned to me that many Pakistanis thought that India meddled in

Balochistan. I told him that we have no interest whatsoever in destabilising Pakistan nor do we harbour any ill intent towards Pakistan. We believe that a stable, peaceful and prosperous Pakistan living in peace with its neighbours is in India's own interest.



I told him then and I say it here again that we are not afraid of discussing any issue of concern between the two countries. If there are any misgivings, we are willing to discuss them and remove them. I told him that I had been told by the leadership of Pakistan several times that Indian Consulates in Afghanistan were involved in activities against Pakistan. This is totally false. We have had Consulates in Kandahar and Jalalabad for 60 years. Our Consulates perform normal diplomatic functions and are assisting in the reconstruction of Afghanistan where we have a large aid programme that is benefiting the common people of Afghanistan. But we are willing to discuss all these issues because we know that we are doing nothing wrong. I told Prime Minister Gilani that our conduct is an open book. If Pakistan has any evidence – and they have not given me any evidence, no dossier was ever supplied – we are willing to look at it because we have nothing to hide.

Madam Speaker, I sincerely believe that it is as much in Pakistan's interest as it is in ours to strive to make peace. Pakistan must defeat terrorism before being consumed by it. I believe the current leadership there understands that. It may not be very strong, but the impression that I have is that the current leadership understands the need for action. I was told by their parliamentarians who accompanied Prime Minister Gilani that there is now a political consensus in Pakistan against terrorism. That should strengthen the hands of its leadership in taking the hard decisions that will be needed to destroy terrorism and its sponsors in their country.

Madam Speaker, our objective, as I said at the outset, must be a permanent peace with Pakistan where we are bound together by a shared future and a common prosperity. I believe that there is a large constituency for peace in both countries. The majority of people in both countries want an honourable settlement of the problems between us that have festered far too long and want to set aside the

animosities of the past. We know this, but in the past there have been hurdles in a consistent pursuit of this path. As a result, the enemies of peace have flourished. They want to make our alienation permanent, the distance between our two countries an unbridgeable divide. In the interest of our people and in the interest of the prosperity and peace of South Asia, we must not let this happen. This is why I hope and pray that the leadership in Pakistan will have the strength and the courage to defeat those who want to destroy not just peace between India and Pakistan, but the future of South Asia. As I have said before, if they show that strength and that courage, we will meet them more than half the way.

There are uncertainties on the horizon. I cannot predict the future. But, as I said, in dealing with our neighbour, - two nuclear powers – the only way forward is to begin to trust each other despite all that has happened in the past, not trust blindly, but trust and verify. For the present, what is it that we have agreed? People have been saying that we have broken the national consensus. I simply refuse to believe that we have broken any national consensus not to tolerate terrorism and that Pakistan has to act and act effectively on terrorism before there can be a comprehensive dialogue covering all areas of disagreement or concerns of the two countries.

For the present, all that we have agreed is that the two Foreign Secretaries will meet. The two Foreign Secretaries have been meeting even before the Joint Statement. Further, we have agreed that the two Foreign Ministers will meet on the sidelines of the General Assembly. The two Foreign Ministers have been meeting even before the Statement was issued. They met recently in Trieste. I met President Zardari in  Russia. I met Prime Minister Gilani even before this Statement. So, in operational  terms all that we have agreed is that there will be a meeting of Foreign Secretaries, as often as necessary, followed by a meeting of the two Foreign Ministers on the sidelines of the General Assembly.

Does it involve a surrender of any position? Does it involve a weakening of a position? As neighbours, I sincerely believe that it is our obligation to keep channels of communication open, look at what is happening in the world today.

America and Iran were sworn enemies for 30 years. But, now they feel compelled to enter into dialogue. This is happening all over the world and unless we want to go to war with Pakistan, there is no other way but to go step by step; trust but verify is the only possible way of dealing with Pakistan.

Madam, I now come to three other issues which hon. Yashwant Sinha Ji has raised. One relates to the end-use monitoring arrangement we have made with the United States for Defence purchases. All Governments, Madam, including our Government, are particular about end-uses to which exported Defence equipment and technologies are put to and for preventing them from falling into wrong hands.

Since the late 1990s, the Governments of India and the United States have entered into end-use monitoring arrangement for the import of US high-technology Defence equipment and supplies. These were negotiated before this Agreement in each case by successive Governments of India. The Government has only accepted those arrangements which are fully in consonance with our sovereignty and dignity.

What we have now agreed with the United States is a generic formulation which will apply to future such supplies that India chooses to undertake. By agreeing to a generic formulation, we have introduced an element of predictability in what is otherwise an ad-hoc case by case negotiation.

I should add that we need access to all technologies available in the world for the modernisation of our Defence forces. The threats to our country are growing and we need to have the capability to deal with them and to be ahead of them. Our Armed Forces are entitled to the best possible equipment available anywhere in the world. It is also in our interest, therefore, to diversify to the maximum extent possible the sources of our imports of Defence items and equipment.

You have my assurance, Madam, and through you I wish to convey this to this august House that our Government has taken all precautions to ensure an outcome

that guarantees our sovereignty and national interest. Nothing in the text that has been agreed to compromises India's sovereignty. There is no provision – I repeat, there is no provision – for any unilateral action by the United States side with regard to inspection or related matters. India has the sovereign right to jointly decide, including through joint consultations, the verification procedure. Any verification has to follow a request; it has to be on a mutually-acceptable date and at a mutually acceptable venue. There is no provision for on-site inspections or granting of access to any military site or sensitive areas. This is the position with regard to end-use monitoring.

Madam Speaker, Shri Yashwant Sinha brought up the issue of climate change as if we have changed goal-posts. There is nothing of that sort. There was a meeting in Italy along with the G-8 meeting of major economies of the world. India was invited to that meeting where 17 other countries were present. I should, however, mention that the Major Economic Forum Declaration adopted at L'Aquila is not a declaration of Climate Change policy by India, nor is it a bilateral declaration between India and another country or a group of countries. It is a declaration that represents a shared view among 17 developed and developing countries, the latter category including China, South Africa, Brazil, Indonesia, and Mexico. Therefore, the formulations are necessarily generally worded to reflect different approaches and positions of a fairly diverse group of countries.

It has been argued in some quarters that the reference in the Declaration to a scientific view that global temperature increase should not exceed two degrees centigrade, represents a significant shift in India's position on climate change, and that it may oblige us to accept emission reduction targets. This is a one-sided and misleading interpretation of the contents of the Declaration.

It is India's view, which has been consistently voiced in all world fora, that global warming is taking place and taking place here and now and that its adverse consequences will impact most heavily on developing countries like India. The reference to a two degree centigrade increase as a threshold reflects a prevalent

scientific opinion internationally and only reinforces what India has been saying about the dangers from global warming. True, this is the first time that India has accepted a reference to two degree centigrade in a document as a possible threshold guiding global action, but this is entirely in line with our stated position on global warming.

Drawing attention to the seriousness of global warming does not automatically translate into a compulsion on the part of India or other developing countries, represented in the Major Economics Forum, to accept emission reduction obligations. I should like to mention in this matter that our position and the Chinese position are nearly identical, and we have been coordinating our position with that country on this important issue.

Quite to the contrary, the greater the threat from global warming, the greater the responsibility of developed countries to take on ambitious emission reduction targets. That is why, 37 developing countries, including India, China, Brazil, South Africa, and Indonesia have tabled a submission at the multilateral negotiations asking the developed countries to accept reduction targets of at least 40 per cent by 2020 with 1990 as the baseline.

Madam, the Major Economies Forum Declaration reaffirms the principles and provisions of the United Nations Framework Convention on Climate Change, in particular, the principle of equity and of common but differentiated responsibilities and respective capabilities.

As is well-known, the United Nations Framework Convention on Climate Change imposes emission reduction targets only on developed countries. Developing countries are committed to sustainable development. The full incremental cost of any mitigation by them must be fully compensated by transfers of financial and technological resources from developed countries. This is fully reflected in the Major Economies Forum Declaration.

Furthermore, at the insistence of India, supported by other developing countries, the Declaration includes an explicit acknowledgement that in undertaking

climate change action, the 'first and overriding priority' of developing countries will be their pursuit of the goals of economic and social development and poverty eradication. This should allay any apprehension that India will be under pressure to undertake commitments that may undermine her economic growth prospects.

Madam, with regard to the G-8 decision on enrichment and re-processing technologies, some Members have raised the issue of the Statement issued by G-8 countries on Non-Proliferation at the L'Aquila Summit in Italy earlier in July, and the reference made to the transfer of enrichment and re-processing items and technology. The concern appears to be as to whether an effort is being made by certain countries to prevent the transfer of enrichment and re-processing items and technology to non-NPT countries, that is, countries like India who have not signed the Non Proliferation Treaty.

Madam Speaker, our Government is fully committed to the achievement of full international civil nuclear cooperation. Consistent with this objective in September last year, India secured a clean, and I repeat we secured a clean exemption from the Nuclear Suppliers Group, one that was India specific. At that time also, there were attempts to make a distinction but we got a clean exemption which means that the Nuclear Suppliers Group consisting of 45 countries has agreed to transfer all technologies which are consistent with their national law.

The 'Statement on Civil Nuclear Cooperation with India' approved by the Nuclear Suppliers Group on September 6, 2008 contains India's reciprocal commitments and actions in exchange for access to international civil nuclear cooperation. It is our expectation that any future decisions of the Nuclear Suppliers Group relating to the transfer of enrichment and re-processing item and technology would take into account the special status accorded to India by the NSG. The NSG has given us this clean exemption knowing full well that India is not a signatory to the NPT.

Prohibition by the NSG of such transfers would require a consensus among all the 46 countries. That does not exist at present. The exemption given to India by

the NSG provides for consultations and we will hence remain engaged with that body so that any decisions take into account the special status accorded to India by the global nuclear community.

As far as G-8 is concerned, the fact is that we have no civil nuclear cooperation agreement with the G-8 Bloc *per se*. We have, however, signed bilateral agreements with France, Russia and the United States.

I said this before and I repeat it. When I read about this G-8 Statement, I raised this matter with the French President. He was gracious enough to tell me that as far as France is concerned, there would be no restriction on the transfer of these technologies. In fact, he volunteered. He said: "If you want me to go public, even I am willing to do that." So, my understanding of this area is that there is no consensus in the Nuclear Suppliers Group to debar India from access to the reprocessing and enrichment technology.


Madam, in the course of discussion, some hon. Members have raised the issue of our accepting pre-conditions for transfer of enrichment and reprocessing items and technology. I wish to, once again, assure Shri Yashwant Sinha that pending global nuclear disarmament, there is no question of India joining the Nuclear Non-Proliferation Treaty as a non-nuclear weapon State.

I would also like to clarify that the transfer of enrichment and reprocessing items and technology has no bearing whatsoever on India's upfront entitlement to reprocess foreign origin spent fuel and the use of such fuel in our own safeguarded facilities.

Finally, Madam, I would like to bring to the attention of this august House that India has full mastery of the entire nuclear fuel cycle, and this includes enrichment and reprocessing technology. We have a well-entrenched E&R infrastructure of our own. Our domestic three-stage nuclear power programme is entirely indigenous and self-sustaining. Our indigenous Fast Breeder Reactor Programme and linked technology put us in the league of those very few nations, which today possess cutting-edge technologies. The transfer of enrichment and

reprocessing items and technology to India as part of full international civil nuclear cooperation, would be an additionality to accelerate our three-stage programme.

Madam, I believe, I have rightly answered all the major points. The hon. External Affairs Minister would sum up the debate. He would deal with other aspects.

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): माननीय प्रधान मंत्री जी, आपने बहुत विस्तृत जवाब दिया, लेकिन आपकी बात में से दो प्रश्न क्लाइमेट चेंज और ईएनआर पर निकलते हैं। आपने बोला है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप जवाब देकर चले जाइये, मैं अपनी बात पांच मिनट में कह दूंगी। क्लाइमेट चेंज पर आपने कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की। यह वही सिद्धांत है कि जो जितना बिगाड़े, वह उतना सुधारे। वह अपनी जिम्मेदारी दूसरे देशों पर न डाले। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत रियो-डी-जेनेरियो में भी आया, जब यूएन फ्रेमवर्क कंवेन्शन आई और उसके बाद क्योटो-प्रोटोकॉल में भी आया। क्योटो-प्रोटोकॉल को आज तक अमरीका ने रेक्टिफाई नहीं किया। लेकिन आपने अभी कहा कि वहां मल्टीलेटरल नेगोशिएशन्स में ब्राजील, साउथ-अफ्रीका-मैक्सिको सब आपके साथ आ रहे थे। मेरा प्रश्न केवल इतना है कि जब मल्टीलेटरल नेगोशिएशन्स में बाकी देशों का साथ हमें मिल रहा था तो भारत ने हेलरी क्लिंटन के आने के समय, बाइलेटरल नेगोशिएशन्स में अपने आपको एंगेज क्यों किया? बाइलेटरल नेगोशिएशन्स में अमरीका का चीफ नेगोशिएटर टॉड स्टर्न जब यहां आया तो भारत के पर्यावरण राज्य मंत्री ने यह कहा कि हम इन शर्तों को नहीं मानते, तो उसने उनकी बात कहने से, इस बात को मानने से इंकार कर दिया कि भारत तो वहां मान चुका। जी-17 के देशों में भारत मान चुका तो आपकी बात मैं यहां स्वीकार नहीं करता। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो मल्टीलेटरल नेगोशिएशन्स चल रही थीं, उनसे अलग एक इतने बड़े विकसित देश के साथ, भारत जैसे विकासशील देश ने अलग से नेगोशिएशन्स करने की बात क्यों की? महोदया, मैंने कहा था कि मेरे दो प्रश्न हैं। पहला - क्लाइमेट चेंज के बारे में और दूसरा - ईएनआर के बारे में। क्लाइमेट चेंज के बारे में मैंने कह दिया है। मेरा दूसरा सवाल ईएनआर के बारे में है, जिसके बारे में यशवंत सिन्हा जी ने थोड़ा-सा जिक्र किया था कि भारत अमरीका परमाणु समझौते के तहत एक स्टेट आफ दि आर्ट रिप्रोसेसिंग फेसिलिटी इस्टेब्लिश करने की बात यहां की है। जब जी-8 ने आप पर बैन लगा दिया, तो एक पुर्जा भी आपको यहां से मिलने वाला नहीं है। फ्यूल का सवाल नहीं है, सवाल टेक्नोलोजी ट्रांसफर का है। जब  भी पुर्जा आपको उसके लिए मिलने वाला नहीं है, तो क्या बहुत बड़ा बोझ भारत ने अपने ऊपर नहीं ले लिया है? मैं ये दो सवाल पूछना चाहती हूँ।

DR. MANMOHAN SINGH: Madam, I would like to say that there are no bilateral negotiations taking place outside the framework of the United Nations Framework Convention. There are discussions. When we have bilateral meetings, there are discussions on many subjects. But these are not negotiations. The negotiating forum is and will be the Framework Convention, the Copenhagen process. That is the correct way of looking at it. Whatever we discuss in the G-8, it is all designed to

explore various options to build the consensus. These are not negotiating forums at all.

Now, with regard to the E&R facilities, the 123 Agreement provides for a dedicated re-processing facility. For that, negotiations have already started. There was a time limit by which those negotiations have to be completed. They are moving in the right direction. So, it is not at all, I think, true to say that this re-processing facility will face any difficulty. First of all, I am not sure that the 45-Member Nuclear Suppliers' Group will endorse what the G-8 decide. Attempts were made in the past also. But I think there are many people who believe that a country like India has to be treated differently and it is a source of strength that this recognition prevented a consensus which would have been injurious to us.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Madam Speaker, the pillar of our foreign policy, which was referred to by Shri Yashwant Sinha, started cracking when BJP was in power. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, please take your seats.

SHRI BASU DEB ACHARIA: Madam, we have seen how a Cabinet Minister was secretly meeting with a junior Minister of United States of America, Mr. Strobe Talbot one day in London, other day in Washington, in New York and then in other places. We have seen also the consensus which we have in regard to our foreign policy, in regard to our signing of CTBT and NPT. There is an attempt to change our foreign policy. We have seen when Iraq was attacked by America, the Government of the day was reluctant to condemn the brutal attack on Iraq.

We had to stall the proceedings of both the Houses for three days. You were in the Rajya Sabha at that point of time. We had to stop the House, disrupt the proceedings of the House for three days, stall the House rather for three or four days and then the Government agreed to bring a soft resolution not “condemn” but “deplore”. We had the apprehension. That was why in the Common Minimum Programme of UPA-I, in the paragraph on foreign policy, it was categorically mentioned that our foreign policy would be an independent foreign policy and our relations with the United States of America will be a friendly relation, but it will not be a strategic relation.

The hon. Prime Minister, after returning from Italy and Egypt, made a statement in this House, the very day he returned from Italy and Egypt, where he said in the last but one paragraph and I quote :

“India seeks cooperative relation with Pakistan and engagement is the only way forward to realize the vision of a stable and prosperous South Asia living in peace and amity.”

I agree with this contention. But, in the preceding paragraph the hon. Prime Minister said :

“The starting point of any meaningful dialogue with Pakistan is a fulfillment of their commitment in letter and spirit, not to allow their territory to be used in any manner for terrorist activities against India.”

Then he said :

“The action on terrorism should not be linked to composite dialogue and, therefore, cannot wait other developments. It was agreed that the two countries will share real-time, credible and actionable information on any future terrorist threats.”

There is a contradiction in the statement itself. We also agree that there is a need for dialogue because there are outstanding issues which are to be resolved. But the action against the terrorists should also be taken and pressure should be put on Pakistan to take action against the terrorists. The perpetrators of crime that was committed on 26th November last year should be brought to justice. But how?

When the hon. Prime Minister said that “the starting point of any meaningful dialogue with Pakistan is a fulfillment of their commitment in letter and spirit, not to allow their territory to be used in any manner for terrorist activity”, and then delinking of action against the terrorists, the action on terrorism not to be linked with composite dialogue, these are contradictory.

This has been done under pressure of the United States of America. Then, Balochistan has also been brought in the agreement, in the Joint Statement. It has also been done under pressure of the USA.

Madam, the Prime Minister, while intervening, has stated that this issue was raised on the floor of this House. When in our House and the other House, we discussed the Indo-US Nuclear Deal, a number of times, we had expressed our apprehension. The Prime Minister a number of times stated, and today also he said, that it marks the end of India’s decades of isolation from nuclear mainstream and technical denial regime. He has said that in this House also, but we have also pointed out a number of times that the waiver is not a clean waiver. It is stated not only in the G-8 meeting now, but earlier also, that the waiver that our Government

claims, is not a clean waiver because we cannot separate Hyde Act and 123 Agreement. When the Prime Minister was speaking today, he has expressed his doubt whether all the 45 NSG countries will agree to that proposal or not. If the position was what the Prime Minister has said today that there is on condition in regard to import of ENR technology, how was this issue raised in the G-8 meeting? If no such condition has been imposed by USA that enrichment technology will not be available to our country even after we sign nuclear agreement, how was this issue raised in G-8 meeting? Not only the USA has categorically stated that although the agreement has been signed, it will be confined only to reactor and nuclear fuel, but the USA will also ask all other NSG countries not to supply this technology to our country. So, there will not be available any enrichment technology to our country.

What will happen to our research and development in the field of nuclear technology? We want to reach to the third phase – from uranium to plutonium to thorium. What is the intention of the USA behind keeping our country dependent for supply of nuclear fuel on other countries?

MADAM SPEAKER: Hon. Members, this discussion will continue tomorrow.



18.00 hrs.

MADAM SPEAKER: Now, matters of urgent public importance under 'Zero Hour'.

Shri R. K. Singh Patel.

... (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Madam Speaker, can I point out one thing? ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please do not disturb. This is the 'Zero Hour'.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri Patel, why do not you start speaking?

... (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, can I point out one thing? Further continuation of this discussion is ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: This will not go on record.

... (*Interruptions*) ... *

श्री आर.के.सिंह पटेल (बांदा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की तरफ दिलाना चाहता हूँ। देश में वर्ष 2001-2002 की जनगणना के अनुसार गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों का सर्वे हुआ था और गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले तमाम लोगों के बीपीएल कार्ड्स बनाये गये थे। आज देश में बीपीएल परिवारों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इसलिए नये सिरे से बीपीएल परिवारों का सर्वे तथा बीपीएल कार्डों का सत्यापन कराकर नये बीपीएल कार्ड्स दिया जाना जरूरी है। क्योंकि बीपीएल कार्डधारकों को केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकारों की तमाम सुविधाओं का लाभ दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदया : आपकी बात आ गई है, अब आप समाप्त करिये।

श्री आर.के.सिंह पटेल : इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में बांदा और चित्रकूट जिलों में बीपीएल परिवारों की संख्या बहुत ज्यादा है और 2001 की जनगणना के अनुसार उनको कार्ड नहीं दिये हैं। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि नये मानक के अनुसार नये सिरे से उन्हें बीपीएल कार्ड्स जारी किये जाएं।

* Not recorded.

SHRI BANSA GOPAL CHOWDHURY (ASANSOL): Madam, this is regarding one Public Sector Undertaking (PSU) of West Bengal named Mining and Allied Machinery Corporation for which the State Government is trying its level-best, and the discussion has been held with the Heavy Industries Department. One year back, there was a discussion between Coal India, Damodar Valley Corporation and Bharat Earth Movers Limited to reopen this closed PSU. This PSU has really given a lot of service for mining activities of our country since 1970s.

At present, the National Thermal Power Corporation (NTPC) and the Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) have started a joint venture company in the name of NTPC-BHEL Power Projects Private Limited (NBPPL) with 50:50 equity contribution.

Madam, my submission to the Union Government is this. This joint venture agreement was signed in January, and the company was registered in April 2008 to manufacture power plant equipment ... (*Interruptions*) The entire property of Mining and Allied Machinery Corporation can be used to open the PSU for this type of green field project. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please conclude. You have made your point.

... (*Interruptions*)

SHRI BANSA GOPAL CHOWDHURY : I want that the Heavy Industries Department should take an initiative for this type of new industries.

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Thank you, Madam. I want to draw the attention of the Government with regard to the drastic fall in prices of arecanut. The farmers of not only Kerala, but also from Karnataka, Goa and some other parts of our country are affected due to this. There are about 3 lakh arecanut farmers, and the total dependents come to about 15 lakh. About four years back, the price of one kilogram of arecanut was Rs. 160. Now, it is reduced to Rs. 40 or Rs. 50. It is also not possible for the farmers to sell their arecanut because nobody is ready to buy it.

It is especially because of the unrestricted imports which the Government has permitted. So, the request of the areca-nut farmers is to give them a special package and they also want the Government to take some steps to restrict the imports. Otherwise, it would be very difficult for the farmers even to repay the loans that they have taken, and we will hear the suicide episodes once again.

DR. G. VIVEKANAND (PEDDAPALLY): This is in respect of the gas being produced in the Krishna-Godavari Basin. Reliance has already started producing; currently, they are producing about 40 million cubic metres per day, and is expected to go up to 80 million cubic metres per day. As the Government has already said in the Supreme Court, gas is a national asset, and many power plants, fertilizer plants, and many other units have come up in Andhra Pradesh, based on this gas. Our request is that the Central Government should direct Reliance to supply gas to Andhra Pradesh first because it is being produced in Andhra Pradesh.

Madam, Andhra Pradesh is already implementing a scheme of giving free power to farmers. So, producing electricity through gas is an important event for Andhra Pradesh. Moreover, Ramagundam Thermal Power Station requires gas. It is a closed public sector undertaking, and it requires gas from the KG Basin. I would request the hon. Petroleum Minister to kindly allocate 20 million cubic metres per day of gas for Andhra units being before supplied to other parts of the country. Thank you.

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। जहां एक ओर सरकार देश की जनता पर अरबों रुपया खर्च कर रही है, विशेषकर बच्चों के स्वास्थ्य पर, वहीं दूसरी ओर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अमानवीयता की हद तक जा रहे हैं। दूध जैसी वस्तु, जिसे हम पौष्टिक मानते हैं, वहां दूध भी नकली बन रहा है। इसको बनाने में यूरिया और अन्य कैमिकल्स का उपयोग हो रहा है। जो दूध नकली नहीं है, वह भी जनता की नजरों में और बच्चों के लिये ज़हर साबित हो रहा है। क्योंकि आक्सीटोसिन नाम के इंजेक्शन का उपयोग जानवरों के लिये किया जा रहा है, तब उनका दूध निकाला जाता है। यह एक ऐसा हॉर्मोन है जिसका अधिक उपयोग मस्तिष्क की ग्रन्थियों पर विपरीत और हानिकारक असर डालता है। घी बनाने में भी हड्डियों का चूरा और जानवरों की खाल और

उसके मांस में से चर्बी निकालकर उसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार फल और सब्जियां भी सुरक्षित नहीं हैं। सब्जियों का आकार बढ़ाने के लिये...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं, वह संक्षेप में बताइये।

श्री राकेश सिंह : अध्यक्ष महोदया, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। मैं यह विषय पिछले 15 दिनों से उठाना चाह रहा था। सब्जियों का आकार बढ़ाने के लिये विभिन्न तरह के इंजैक्शनों का उपयोग हो रहा है। फलों को पकाने और अधिक समय तक बाजार में रखने के लिये अलग अलग तरह के रसायनों का उपयोग हो रहा है। खोया भी नकली आ रहा है। सब से बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, वह यह है कि सिर्फ मुझे नहीं मालूम बल्कि अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से पूरे देश की जनता ने इसे अनेकों बार देखा है। इसके बाद भी केन्द्र की सरकार मौन क्यों है? आखिर तब तक इस महत्वपूर्ण विषय को हम राज्यों पर छोड़ते रहेंगे?

अध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में कोई कड़ा कानून बनायें और विशेष रूप से दूध जैसी वस्तु को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल करें ताकि उसके मूल्य पर भी नियंत्रण हो सके और उसकी गुणवत्ता पर भी हम ध्यान दे सकें।

श्री राधा मोहन सिंह (पूर्वी चम्पारण): अध्यक्ष महोदया, बिहार में बिजली का जो संकट है, मैं उसकी ओर केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। झारखंड राज्य बनने के बाद सारी विद्युत उत्पादन क्षमता झारखंड के पास चली गई जबकि बिहार की आबादी 70 प्रतिशत रही। बरौनी और मुजफ्फरपुर मुख्य ताप बिजली घर बिहार में रह गये जिन में नगण्य बिजली पैदा होती है। इसे राष्ट्रीय सम्पदा मानना चाहिये। जिन राज्यों में राष्ट्रीय औसत से कम बिजली है, केन्द्र से कम से कम राष्ट्रीय औसत के आधार पर बिजली उपलब्ध करायी जानी चाहिये जब तक उनके यहां उत्पादन क्षमता पैदा नहीं हो जाती। बिहार सरकार ने नयी विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिये चार साल पहले कोल लिंकेज और प्रोसैसिंग के लिये पैसा जमा कर दिया है। भारत सरकार ध्यान नहीं दे रही है। बरौनी और मुजफ्फरपुर थर्मल पॉवर स्टेशन के विस्तार की लम्बी अवधि के कोल लिंकेज को दूर करने के लिये कोई प्रयास नहीं किया गया है। बिहार की हालत यह है कि वहां 2500 मेगावाट बिजली की जरूरत है।



महोदया, हमारा 1500 मेगावाट का कोटा निर्धारित है, भीषण सूखे का संकट है और हमें 800-900 मेगावाट बिजली मिल रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि अविलंब बिहार को पर्याप्त बिजली देने का कष्ट करें।

SHRI O.S. MANIAN (MAYILADUTHURAI): Madam Speaker, I wish to bring to the notice of the Government the need to set up a Help Desk at the Chennai International Airport. Everyday, hundreds of men and women from Tamil Nadu and Pondicherry are going to Gulf and other countries for employment. Most of them have just basic education. They know only Tamil. But they are asked to complete the Immigration Forms printed in English. The situation has put the passengers to great difficulty and they have to seek the help of persons who are around. It is said that some people charge them Rs.500 for filling up the forms. This difficulty is also faced by people coming to Chennai from abroad.

A Help Desk with officials knowing Tamil and English may be set up at the Immigration Section of the Airport to help the passengers. I also appeal to the Government to provide Immigration Forms printed in Tamil for the benefit of passengers.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदया, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण और गंभीर विषय की ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूँ उसके आसपास करीब 11 मरुस्थलीय जिले हैं और वहाँ पर नील गाय और हिरण हैं। हालांकि हम उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन किसान यह सोचने लग गये हैं कि हम बच्चों को पालें या इन्हें पालें। मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत मुश्किल से फसल होती है और कभी उसे हिरण खा जाते हैं, कभी नील गाय खा जाती हैं। मैं भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय से अर्ज करना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी 10 या 15 किलोमीटर के बीच में कोई गवर्नमेंट लैंड एवलेबल है, उनमें पॉकेट बनाकर हिरणों की रक्षा के लिए कोई स्कीम बनायें ताकि कंटीले तार या चारदीवारी बनाकर उनकी रक्षा कर सकें। नील गायों के लिए भी चारदीवारी बनाकर घास उगा दें, ताकि वे उसे खा सकें। इससे किसानों के बच्चे भी पल सकेंगे और किसान देश में अन्न का उत्पादन भी कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदया : केंद्र सरकार से आप क्या चाहते हैं?

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मैं केंद्र सरकार से चाहता हूं कि इसके लिए कोई स्कीम बनायें ताकि किसानों की फसलों की रक्षा हो सके और हिरण और नील गाय की भी रक्षा हो सके।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : महोदया, मैं भूतल परिवहन मंत्रालय का ध्यान बिहार के एनएच की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आप भी इधर-उधर जाते होंगे, जब हम बिहार में जाते हैं, तो देखते हैं कि जितने एनएच हैं, उनकी दुर्दशा हो रही है। उसमें गड्ढे हैं, कहां गड्ढा है, कहां सड़क है, सड़क में गड्ढा है या गड्ढा में सड़क है, कुछ पता नहीं चलता है। सड़क में इतने गड्ढे हैं कि उसमें धान की खेती कर लो, पानी लगा है, ऐसी बद्तर हालत है। अन्य राज्यों में जैसे फोर-लेन और सिक्स-लेन कार्यवाही चल रही है, वैसी बिहार में क्यों नहीं करायी जाती? भूतल परिवहन मंत्रालय, एनएच और एनएचआई, सभी बिहार की तरफ से उदासीन हैं। हम लोगों की कमर टूट रही है, हड्डी टूट रही है। क्या केंद्र सरकार को वहां कम सीटें मिली हैं, इसका बदला हमसे क्यों चुकाया जा रहा है, वह क्यों हमारी कमर तुड़वा रही है?

अध्यक्ष महोदया : केंद्र सरकार से आप क्या चाहते हैं, वह संक्षेप में बताइए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : इस ओर केंद्र सरकार का विशेष ध्यान जाना चाहिए। सीवान को छोड़कर, बिहार के सभी जिले, 200 पिछड़े जिलों की सूची में शामिल हैं। उस ओर विशेष ध्यान देकर उन सड़कों की तत्काल मरम्मत करायी जाए और चार-लेन और सिक्स-लेन सड़कों को बनाकर हमें भी अच्छे परिवहन और यातायात की सुविधा दी जाए, धन्यवाद।

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER (PONNANI): Madam, my submission is in respect of more than 40 prisoners who are under imprisonment in Sri Lankan jail. Most of them have completed 16 years in jail. Actually, the charges against them are really flimsy. The imprisonment is there. Life sentence in Sri Lanka means total life, not like ours. They have to be in jail for total life. In three jails, there are more than 40 prisoners. Their conditions are really deplorable. Actually, they are suffering from so many difficulties. They are suffering from illness and things like that. They have made several representations, but unfortunately, nothing has been heard so far. They are all poor prisoners mainly from Kerala and Tamil Nadu. During the trial, they were not even able to argue the case properly because they belong to very poor families.



I request the Government to kindly intervene and take up the matter with the Sri Lankan Government and come forward for the rescue of the ill-fated poor prisoners.

Thank you.

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं एक गंभीर बात पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मेरी कांस्टीट्यूएन्सी कालाहांडी में इस साल 20000 हैक्टेयर ज़मीन में तेल रिवर का पानी आने से वाटरलॉगिंग हो गई जिससे किसानों का नुकसान हुआ है। हर साल इस तरह से पानी आता है और 30000 से 40000 हैक्टेयर ज़मीन को नुकसान होता है। कालाहांडी में नदी किनारे रहने वाले किसानों का दुख कभी खत्म नहीं होता है। एक समय में कालाहांडी में अकाल हुआ करता था। इस ओर अभी तक सरकार का ध्यान नहीं गया। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि एक रिवर एम्बैंकमेंट बनाने की योजना बनी है किसानों को इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए। इसमें 663 करोड़ रुपये खर्च होने का एस्टिमेट है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करूँगा कि सालाना सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था करके रिवर एम्बैंकमेंट बनाए जाएँ ताकि आने वाले दिनों में किसान इस बाढ़ से बच सकें।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): माननीय अध्यक्ष जी, हमारे शिवहर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत रीगा चीनी मिल से बहुत पॉल्यूशन होता है। इस चीनी मिल से चीनी उत्पादन के उपरांत बचे हुए कचरे का फैलाव होता है और वह खुले स्थान में बहता रहता है जिसका विस्तार रीगा से बेलसण्ड तक है। इससे उस इलाके में लंबे समय से काफी प्रदूषण है जिससे मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। क्या इसके लिए चीनी मिल में कोई प्लांट लगाएगी जिससे प्रदूषण रोका जाए। इसका सभी जगह पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसका कोई उपाय किया जाए।

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHICODE): Thank you, Madam Speaker, for giving me this opportunity to bring to the attention of the House a serious health problem prevailing in my Constituency Kozhikkode. There is a major outbreak of fever since last month, and daily thousands of people are reaching Government hospitals for treatment. The facilities in the hospitals there are inadequate to handle the sudden influx of patients in such large numbers. Eighty-five per cent of the patients are diagnosed as suffering from Chikungunya, seriously affecting body joints, and patients are made immobile for some weeks. The remaining 15 per cent of the patients suffer from dengue fever, weil's disease and viral fever. In addition to this

grave situation, G-B Syndrome disease is also spreading in this area. A large majority of these are poor people. These people who are affected by the disease have to remain in bed for weeks and in the absence of any income from work, they are in a pitiable situation. These people require free medical help and all financial support till they are cured of the disease.

The outbreak of fever in the form of an epidemic scale, points to the poor sanitary conditions and public health in the area. I would request the hon. Minister of Health of the Government of India to send an expert team to study the problems and start remedial measures to prevent such outbreaks in future.

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से देश का जो एक बहुत बड़ा वर्ग है- नौजवानों का, युवाओं का, छात्रों का - उस वर्ग की एक गंभीर समस्या आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे देश का राष्ट्रीय आंदोलन रहा हो ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : इतने विस्तार में नहीं, संक्षेप में बोलिये।

श्री धर्मेन्द्र यादव : मैडम प्लीज़। हमारे देश का राष्ट्रीय आंदोलन रहा हो या जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन रहा हो, हर आंदोलन में और देश के निर्माण में नौजवानों और छात्रों की विशेष भूमिका रही है। जहाँ देश के अंदर युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की हर स्तर पर चर्चा चल रही है, सत्ता के गलियारों में भी चल रही है, मीडिया में भी चल रही है और हर जगह चल रही है कि छात्रों और नौजवानों को आगे बढ़ाया जाए, वहाँ बड़ी अजीब विडंबना है कि जो केन्द्र सरकार छात्रों और नौजवानों को इतना आगे बढ़ाने का ढिंढोरा पीट रही है, उस केन्द्र सरकार की देख रेख में चलने वाले अधिकांश विश्वविद्यालयों के छात्र संघ आज पूरी तरह से भंग पड़े हुए हैं। जामिया मिलिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बीएचयू हो अथवा देश के किसी भी कोने का विश्वविद्यालय हो, अधिकांश छात्रसंघों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। उससे भी गंभीर विडंबना यह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि वर्ष 2005 में केन्द्रीय विश्वविद्यालय बना था, जब तक वह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार की देखरेख में चला, तब तक वहाँ छात्रसंघों के लगातार चुनाव होते रहे और छात्रों के नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम किया गया। लेकिन जब से वह केन्द्रीय विश्वविद्यालय बना है, तब से वहाँ आज तक एक बार भी चुनाव नहीं हुए हैं। इसलिए हम आपके माध्यम से प्रार्थना करेंगे कि हर तरह की ट्रेनिंग होती है, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, वकीलों की ट्रेनिंग होती है, लेकिन राजनीति की नर्सरी...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं, वह बताइए।

श्री धर्मन्द्र यादव : छात्रसंघों के चुनावों को बहाल करने की कृपा केन्द्र सरकार करे, आपके माध्यम से हम प्रार्थना करना चाहते हैं।

महोदया, नौजवानों को संरक्षण दिया जाए, इसके लिए विशेष रूप से आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामकिशुन (चन्दौली): अध्यक्ष महोदया, लाल बहादुर शास्त्री शताब्दी समारोह के अवसर पर उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार ने शास्त्री जी के पैतृक स्थान राम नगर को गंगा नदी के कटान से बचाने के लिए और वहां पक्का घाट बनाने के लिए एक कार्य योजना बनायी थी। उसके लिए धन भी है। वह डीएम के खाते में है। लेकिन वन विभाग और पर्यावरण विभाग ने उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। उसी के बगल में हमारी पूर्व सरकार ने एक पुल बनाया था, जहां से लाल बहादुर शास्त्री जी गंगा के उस पार जाया करते थे। उनके पैतृक स्थान को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में हमारी पूर्व सरकार, माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार ने घोषित किया था। वन विभाग और पर्यावरण विभाग द्वारा दूसरे कार्यों पर तो अनुमति प्रदान कर दी गयी, लेकिन भारत सरकार के वन और पर्यावरण विभाग ने पूरी तरह से उस कार्य योजना को रोक दिया है, जिसमें गंगा कटान को रोकने के लिए धन दिया गया था और वहां एक सुंदर घाट शास्त्री जी के नाम से बनाने का प्रावधान है।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए। केन्द्र से क्या चाहिए, वह बताइए।

श्री रामकिशुन : महोदया, उस पर करीब चालीस से पचास लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वन विभाग और पर्यावरण विभाग को यह निर्देश जारी किया जाए कि जो उस पर प्रतिबंध लगा है, उस प्रतिबंध को तत्काल समाप्त किया जाए और उस घाट को और गंगा कटान के कार्य को पूरा कराया जाए। यही मेरी केन्द्र सरकार से मांग है। आपने बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet tomorrow at 11 a.m.

18.23 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, July 30, 2009/Sravana 8, 1931(Saka).

